



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय: कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्यूरिफाइड टेरैफथेलिक एसिड के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच

फा.सं. 7/36/2018-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि :

- जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद से इन्हें प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) ने दिनांक 19 जून, 2014 की अधिसूचना सं. 14/7/2013- डीजीएडी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे, जिसमें कोरिया गणराज्य (जिसे इसके बाद से संबद्ध देश के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्यूरिफाइड टेरैफथेलिक एसिड (इसके बाद से इसे पी.टी.ए., संबद्ध वस्तुएं अथवा विचाराधीन उत्पाद के रूप में कहा गया है) के आयातों के खिलाफ अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 36/2014- सीमा शुल्क (ए. डी. डी.) के द्वारा लगाया गया था।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 14/7/2013- डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 27 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 23/2015- सीमा शुल्क (ए. डी. डी.) के तहत निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।
3. और जबकि, मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज और मै० एम. सी. पी. आई. प्रा० लि० (इसके बाद से इन्हें याचिकाकर्ताओं के रूप में कहा गया है) द्वारा अधिनियम और नियमों के अनुसार संयुक्त रूप से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें संबद्ध आयातों के खिलाफ लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने और शुल्कों को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने के लिए मांग की गई थी। इस अनुरोध का आधार यह था कि पाटनरोधी उपायों की समीक्षा होने के कारण संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के क्षति होने की संभावना है।
4. और जबकि, घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों के जारी रखने की समीक्षा करने और यह जांच करने की जरूरत की समीक्षा के लिए दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. फाइल सं. 7/36/2018- डीजीटीआर के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की कि क्या इन शुल्कों को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ख. प्रक्रिया :

5. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-
 - i. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना शुरू करने के संबंध में अधिसूचना की प्रति भेजी थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार प्रकट करने और निर्धारित समय में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
 - ii. निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर देने के लिए संबद्ध देशों से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया था।
 - iii. आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना की प्रति प्रेषित की थी और उन्हें नियमावली के नियम 6 (2) और 6 (4) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया था :-

क. ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

ख. टीकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी, लि०, कोरिया गणराज्य

ग. हानवा जनरल केमिकल कंपनी, लि०, कोरिया गणराज्य

घ. ह्योसुंग पेट्रोकेमिकल, कोरिया गणराज्य

ड. होनाम पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

- च. समनाम पेट्रोकेमिकल कंपनी, लि०, कोरिया गणराज्य
- छ. एस. के. पेट्रोकेमिकल, कोरिया गणराज्य
- ज. लोट्टे केमिकल, कोरिया गणराज्य
- झ. सियाम मिटसुई पी. टी. ए. कंपनी, लि०, थाईलैंड
- ञ. इंडोरामा पेट्रोकेम लि०, थाईलैंड
- ट. टी. पी. टी. पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कंपनी, लि०, थाईलैंड
- v. संबद्ध जांच शुरू किए जाने के उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके और अपने अनुरोध करके उत्तर दिया :-
- क. टीकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लि०, कोरिया गणराज्य
- ख. ह्योसुंग टी. एन. सी. कोरपोरेशन, कोरिया गणराज्य
- ग. हानवा जनरल केमिकल कंपनी, लि०, कोरिया गणराज्य
- घ. इंडोरामा पेट्रोकेम लि०, थाईलैंड
- ङ. टी. पी. टी. पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कंपनी, लि०, थाईलैंड
- vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना भेजने की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्तों को प्रश्नावली भेजी गई थी :-
- क. जे. बी. एफ. इंडस्ट्रीज लि०
- ख. आलोक इंडस्ट्रीज लि०
- ग. भिलोसा इंडस्ट्रीज लि०
- घ. गार्डेन सिल्क मिल्स लि०
- ङ. गोकुलानंद पेट्रोफाइबर्स
- च. डी. एन. एच. स्पिनर्स प्रा० लि०
- छ. फिलाटेक्स इंडिया लि०
- ज. रश्मी पोलीफैब प्रा० लि०
- झ. सुमित इंडस्ट्रीज
- ञ. एस. आर. एफ. लि०
- ट. शुभलक्ष्मी पॉलिस्टर्स लि०
- ठ. वेलनोन पॉलिस्टर लि०
- vii. उपरोक्त के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/ उपभोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया और अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :-

- क. गार्डेन सिल्क मिल्स लि०
- ख. फिलाटेक्स इंडिया लि०
- ग. इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि०
- घ. आई. बी. एल. धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
- ङ. सुमित इंडस्ट्रीज
- च. द बॉम्बे डाइंग एंड मैनुफैक्चरिंग लि०
- viii. इस जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों ने भी अनुरोध दाखिल किए हैं :-
- क. गार्डेन सिल्क मिल्स लि०
- ख. पी. टी. ए. यूजर्स एसोसिएशन
- ग. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री
- घ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन
- ङ. द साउदर्न इंडियन मिल्स एसोसिएशन
- ix. ऐसे निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, अथवा इस जांच के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- x. दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि (जांच की अवधि) के लिए जांच की गई थी। तथापि, वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि के लिए क्षति की जांच की गई थी।
- xi. वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) को भी विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना करने और अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः सहमत लेखांकन सिद्धांतों (जी. ए. ए. पी.) के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उनको बनाने तथा उनकी बिक्री करने की अनुकूलतम लागत निर्धारित की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन से कम मार्जिन पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- III के तहत यथा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार गैर क्षतिकारी कीमत (एन. आई. पी.) का निर्धारण किया गया है।
- xiii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, उन्हें मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोध के साथ दाखिल करने और उसके बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने का अनुरोध किया गया था।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय

आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान कराने का निर्देश दिया गया था।

- xv. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार किया है अथवा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच के अवरोध उत्पन्न किया है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटीकरण में दर्ज किया है।
- xvi. हितबद्ध पक्षकारों को एक प्रकटीकरण विवरण दिनांक 18 जून, 2019 को जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य शामिल थे और प्रकटीकरण विवरण के संबंध में यदि कोई टिप्पणियां हों तो उन्हें प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 25 जून, 2019 तक प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्राप्त प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों को वर्तमान जांच परिणामों में शामिल किया है।
- xvii. *** चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और जिसे प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के तहत गोपनीय माना गया है।
- xviii. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के दौरान प्रचालित औसत विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 65.33 रु. स्वीकार की गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु :

- 6. जांच में और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद प्यूरिफाइड **टेरेफ्थेलिक एसिड** है। मूल जांच में, विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार था :-

"i. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्यूरिफाइड **टेरेफ्थेलिक एसिड** (पी. टी. ए.) है, जिसमें इसके अन्य प्रकार - मीडियम क्वालिटी **टेरेफ्थेलिक एसिड** (एम. टी. ए.) तथा क्वालिफाइड **टेरेफ्थेलिक एसिड** (क्यू. टी. एम.) शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद एक सफेद फ्री फ्लोइंग क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो किसी विजुअल कंटेमिनेशन रहित है। **टेरेफ्थेलिक एसिड** आर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका रासायनिक सूत्र $C_6H_4(COOH)_2$ है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावशाली रहता है और पानी तथा अल्कोहल में मुश्किल से घुलता है। पी. टी. ए. पॉलिस्टर चिप्स के निर्माण में प्राथमिक कच्ची सामग्री होता है, जो टेक्सटाइल्स, पैकेजिंग, फर्निशिंग, उपभोक्ता वस्तुओं, रेसिन तथा कोटिंग आदि अनेक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होती है। चूंकि क्यू. टी. ए., एम. टी. ए. और पी. टी. ए. रासायनिक तौर पर समान उत्पाद हैं और साथ ही इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद में क्यू. टी. ए. और एम. टी. ए., दोनों आते हैं। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष 29173600 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

ii. जैसा कि आवेदकों द्वारा दावा किया गया है, डाई मिथाइल **टेरेफ्थेलिक** (डी. एम. टी.) रासायनिक तौर पर एक अलग उत्पाद है और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है।"

- 7. प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमतों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वस्तुओं के वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है। उपभोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ला रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने उन्हें घरेलू उद्योग से भी खरीदा है। इसे देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान घरेलू वस्तुएं मानी गई थीं।

8. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उपरोक्त को देखते हुए की गई जांच, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना और रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का दायरा वर्तमान जांच में वहीं रहा जो मूल जांच में है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार :

9. यह आवेदन मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज और मै० एम. सी. पी. आई. प्रा० लि० द्वारा दाखिल किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक अर्थात् इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (आई. ओ. सी. एल.) भी है।
10. घरेलू उद्योग की परिभाषा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत प्रदान की गई है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है :

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”

11. याचिकाकर्ताओं के पास भारतीय उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और ये निर्यातकों अथवा उनके आयातकों से संबद्ध नहीं हैं। निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। की गई जांचों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि याचिकाकर्ता नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग में आते हैं।

ड. गोपनीयता :

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध :

12. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- उपभोक्ताओं ने गोपनीयता का दावा करने के लिए कोई कारण प्रदान नहीं किया है।
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना जैसे शेयरहोल्डिंग, वार्षिक रिपोर्ट, उत्पाद विनिर्देशन के लिए भी निर्यातकों और उपभोक्ताओं द्वारा गोपनीयता का दावा किया गया है।
- निर्यातकों ने तो यहां तक कि उत्पादकों तथा निर्यातकों के नाम भी गोपनीय होने का दावा किया है। यद्यपि सच्चाई यह है कि वितरण के चैनल का शुल्क सारणी में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है।
- यहां तक कि उन उत्पादकों और निर्यातकों के नाम भी जिनके माध्यम से वस्तुओं का निर्यात किया गया है, गोपनीय होने का दावा किया गया है, यद्यपि सच्चाई यह है कि ये ब्यौरे अनिवार्य रूप से शुल्क सारणी में दिए गए होते हैं।
- निर्यातकों ने व्यापार सूचना 10/2018 के साथ मिलान नहीं किया है।
- घरेलू उद्योग का गोपनीयता का दावा व्यापार सूचना 10/2018 के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वे घरेलू उद्योग के तर्कों के बारे में जानते थे।

- viii. फार्मेट - क से ठ, जिनमें घरेलू उद्योग की लागत और कीमत संबंधी सूचना शामिल है, उनकी प्रकृति गोपनीयता की है और उनका प्रकटीकरण होने से घरेलू उत्पादकों के प्रतिस्पर्धी हितों के अत्यधिक प्रतिकूल होगा।
- ix. प्रति दिन की उत्पादकता और कर्मचारियों के संबंध में आंकड़े प्रकट नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक कंपनी के संबंध में ये आंकड़े अन्य प्रतिवादी पक्षकारों के संबंध में न केवल गोपनीय होते हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध :

13. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. घरेलू उद्योग ने सभी मात्रात्मक मापदंडों के गोपनीय होने का दावा किया है, जबकि इनके बारे में मूल जांच के जांच परिणामों में प्रकटीकरण किया गया था। किसी भी पक्षकार द्वारा व्यापार सूचना 10/2018 की मूल भावना का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. कैप्टिव खपत की वास्तविक मात्रा प्रकट नहीं की गई है, जिससे कि पक्षकार महत्वपूर्ण मात्रा संबंधी मापदंडों पर टिप्पणी कर सकें।
- iii. घरेलू उद्योग ने निर्धारित फार्मेट के स्थान पर फार्मेट - ज से पूंजी की प्रतिशतता को रखकर नकद लाभ, औसत पूंजी और पी. बी. आई. टी. की पंक्तियों को हटा दिया है। अधूरा फार्मेट - ज पूर्ण और अधिकृत के रूप में प्रमाणित किया गया है जबकि इसमें हेराफेरी की गई है और घरेलू उद्योग द्वारा इसमें बदलाव किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी पक्षकारों के पास वास्तविक अथवा सूचीबद्ध फार्म में शामिल पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में सूचना नहीं है।
- iv. आवेदक के अगोपनीय अंश में गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है। याचिका में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े समुचित रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई गोपनीयता के लिए दिए गए कारकों को स्पष्ट करने वाली सारणी व्यापार सूचना के तहत अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है।
- v. खंड VI के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है, केवल अनुलग्नक 6.1 का हवाला दिया है, जिसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। लागत संबंधी सूचना याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों को समझने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि क्षति के संदर्भ में अनेक तर्क इन दस्तावेजों पर आधारित हैं।
- vi. यूनिट कीमत, कुल लागत, निवेश, रोजगार और स्टॉक के संबंध में सूचीबद्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं और विश्लेषण नहीं किया गया है।
- vii. व्यापार सूचना 10/2018 के तहत कर्मचारियों की संख्या के संबंध में समग्र डाटा और प्रति दिन की उत्पादकता के लिए औसत डाटा प्रकट किए जाने चाहिए थे जबकि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें प्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया है।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों ने कतिपय सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जो नियम 7 में अनुमत है और इसके लिए समुचित कारक प्रदान किए गए हैं।
- ix. घरेलू उद्योग को नियम 7 का अनुपालन करने और आवश्यक विवरण प्रकट करने का निदेश दिया जाना चाहिए ताकि प्रतिवादी पक्षकारों को याचिका पर प्रभावी टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त हो सके।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच :

14. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार हैं :-

“गोपनीय सूचना (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है।

च. विविध अनुरोध :

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध :

16. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- उपभोक्ताओं के उत्तरों को अस्वीकार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता ने संगत सूचना दाखिल नहीं की है और कुछ सबसे महत्वपूर्ण सूचना जैसे आयातों, घरेलू खरीद, विचाराधीन उत्पाद की खपत और लाभप्रता से संबंधित ब्यौरे दाखिल नहीं किए हैं जिससे प्रश्नावली उत्तर एक व्यर्थ की मेहनत हुई है।
- उपभोक्ताओं ने अपने वित्तीय वितरण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिसके कारण उनके उत्तर अधूरे हैं।
- उपभोक्ता इनवॉयस/ बिक्री डिस्काउंट के बाद के ब्यौरे भी प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं, जिससे आयातों के संबंध में प्रदान की गई कीमत की सूचना के सटीक होने पर संदेह होता है।
- उपभोक्ता अन्य दस्तावेज प्रदान करने में भी विफल रहे हैं।
- उपभोक्ताओं ने कठोर, दोष लगाने वाली और आक्रामक भाषा का प्रयोग किया है और अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य न होने के चलते गंभीर दोषारोपण करने का सहारा लिया है।
- उपभोक्ताओं ने इन तथ्यों को छुपाने का प्रयत्न किया है कि (क) उपभोक्ता उद्योग इस पूरे परिदृश्य में अपने निष्पादन में अत्यधिक सुधार कर पाने में सफल रहा है। चाहे यह मात्र अथवा लाभ/ मार्जिन का ही एक प्रश्न है। (ग) पी. टी. ए. खपत में वर्तमान क्षति अवधि के दौरान *** लाख मी. टन तक वृद्धि की है। जबकि यह विगत क्षति अवधि के दौरान *** लाख मी. टन थी (घ) वैश्विक खपत में इस अवधि के दौरान कम अनुपात में वृद्धि हुई है।

- vii. इस संबंध में आरोपों के उत्तर में यह कहना है कि वर्तमान कार्यवाही चूंकि एक पाटनरोधी जांच है न कि प्रतिस्पर्धा कानून के तहत एक जांच है, इसलिए “एकाधिकार की कार्यवाही का आरोप अथवा “एकाधिकार की स्थिति का आरोप” जैसे आरोप लगाने का इस जांच से कोई संबंध नहीं है। ऐसी अनेक जांच होती हैं जिनमें एक या अधिक उत्पादक होते हैं।
- viii. भारत में ही संबद्ध वस्तुओं के ऐसे तीन उत्पादक हैं, जिनमें प्रत्येक अपना संयंत्र शीघ्र स्थापित करना चाहते हैं। अतः बिना आयातों के भी बाजार में कोई एकाधिकार नहीं हो सकता।
- ix. यहां तक कि शुल्कों के साथ भी आयात जारी रह सकते हैं एक अपाटित कीमतों पर और इसीलिए कोई एकाधिकार नहीं है।
- x. प्रतिवादियों के आरोपों के जवाब में यह तर्क दिया गया था कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को आयातों के द्वारा समाप्त किया जा रहा है न कि घरेलू उद्योग द्वारा।
- xi. रिकार्ड में उपलब्ध डाटा से स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने “एकाधिकार का पट्टा”, “सामान्य से अधिक लाभ” अथवा एक “शामिल पूंजी पर अत्यधिक प्रतिफल” अर्जित नहीं किया है, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिए गए हैं। यह बिल्कुल सही है कि कीमतों में कटौती मामूली है जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग आयातों के कीमत रखकर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है।
- xii. यह तथ्य कि प्रयोक्ता उद्योग ने घरेलू उद्योग की बजाय बेहतर प्रतिफल अर्जित किया है, उनके वित्तीय विवरणों से स्पष्ट हो जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग कथित एकाधिकार की स्थिति नहीं रख रहा है।
- xiii. इस तथ्य को छिपाने के लिए प्रयोक्ता उद्योग पर शुल्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रतिवादियों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से सूचना दाखिल करने से इंकार किया है।
- xiv. इस आरोप के प्रत्युत्तर में कि घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग की आवाज को दबा रहा है, यह कहना है कि प्रतिवादियों ने केवल इस कारण से गंभीर आरोपों का सहारा लिया है, क्योंकि उनकी गलतियां सामने आ चुकी हैं।
- xv. प्रयोक्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामले की वास्तविक सच्चाई से दूर करने और घरेलू उद्योग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसी भाषा का सहारा लिया है।
- xvi. प्रयोक्ताओं ने ऐसी सूचना को रोककर रखा है, जो कि उनके ऐसे मिथ्या तर्कों के लिए घातक साबित होती कि उन्हें शुल्क लगाए जाने के कारण से हानि उठानी पड़ी है।
- xvii. इन तर्कों के जवाब में कि प्रयोक्ताओं की एसोसिएशन हितबद्ध पक्षकार की परिभाषा में आती है, यह कहा गया था कि प्रयोक्ताओं के भाग लेने का तरीका नियम 6 (5) में विनिर्दिष्ट है कि (क) औद्योगिक प्रयोक्ता और (ख) प्रयोक्ता एसोसिएशन, लेकिन जब उत्पाद खुदरा स्तर पर बेचा जा रहा हो।
- xviii. जांच में भाग लेने से एसोसिएशन के अधिकार का हनन प्रयोक्ताओं के भाग लेने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है और इसीलिए प्रयोक्ताओं को बिना निवारण किए नहीं छोड़ा गया है जैसा कि प्रयोक्ताओं द्वारा दावा किया गया है।
- xix. यदि “कारोबार पर शुल्कों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव” को मापने का तरीका, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया है, उस पर विचार किया जाए तो “हितबद्ध पक्षकार” शब्द की एक बहुत ही व्यापक व्याख्या हो जाएगी और यह अर्थ हो सकेगा कि यहां तक कि कमीशन एजेंट, कस्टम हाउस एजेंट, शिपिंग लाइन, स्वदेशी ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस इत्यादि, जो आयातित और घरेलू वस्तुओं के वितरण में लगे हुए हैं, वे भी “हितबद्ध पक्षकार” के रूप में माने जाएंगे। इसके अलावा, उस तर्क से तो यहां तक कि पी. ई. टी. रेसिन से

बने बोतल वाले पानी का कोई उपभोक्ता अथवा मानव निर्मित वस्त्र से बने गारमेंट खरीदने वाला उपभोक्ता भी एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जा सकता है।

- xx. इस तर्क के संबंध में कि प्रयोक्ता एसोसिएशन नियम 2 (ग) के तहत परिभाषा में शामिल हैं, यह कहा गया था कि प्रतिवादियों को नियम 2 (ग) के प्रावधानों को इस तरीके से पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि जिससे नियम 6 (5) के प्रावधान ही निरर्थक हो जाएं।
- xxi. यह कानून की व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि कतिपय मामले में कोई विशेष प्रावधान किया जाता है तो वह मामला समानता प्रावधान से बाहर हो जाता है। अतः ऐसे मामले में जिसमें कि प्रयोक्ता भाग ले सकते हैं, नियम 6 (5) के तहत जब एक विशेष प्रावधान कर दिया गया है तो यह मामला नियम 2 (ग) के तहत "हितबद्ध पक्षकार" की व्यापक परिभाषा के तहत कवर नहीं होगा।
- xxii. जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा ऑटोमेटिव टायर इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के मामले में पाया गया है, एक प्रयोक्ता एसोसिएशन को स्वयं को अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करके एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्थापित करना चाहिए, जो कि वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।
- xxiii. यहां तक कि जब यह मान लिया गया है कि नियम 2 (ग) की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, जिसमें ऐसे पक्षकार, जिन्हें नियम 2 (ग) के तहत हितबद्ध पक्षकार के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी से एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माने जाने के लिए छूट लेने की जरूरत होती है।
- xxiv. निचले (डाउनस्ट्रीम) उद्योग को शामिल करने के लिए प्रतिवादी प्रयोक्ताओं की आकांक्षा इस तथ्य को झुठलाना प्रतीत होता है कि चूंकि वर्तमान प्रतिवादियों और पी. टी. ए. उपभोक्ता एसोसिएशनों के सदस्यों को लागू शुल्कों के कारण समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन वे आगे के निचले (डाउनस्ट्रीम) उपभोक्ताओं के लिए इसका सामना करने का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
- xxv. उपभोक्ताओं के डाउनस्ट्रीम उद्योग अथवा उनके संघ एक हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं, क्योंकि उनका शुल्कों को लगाने में कोई असन्न हित नहीं है और उनकी स्थितियों के विश्लेषण के लिए कोई आंकड़े रिकार्ड में नहीं हैं।
- xxvi. कताई आदि से संबंधित डाउनस्ट्रीम उद्योगों के संघों को न केवल हित प्रदर्शित करने की जरूरत होती है, बल्कि उनका हित दूर का अथवा नजरअंदाज करने योग्य नहीं होना चाहिए। इसके बजाय पक्षकार अपने प्रचालनों पर शुल्कों के एक महत्वपूर्ण प्रभाव दर्शाने में समर्थ होना चाहिए।
- xxvii. केवल ऐसी संस्थाओं को परिभाषा में "शामिल" माना जाना चाहिए, जो उसी श्रेणी अथवा प्रकार की होती हैं, जिनकी गणना की गई है। चूंकि वर्तमान परिभाषा विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तुओं के केवल उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों इत्यादि से संबंधित है, एक ऐसी संस्था, जो किसी अन्य वस्तु की एक उपभोक्ता है, उसे हितबद्ध पक्षकार की परिभाषा के दायरे में नहीं माना जा सकता है।
- xxviii. जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा मेरिनो पैनल मामले में पाया गया है यह एक पक्षकार पर निर्भर करता है कि वह स्वयं को संगत सूचना दाखिल करके एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में प्रदर्शित करे। एसोसिएशन द्वारा ऐसी कोई सूचना दाखिल नहीं की गई है।
- xxix. जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकार को अपने निहित हित की प्रकृति को भी प्रदर्शित करना होता है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका हैंडबुक के अनुसार भी, पक्षकारों को जांच में भाग लेने के लिए अपने कारणों के बारे में बताना होता है और सचिव द्वारा किसी व्यक्ति के समुचित कारण पाए जाने पर ही एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- xxx. कम से कम अन्य डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के संघ को उसके भाग लेने के समुचित कारण बताने चाहिए कि उनके आंकड़ों से यह प्रमाणित होना चाहिए कि वास्तव में उन्हें शुल्कों ने प्रभावित किया है।

- xxxi. प्रतिवादियों द्वारा एफ. ए. क्यू. पर निर्भरता गलत थी, क्योंकि यह केवल पाटित उत्पादों के उपभोक्ताओं के संदर्भ में है।
- xxxii. उपभोक्ताओं द्वारा भारत सॉल्वेंट में निर्णय के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया था कि निर्णय से यह स्पष्ट हो गया था कि पक्षकार का हित वास्तविक और उससे संबद्ध होना चाहिए।
- xxxiii. ये एसोसिएशन इस कारण से पात्र नहीं नहीं हैं कि उनके सदस्य प्राथमिक रूप से कपास पर निर्भर हैं न कि मानव निर्मित फाइबर्स पर निर्भर हैं।
- xxxiv. यहां तक कि यदि यह माना जाए कि उपभोक्ताओं का 'डाउनस्ट्रीम उद्योग' प्रभावित हो रहा है, तब उपभोक्ताओं के इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- xxxv. इस तर्क के उत्तर में कि प्रयोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि प्रतिवादी यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि (क) उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा है; और (ख) यह कि शुल्कों को लगाए जाने के कारण हानि हुई है।
- xxxvi. ऐसा लगता है कि प्रतिवादियों का यह मानना है कि उन्हें अनुचित कीमतों पर आयात करने का अधिकार है और सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाकर बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा लाने के लिए किए गए उपायों के कारण उन्हें हानि हुई है।
- xxxvii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह दर्शाया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के तकरीबन सभी उपभोक्ताओं का लाभप्रद कारोबार चल रहा है और वास्तव में इस अवधि के दौरान उनकी लाभप्रदता में और भी तेजी आई है।
- xxxviii. ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए जो नुकसान में हैं, उनकी वार्षिक रिपोर्ट अपने आप यह दर्शाती है कि नुकसान होने का कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के अलावा किसी अन्य कारण से है।
- xxxix. निचले उद्योग (डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री) के ठहराव के दावों का उत्तर देते हुए यह उल्लेख किया गया था कि फिलाटेक्स इंडिया लि०, चिरपाल पॉली फिल्म्स लि०, शुभलक्ष्मी पॉलिस्टर्स लि०, वॉकमेट इंडिया लि०, वेलनॉन पोस्टिर्स लि०, एस. आर. एफ. लि० और भिलोसा इंडस्ट्रीज लि० ने शुल्क लगाए जोन के बाद से विस्तार किया है।
- xl. इसके अलावा, फिलाटेक्स इंडिया लि०, भिलोसा इंडस्ट्रीज लि०, ईस्टर लि० तथा जिंदल पॉलि फिल्म्स लि० आगे अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उपभोक्ता उद्योग ठहराव का सामना नहीं कर रहा है।
- xli. प्रतिवादियों ने स्वयं ही यह माना है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग कई गुणा वृद्धि कर रहा है।
- xlii. प्रयोक्ताओं ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया है कि पी. टी. ए. के डाउनस्ट्रीम उद्योग का मार्जिन बढ़ रहा है।
- xliii. जहां तक कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और गारमेंट उद्योग में लगे अन्य उद्योग का संबंध है, प्रतिवादियों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह दर्शा सके कि इन उद्योगों के उत्पादन की लागत पर शुल्क का प्रभाव है।
- xliv. शुल्कों का प्रभाव तकरीबन 110 रु. प्रति कि. ग्रा. के टेक्सचर्ड यार्न के संबंध में केवल तकरीबन 1.39 रु. प्रति कि. ग्रा. है। इसलिए शुल्कों का प्रभाव एक 250 रुपए की साड़ी में केवल 0.56 रु. है। करीब 146 रु. की शर्ट में करीब 0.31 रूप का शुल्क होगा।
- xlv. वस्त्र उद्योग के विकास की संभावना यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत आत्म निर्भर रहे, घरेलू उद्योग के निरंतर विकास के महत्व को कम आंकता है।

- xlvi. शुल्कों को लगाए जाने से वस्त्र उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता क्योंकि प्रयोक्ता शुल्कों का भुगतान किए बिना निर्यातों के प्रयोजन से अग्रिम लाइसेंस के तहत संबद्ध वस्तुओं का आसानी से आयात कर सकते हैं।
- xlvii. जब प्रयोक्ताओं को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है तो उनके डाउनस्ट्रीम उद्योग को हानि अथवा ठहराव केवल दो बातें दर्शाता है – (क) या तो प्रयोक्ताओं को लाभ हो रहा है और उन्होंने अपने उपभोक्ताओं को कीमतें कम होने के लाभ प्रदान नहीं किए हैं; अथवा (ख) डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को हो रही हानियां लागू शुल्कों के कारण से नहीं हैं।
- xlvi. प्रतिवादियों के तर्कों के विपरीत, पी. सी. आई. वुड मैकेन्जी के द्वारा यह दर्शाते हैं कि पॉलिस्टर की खपत इस अवधि के दौरान बढ़ती रही है, जो डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास को दर्शाता है।
- xlix. चाहे जो भी हो, कताई मिलों को अत्यधिक क्षमता के कारण हानि का सामना करना पड़ा है।
- i. इसकी ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या ये आपत्तियां वास्तव में प्रयोक्ताओं के रूप में प्रतिवादियों द्वारा ही उठाई जा रही हैं अथवा उनके संगत निर्यातकों को शुल्कों से बचाने के लिए मदद करने के लिए हानि होने के मिथ्या दावे तो नहीं किए जा रहे हैं।
 - ii. प्रतिवादी, फिलाटेक्स इंडिया लि० के अध्यक्ष ने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया है कि पी. टी. ए. की घरेलू तौर पर उपलब्धता से प्रयोक्ताओं की संभावनाओं में सुधार हुआ है।
 - iii. इस तर्क के संबंध में कि आर. आई. एल. ने डाउनस्ट्रीम उद्योग में भी लाभ उठाया है, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रयोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्हें हानियों के कारण नुकसान हुआ है।
 - liii. इसके अलावा, जब आर. आई. एल. ने पी. टी. ए. की कैप्टिव खपत का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया है और डाउनस्ट्रीम उत्पादकों ने क्षति का सामना नहीं किया है तो इस तर्क का कोई आधार नहीं बनता कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्कों के कारण से हानि हो रही है।
 - liv. जहां तक प्रतिवादियों के पी. एस. एफ. मामले पर निर्यात का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि इंडो रामा सिंथेटिक्स, जो पहले कम क्षमता के उद्योग के कारण से क्षति का सामना कर रही थी, उसने स्वयं ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वे आज अधिक प्रचालन दरों और लाभ मार्जिन प्राप्त कर रहे हैं। पी. एस. एफ. के अन्य उत्पादकों का निष्पादन में, विशेषकर बॉम्बे डाइंग के संबंध में, काफी सुधार हुआ है।
 - lv. जहां तक पी. एस. एफ. उद्योग के कम क्षमता उपयोग का तर्क है, यह उल्लेख किया गया था कि बॉम्बे डाइंग ने स्वयं ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि उसने 93 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया है और यह कि अन्य उत्पादकों ने 80 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। उस समय भी पी. एस. एफ. उत्पादकों का औसत क्षमता उपयोग आलोक इंडस्ट्रीज के कारण कम था, जो कि वित्तीय समस्याओं के कारण से 30 प्रतिशत पर प्रचालन में है और इंडो रामा सिंथेटिक्स, जो कार्यशील पूंजी की समस्या से काम रही है। इसके अलावा, प्राधिकारी के जांच परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि पी. एस. एफ. उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
 - lvi. जहां तक मांग आपूर्ति के अंतराल में कमी पर निर्भरता का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि यह दर्शाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि मांग आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं हो तब भी आयातों में वृद्धि नहीं होगी।
 - lvii. आयातों को बंद करने संबंधी तर्क के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि जब वर्तमान शुल्कों के कारण आयातों को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है तो इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि शुल्कों के जारी रहने से ऐसा हो जाएगा।

- lviii. जांच की अवधि के उपरांत के आंकड़ों के संबंध में यह कहा गया था कि ऐसे आंकड़े केवल तभी संगत हैं जब (क) पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन जांच की अवधि में नकारात्मक हो, अथवा (ख) जांच की अवधि के बाद शुल्क समाप्त हो गए हों जिनसे कि क्षति की संभावना को दर्शाया जा सके।
- lix. यदि जांच के उपरांत की अवधि के डाटा की मांग की जाए, तो एक वर्ष के लिए शुल्कों का विस्तार करने का अनुरोध किया जाना चाहिए क्योंकि जांच को समाप्त होने में काफी समय लगेगा।
- lx. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आई. ओ. सी. एल. का संयंत्र बंद हो गया था, यह तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग ने तालाबंदी से हुए घाटे को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त मात्रा में आपूर्ति की थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं को हानि नहीं हुई है। इसके अलावा आर. आई. एल. के पटलगंगा स्थित संयंत्र को आपूर्ति करने के लिए 15 दिनों की अवधि के भीतर पुनः शुरू किया जा सकता है।
- lxi. एशियन (एसईएएन) – इंडिया फ्री ट्रेड करार के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया था कि यह अनुच्छेद केवल गैर प्रशुल्क उपायों से संबंधित है।
- lxii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा पेपर बुक परिचालित नहीं की गई थी, इस संबंध में भेजी गई ई-मेल की प्रतियां प्रस्तुत की गई थीं। यह भी कहा गया था कि चूंकि पेपर बुक में उत्तरों के स्तर निहित हैं और घरेलू उद्योग ने उनमें कमियों का उल्लेख करते हुए पहले ही पत्र भेजे थे, प्रतिवादियों को बचाव में पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गए थे।
- lxiii. इस आरोप के उत्तर में कि आवेदन के साथ में पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, रिलायंस पर इस संबंध में जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना में अवलोकन किया गया था।
- lxiv. जहां तक सार्वजनिक हित का संबंध है, यह कहा गया था कि इस पर विचार करने का काम भारत सरकार का है, इस पर टिप्पणियां देने का काम निर्यातकों का नहीं है। शुल्कों के जारी रहने से बाजार में प्रतिभागिता के लिए समान अवसर मिलेगा।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध :

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- i. जांच की अवधि के उपरांत के आंकड़े निर्णायक समीक्षा में संगत हैं जिनसे आयातों में गिरावट दिखाई देगी।
- ii. यह तर्क कि 'प्रयोक्ता एसोसिएशन' को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत है। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रयोक्ता पाटनरोधी जांच में उपचारहीन होते हैं। चाहे पाटनरोधी शुल्कों का किसी पक्षकार के कारोबार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, यह तय करता है कि क्या कोई पक्षकार एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जा सकता है अथवा नहीं।
- iii. नियम 2 (ग) के तहत परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि स्वयं की खपत के लिए आयात करने वाला पक्षकार एक हितबद्ध पक्षकार नहीं हो सकता। पाटनरोधी करार में भी यह दर्शाया गया है कि अन्य पक्षकार जो सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, वे एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में मान जाएं।
- iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व की प्रथा में भी परिभाषा के समावेशी पहलू को अपनाने के बारे में दर्शाया गया है, क्योंकि पी. टी. ए. यूजर्स एसोसिएशन को पूर्व में भी एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है। एसोसिएशन में पी. टी. ए. के प्रयोक्ता शामिल होते हैं और उन पर पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से शुल्कों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

- v. न केवल पी. टी. ए. यूजर्स एसोसिएशन बल्कि पी. टी. ए. यूजर्स द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों से संबंधित प्रयोक्ता और एसोसिएशन को भी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वे पी. टी. ए. पर पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति का सामना करते हैं।
- vi. पी. टी. ए. यूजर्स एसोसिएशन और उसके सदस्य तथा डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की एसोसिएशन स्पष्ट रूप से हितबद्ध पक्षकार है और घरेलू उद्योग द्वारा इसके विपरीत मत रखना यह दर्शाता है कि वे पाटनरोधी शुल्कों के जारी रखने के लिए अपनी अनुरोध के खिलाफ किसी भी आवाज को बंद करना चाहते हैं।
- vii. ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना, जहां पर कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल होने के कारण आयात आवश्यक है, प्रयोक्ता उद्योग को नुकसानों और ठहराव की स्थिति का सामना करने के लिए ऐसा आवश्यक है।
- viii. प्रयोक्ता उद्योग में डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग जैसे पी. एस. एफ., पी. ओ. वाई., डी. टी. वाई, फिल्म, पी. ई. टी. इत्यादि के कई उत्पादक शामिल हैं और ये देश में सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले उद्योग हैं, जिनमें कताई, बुनाई, बिनाई (निटिंग), प्रसंस्करण और गारमेंट उद्योग शामिल हैं।
- ix. घरेलू निर्यातकों ने काफी क्षमता वृद्धि की है और पाटन आपूर्ति की स्थिति में सुधार किया है, जिसमें पाटनरोधी शुल्कों का उनके द्वारा संरक्षण का लाभ उठाया जाना शामिल है, जिसके कारण भारत में आयातों में काफी गिरावट आई है।
- x. घरेलू उत्पादकों को करीब-करीब एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है और वे एकाधिकार का लाभ उठाते हैं और प्रयोक्ताओं के नुकसान के लिए कीमतों में बदलाव करते हैं।
- xi. रिलायंस इंडस्ट्री लि०, जो सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके पास शीर्ष एकीकरण है, वह बाजार में प्रभावशाली स्थिति में है, जबकि प्रयोक्ता उद्योग अत्यधिक विविधिकृत हैं और पी. टी. ए. पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रभावित है।
- xii. पी. टी. ए. के डाउनस्ट्रीम उत्पादक करीब 8080 करोड़ रूपए का बड़ा विदेशी विनिमय अर्जित करते हैं और यदि डाउनस्ट्रीम उत्पादों में गारमेंट तक को शामिल किया जाता है तो उनकी आय करीब 1 ट्रिलियन होगी। यह घटक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और शहरी तथा ग्रामीण रोजगार प्रदाता भी है। ये सभी डाउनस्ट्रीम उत्पादक पाटनरोधी शुल्कों के कारण से गंभीर नुकसान की स्थिति में हैं।
- xiii. पी. टी. ए. पर पाटनरोधी शुल्क होने के कारण से कच्ची सामग्रियों की अधिक लागत होने के कारण वस्त्र निर्यातक ठहराव की स्थिति में है। समग्र मूल्य श्रृंखला में मूल्य वर्धित (वैल्यू एडेड) वस्त्र उत्पादों के डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को संवेदनशील बनाया गया है और वे अप्रतियोगी हो गए हैं।
- xiv. मांग और आपूर्ति की स्थिति में परिवर्तन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है।
- xv. घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे काफी अच्छा लाभ हो रहा है और उसे एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है।
- xvi. आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति का होना और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र वृद्धि होना यह दर्शाता है कि वह पाटनरोधी शुल्क लागू होने का दुरुपयोग करके भारत में पी. टी. ए. के प्रयोक्ताओं की ओवर चार्जिंग का सहारा लेता रहा है। भविष्य में इतनी सीमित मात्रा जारी रहने को घरेलू उद्योग को उनके द्वारा उत्पादित पी. टी. ए. की अधिक कीमत से रोकने के लिए इसे एक संतुलनकारी के तौर पर भी देखा जा सकता है।
- xvii. वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटन के जारी रहने की कोई संभावना नहीं है।

- xviii. यद्यपि पी. टी. ए. पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से पी. टी. ए. के कुछ उत्पादकों को महत्वपूर्ण फायदा हुआ है, लेकिन प्रयोक्ता छूट में दर्जनों कंपनियां प्रभावित हुई हैं।
- xix. प्रयोक्ता सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी कच्ची सामग्रियों पर पाटनरोधी शुल्क लंबे समय से जारी रहे हैं। प्रयोक्ताओं को अपना कारोबार प्रतिस्पर्धी तरीके से चलाने के लिए उचित स्थान प्रदान करने के लिए शुल्कों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- xx. आई. ओ. सी. एल. के संयंत्र को 3-4 माह के लिए बंद किया गया है और प्रयोक्ताओं को पी. टी. ए. के एक व्यावहारिक वैकल्पिक स्रोत की जरूरत है। पी. टी. ए. के अन्य स्रोतों की निर्बाध और उचित उपलब्धता होनी चाहिए।
- xxi. रिलायंस द्वारा अत्यधिक कैप्टिव खपत की लागू पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पी. टी. ए. बाजार को रिलायंस द्वारा चलाए जाने की पूरी संभावना है।
- xxii. पी. एस. एफ. के आयातों में हाल की जांच में कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया था, क्योंकि घरेलू उद्योग यह सिद्ध नहीं कर सका था कि आयातों के कारण से क्षति हुई थी। पी. एस. एफ. के प्रमुख उत्पादक के रूप में रिलायंस ने भाग नहीं लिया था और उसने पी. टी. ए. और पी. एस. एफ., दोनों के लिए कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को हानि हुई है, क्योंकि उसने अपने प्रयोक्ताओं को उत्पादन की लागत का लाभ तक प्रदान नहीं किया था।
- xxiii. भारत में पी. टी. ए. की कीमतें किसी अन्य देश की तुलना में काफी अधिक हैं। भारतीय पी. टी. ए. उत्पादक समुदाय माल भाड़ा, बंदरगाह मंजूरी प्रभार, सीमा शुल्क और पाटनरोधी शुल्क के रूप में पी. टी. ए. की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर अतिरिक्त प्रीमियम ले रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अत्यधिक 7120 रूपए प्रति टन अथवा 102 यू. एस. डॉलर प्रति टन की अतिरिक्त वसूली करते हैं।
- xxiv. प्रयोक्ता उद्योग को वस्त्र/ मानव निर्मित फाइबर के लिए मजबूत निर्यात और घरेलू बाजार सहित अपने सभी अवसरों को तलाशने के लिए उचित कीमत पर पी. टी. ए. प्राप्त करने की जरूरत है। यह प्रमुख कारण कि क्यों मानव निर्मित फाइबर का हिस्सा बढ़ नहीं रहा, महंगी कच्ची सामग्री होना है।
- xxv. शुल्कों के कारण से, पी. एस. एफ. उत्पादकों की कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होती है और उन्हें अपने तैयार उत्पादकों पर डिस्काउंट देने पर बाध्य होना पड़ता है जिसके कारण से वे बीमार हो गए हैं।
- xxvi. जैसे-जैसे भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास होता है, उसके लाभ सभी घरेलू प्रतिभागियों को मिलेंगे, जिनमें पी. टी. ए. उत्पादक शामिल हैं, साथ इससे रोजगार, निर्यात और जी. डी. पी. में भी वृद्धि होगी।
- xxvii. संयंत्र में अल्प अवधि के लिए तालाबंदी हुई है, जिसकी अवधि और समय सीमा का नहीं पता है। इस तालाबंदी के कारण से बाजार में अभाव की स्थिति है और उत्पादक कीमतों पर कब्जा रखने के लिए इस अभाव का लाभ उठाते हैं।
- xxviii. प्रयोक्ता कम आपूर्ति को आयात नहीं मान सकते और प्रचालनों में कटौती हो रही है। जबकि रिलायंस 2018-19 में पी. एस. एफ. में 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग कर पाया और पी. टी. ए. की अबाध आपूर्ति के कारण उसके बाद 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग कर पाया, जबकि अन्य पी. एस. एफ. उत्पादक स्थानीय तालाबंदी के कारण से 65-75 प्रतिशत तक का न्यून उपयोग ही कर पाए।
- xxix. आपूर्ति के मामले कम से कम अगले 6 माह तक के लिए जारी रहने वाले हैं और पी. टी. ए. के उत्पादक इन अवसरों का उपयोग कीमतों में वृद्धि करने के लिए करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रयोक्ताओं के पास आयातों का रुख करना व्यावहारिक नहीं होगा।

- xxx. घरेलू उद्योग ने सुनवाई के दौरान पेपर बुक परिचालित नहीं की थी, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पूर्व में जारी व्यापार सूचना द्वारा अपेक्षित है। घरेलू उद्योग एकतरफा आरोप लगता रहा है, जबकि वह उसका खंडन करने के लिए दूसरे पक्ष को अवसर नहीं दे रहा है।
- xxxi. यद्यपि पेपर बुक बाद में 30 अप्रैल, 2019 को परिचालित की गई, उन्हें लिखित में दावों को पुनः प्रस्तुत करने तक उपयुक्त अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- xxxii. घरेलू उद्योग के आरोपों के उत्तर में यह कहा गया था कि प्रयोक्ताओं को उत्तर में खरीदों और आयातों के बारे में भी संगत सूचना निहित है।
- xxxiii. प्रश्नावली में खंड- ड. के उत्तर में उल्लेख किया गया था कि लागू नहीं है, क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के आयातों और पुनः बिक्रियों पर लागू है।
- xxxiv. सभी प्रयोक्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित सीडी- रोम में प्रदान की गई थी। इसमें सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सीडी- रोम का अगोपनीय पाठ शामिल है।
- xxxv. घरेलू उद्योग के इन्वायस डिस्काउंट के संबंध में आरोप आधारहीन हैं, क्योंकि उत्तरों में ऐसी सभी सूचना निहित है कि कैसे ये वस्तुएं संबंधित कंपनी के बुक अकाउंट में शामिल की जाती हैं।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. पाटन-रोधी विधि के अंतर्गत वर्तमान जांच किए जाने के कारण प्राधिकारी ने केवल ऐसे मुद्दों पर विचार किया है और जांच की है, जो कि वर्तमान विधि के अंतर्गत प्रासंगिक और उपयुक्त हैं। आरोपित मुद्दे, जैसे कि एकाधिकार से कीमत निर्धारण अथवा सुने जाने के अधिकार का दुरुपयोग, वर्तमान जांच के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इन आरोपों के समर्थन में रिकार्ड में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत, प्रत्येक याचिकादाता की बिक्री कीमत से कम है।
19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ग) में हितबद्ध पक्षकारों के कार्य-क्षेत्र के दायरे के बारे में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-
- "(ग) "हितबद्ध पक्षकार" में निम्नोक्त शामिल हैं:-*
- (1) जांच अधीन भारत में पाटित की जा रही किसी वस्तु का एक निर्यातक अथवा विदेशी उत्पादक अथवा आयातक अथवा व्यापारी अथवा व्यवसायिक संघ के ऐसे सदस्यगण जो कि उसके उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हैं;*
 - (2) निर्यातक देश की सरकार; और*
 - (3) भारत में समान वस्तु अथवा व्यापार अथवा व्यवसायिक संघ, जिसके अधिकतर सदस्यगण भारत में समान वस्तु का उत्पादन करते हैं।"*
20. यह नोट किया जाता है कि निचले स्तर के प्रयोक्ताओं और उनके संघों ने पाटन-रोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।
21. यह नोट किया जाता है कि हालांकि निचले स्तर के प्रयोक्ताओं और उनके संघों का नियम 2 (ग) में उल्लिखित परिभाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, तथापि, प्राधिकारी ने इन संघों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं को हल करने के लिए उनके अनुरोध की जांच की। एसआईएमए, सीआईटीआई और आईएसए जैसे संघों ने अपने विचार व्यक्त करते समय अपने दावों को अधिप्रमाणित करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही अपने सदस्यों पर मौजूदा शुल्कों के प्रभाव की मात्रा का कोई उल्लेख किया है। चूंकि कुछ समय से इस उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लागू था, इसलिए संघों के लिए यह संभव था कि वे पाटन-रोधी शुल्क के प्रभाव और उसकी मात्रा का उल्लेख

करते। प्राधिकारी निचले स्तर के अंतिम उत्पादों पर शुल्कों के प्रभाव की मात्रा पर याचिकादाताओं के निवेदनों को भी नोट करते हैं। याचिकादाताओं ने यह भी निवेदन किया है कि उपभोक्ताओं के निचले स्तर के उद्योग के आरोपित प्रतिकूल कार्य-निष्पादन के लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं।

22. शुल्कों के प्रभाव के बारे में प्रतिवादी प्रयोक्ताओं के निवेदनों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं ने अपने दावे को अधिप्रमाणित करने के लिए कोई ठोस अथवा सत्यापन किए जाने योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं ने निर्धारित प्रारूप और तरीके से कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर अधूरे हैं। घरेलू उद्योग ने अनेक उपभोक्ताओं के वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जो कि यह दर्शाती हैं कि प्रयोक्ता उद्योग के लाभप्रदता में गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्य यह दर्शाता है कि निचले स्तर का उद्योग फैल रहा है।
23. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने से किसी भी तरीके से आयातों की रोकथाम नहीं हुई है और न ही किसी तरीके से शुल्क को जारी रखने से आयातों की रोकथाम होगी। शुल्क को जारी रखने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने का उद्देश्य सामान्यतया अनुचित व्यापारिक पद्धतियों के कारण होने वाले व्यापार की विकृति के मुद्दे का निदान करना है, ताकि खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ. 1 घरेलू उद्योग के निवेदन

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देशों से निर्यातकों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन करना जारी रखा हुआ है।
- (2) संबद्ध देशों से पाटन का लम्बा इतिहास है और भारत में वर्तमान जांच में पाटन का मार्जिन, विगत जांच में निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन से अधिक है।
- (3) मेसर्ज इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड (आईआरपीएल), मेसर्ज टीपीटी पेट्रोकेमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड (टीपीटी) और मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन (एचटीसी) ने निर्यातक की प्रश्नावली के भाग-2 के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो कि संभावित विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- (4) जांच की अवधि के दौरान मेसर्ज एचटीसी विद्यमान नहीं थी और उसका मेसर्ज मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए निर्यातों के लिए उत्तर देने को कोई अधिकार नहीं है। एक संबंधित पक्षकार का उत्तर, वस्तुओं के वास्तविक निर्यातक के उत्तर को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
- (5) वितरण की श्रृंखला का भाग बनने वाले निर्यातकों और व्यापारियों ने जांच में भाग नहीं लिया है, जिसके कारण मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है।
- (6) एक ऐसे उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है, जिसकी वस्तुओं को मेसर्ज एचटीसी द्वारा भारत को निर्यात किया गया है।
- (7) मेसर्ज टीपीटी के उत्तरों में मेसर्ज एचटीसी, मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ("टेकवांग") और मेसर्ज टीपीटी जैसे अन्य निर्यातकों का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने जांच में भाग नहीं लिया है।
- (8) मेसर्ज आईआरपीएल, मेसर्ज टीपीटी और मेसर्ज एचटीसी ने अपने तृतीय देश के निर्यातों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो कि जो कि संभावित विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं।
- (9) मेसर्ज एचटीसी ने कोरिया के दो उत्पादकों की वस्तुओं की आपूर्ति की है, लेकिन उनमें से केवल एक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया है।

- (10) मेसर्ज आईआरपीएल और मेसर्ज टीपीटी ने भारत में मेसर्ज इंडो रामा सिंथेटिक्स लिमिटेड नामक अपने संबंधित आयातक के ब्यौरों को छिपाया है, जिसने वास्तव में थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए हैं।
- (11) मेसर्ज एचटीसी ने इस तथ्य को छिपाया है कि उसके संबंधित प्रयोज्यता का कोरिया जनवादी गणराज्य में एक संयंत्र है।
- (12) उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर स्वतः विरोधाभासी हैं।
- (13) जबकि एक स्थान पर मेसर्ज एचजीसी ने यह बताया है कि उनका कोई भी शेयरधारक और उनसे संबंधित कोई भी पक्षकार विचाराधीन उत्पाद को पुनः बेचने का कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी बाद में उसने यह बताया है कि उसका एक पक्षकार उत्पादों को पुनः बेचने का कार्य कर रहा है।
- (14) मेसर्ज टीपीटी, मेसर्ज आईआरपीएल और मेसर्ज टेक्वांग ने वितरण के माध्यम के बारे में परस्पर विरोधी दावे किए हैं।
- (15) जब तक किसी पक्षकार ने सही, संपूर्ण और वास्तविक सूचना प्रस्तुत नहीं की है, तब तक उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ अपनी उत्तम क्षमता से सहयोगी नहीं माना जा सकता है और उसके उत्तर को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- (16) प्रतिवादियों ने यह कहते हुए सहयोगी होने के दावे किए हैं कि वे किसी भी प्रकार की जरूरी "अन्य सूचना" अथवा "ब्यौरे" प्रदान करेंगे। तथापि, ऐसी स्थिति में प्राधिकारी केवल "अन्य" सूचना अथवा "ब्यौरे" की ही मांग कर सकते हैं और ऐसी सूचना की मांग नहीं करेंगे, जो कि प्रश्नावली की स्पष्ट भाषा के अनुसार पहले ही प्रदान की जानी अपेक्षित थी।
- (17) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शुल्क 24 जुलाई, 2019 को समाप्त हो जायेंगे और उससे पहले जांच पूरी हो जानी चाहिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्तरों के अपूर्ण होने के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं।
- (18) जबकि निर्यातकों ने प्रश्नावली का भाग-2 भी प्रस्तुत नहीं किया है अथवा तृतीय देश के निर्यातों का निर्धारण नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उनके उत्तर पर आधारित संभावित निर्धारण किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (19) घरेलू उद्योग द्वारा उत्तरों में कमियों का पता लगाने के लिए बहुताधिक पत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्यातकों को निवेदनों पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देने के बावजूद भी प्रतिवादियों को रक्षा में निवेदन करना अथवा स्पष्टीकरण देना अभी भी बाकी है।
- (20) चूंकि निर्यातक के गृह बाजार में प्रचलित कच्चे माल की लागत को ध्यान में रखते हुए पीएक्स, उत्पादन की कुल लागत का लगभग 80% भाग बनता है, इसलिए यह स्वतः सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का एक उचित आधार बनेगा।

छ. 3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
 - (1) हालांकि प्रस्तुत किए गए उत्तर, पक्षकारों की बेहतर समझ के अनुसार संपूर्ण हैं, फिर भी वे और सूचना/ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
 - (2) जांच की अवधि के दौरान वैश्विक तेल बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुआ है, जिसका पीएक्स और पीटीए की कीमतों पर सीधे प्रभाव पड़ा है। इसलिए पाटन मार्जिन का परिकलन, मासिक-वार आधार पर किया जाना चाहिए।
 - (3) याचिकादाताओं ने संबद्ध देशों में उत्पादकों के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है। ऐसा परिकलन काल्पनिक है और यह वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं है।

- (4) पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार मौके पर जांच करने का मुख्य उद्देश्य प्रदत्त सूचना का सत्यापित करना तथा और ब्यौरे प्राप्त करना होता है। इसलिए निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर जांच की समाप्ति नहीं है और प्राधिकारी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।
- (5) उपरोक्त सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य पक्षकारों ने क्रमशः पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए समस्त संबद्ध सूचना प्रस्तुत कर दी है और अंतिम जांच परिणाम के लिए उसको अपनाया जाना चाहिए।
- (6) मेसर्ज ह्यूसोंग का उत्तर संपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारत को किए गए सभी निर्यातों के बारे में सूचित कर दिया है तथा एक निर्यातक प्रयोज्यता पर लागू होने वाली प्रश्नावली में संपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं।
- (7) मेसर्ज एचटीसी पहले मेसर्ज ह्यूसोंग कापॉरेशन की एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र प्रयोज्यता है।
- (8) निर्यातित 85% से भी अधिक वस्तुएं मेसर्ज हनवा द्वारा उत्पादित की गई थीं और इसलिए ऐसी वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला संपूर्ण है, जबकि प्राधिकारी सदैव ऐसे उत्तर स्वीकार करते हैं, जहां 70% से भी अधिक मूल्य श्रृंखला पूरी होती है।
- (9) मूल जांच में मेसर्ज टीकवांग का पाटन मार्जिन केवल 4-5% था और वर्तमान जांच में यह पाटन नहीं है। कोरिया जनवादी गणराज्य से आयात पाटित नहीं किए जा रहे हैं और ये भारत में मांग और पूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए ही किए जा रहे हैं।
- (10) मेसर्ज टीकवांग द्वारा 90% से भी अधिक निर्यात सीधे किए गए हैं और बाकी निर्यात एक असंबंधित निर्यातक द्वारा किए गए हैं। इस निर्यातक ने शाब्दिक आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा उसे असहयोगी नहीं माना जा सकता है क्योंकि 70% से भी अधिक मूल्य श्रृंखला संपूर्ण है।
- (11) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ रिकार्ड पर उल्लिखित मेसर्ज सेमसंग जनरल केमिकल कंपनी लिमिटेड नाम में परिवर्तन करके उसे मेसर्ज हनवा जनरल केमिकल कर दें।
- (12) मेसर्ज आईआरपीएल और मेसर्ज टीपीटी ने इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ट्रेड नोटिस के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है।
- (13) मेसर्ज टीपीटी ने कुछ असंबंधित पक्षकारों के माध्यम से कुछ मात्रा में उत्पाद के निर्यात किए हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, ऐसे निर्यात बहुत नगण्य हैं।
- (14) यह निवेदन सही नहीं है कि घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन को अतिरंजित करने के लिए बड़ा-चढ़ा कर सामान्य मूल्य और निम्नतर निर्यात कीमत प्रस्तुत की है।
- (15) प्रश्नावली में निर्यातकों से ऐसी अपेक्षा है कि यदि निर्यातक की घरेलू कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया गया है, तो वे तृतीय देश के निर्यात आंकड़े प्रदान करें। किसी भी स्थिति में निर्यातक द्वारा प्रदत्त कार्य-निष्पादन के आंकड़ों में तृतीय देश के निर्यातों के ब्यौरे भी निहित हैं।
- (16) मेसर्ज टीपीटी और मेसर्ज इंडोरामा ने अपने कापॉरिट ढांचे के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।
- (17) मेसर्ज आईआरएसएल किसी भी शेयरधारिता के रूप में निर्यातकों से संबंधित नहीं है और संबंध केवल निदेशकों के परिवार के संबंधियों तक ही सीमित हैं। प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई मेसर्ज आईआरएसएल की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा प्रकटन उपलब्ध है।
- (18) घरेलू उद्योग का ऐसा दावा सही नहीं है कि मेसर्ज आईआरएसएल ने थाईलैंड से आयात किए हैं।
- (19) उत्तरों में कमी नहीं है और उन्हें खारिज नहीं कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं और उत्तर संपूर्ण हैं।

ज. सामान्य मूल्य

26. कोरिया जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
- (1) मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य
 - (2) मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
 - (3) मेसर्ज हनभा जनरल केमिकल कंपनी, कोरिया जनवादी गणराज्य
 - (4) मेसर्ज इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड, थाईलैंड
 - (5) मेसर्ज टीपीटी पेट्रोकेमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
27. कुछ निर्यातकों ने यह निवेदन किया है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण, मासिक आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करके किया जाना चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक, मासिक कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों में विशेष अंतर को दर्शाने में समर्थ नहीं हुए हैं।

ज.1 कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने उत्तर प्रस्तुत किया है। कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं के सीधे निर्यात किए थे और *** मी.टन निर्यात संबंधित निर्यातक मेसर्ज पोसको दाईवू के माध्यम से किए थे। वर्तमान जांच में मेसर्ज पोसको दाईवू ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
29. घरेलू बाजार में कंपनी ने कुछ केप्टिव खपत की है और कुछ बिक्रियां संबंधित पक्षकार को की हैं। कंपनी द्वारा सूचित उत्पादन की लागत की विस्तार से जांच की गई थी तथा आंकड़ों का उचित सत्यापन और समाधान करने के बाद कंपनी के उत्पादन की लागत का निर्धारण *** अमरीकी डालर/मी.टन किया गया है (जिसमें पैकिंग लागत शामिल नहीं है), जिसे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है।
30. कंपनी द्वारा की गई कारोबार-वार व्यौरों की विस्तार से जांच की गई है। लाभप्रद बिक्रियों के संबंध में ***% लाभ मार्जिन निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि कंपनी की ***% बिक्रियां लाभप्रद हैं। चूंकि बिक्रियां उत्पादन की लागत से 20% से भी अधिक हैं, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू बाजार में कंपनी की लाभप्रद बिक्रियों के आधार पर किया गया है। अंतर्देशीय भाड़े, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागत के संबंध में समायोजन के दावे किए गए हैं, जिनकी विधिवत् सत्यापन के बाद अनुमति दे दी गई है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/प्रति मी.टन बनता है।

मेसर्ज हनवहा जनरल केमिकल कंपनी, कोरिया जनवादी गणराज्य और मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज हनवहा जनरल केमिकल कंपनी (एचओसी) ने जांच अवधि के दौरान मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन (एचसी) के व्यापारी मंडल के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए थे। मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन (एचसी) के व्यापारी मंडल को समाप्त कर दिया गया है और मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन नामक एक नया प्रयोज्यता बनाया गया है। मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन (एचसी) द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में मेसर्ज एचटीसी ने उत्तर प्रस्तुत किया है। रिकार्ड का उचित सत्यापन करने के बाद प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि मेसर्ज एचओसी और मेसर्ज एचटीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाए।

32. निर्यातक द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों के कारोबार-वार व्यौरों की विस्तार से जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में ***% बिक्रियां लाभप्रद हैं। तदनुसार, लाभप्रद बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/प्रति मी.टन बनता है।

कोरिया जनवादी गणराज्य के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

33. कोरिया से ऐसे अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में जिन्हें असहयोगी माना गया है, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

ज. 2 थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

मेसर्ज इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड (आईआरपीएल), थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

34. मेसर्ज इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों का अनुशीलन करने पर यह पता चलता है कि उन्होंने प्रश्नावली के भाग-2 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें संभावित निर्धारण करने के लिए संबद्ध सूचना निहित होती है।
35. इसके अतिरिक्त विभिन्न परिशिष्टों पर सूचित किए गए आंकड़े/व्यौरे मिलते नहीं हैं। परिशिष्ट-9 में सूचित किए गए एसजीए व्यय, परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 में सूचित आंकड़ों के अनुरूप नहीं हैं। परिशिष्ट-5 (व्यापार के लिए) में सूचित लाभ और अन्य कच्चे माल की लागत, पैकिंग लागत और प्रयोज्यता लागत के आंकड़े भी परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 में निर्दिष्ट आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, जैसा कि परिशिष्ट-6 में सूचित किया गया है।
36. तदनुसार प्राधिकारी का यह मानना है कि निर्यातक असहयोगी है और निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन की अनुमति नहीं दी है।

मेसर्ज टीपीटी पेट्रोकेमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

37. मेसर्ज टीपीटी पेट्रोकेमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड (टीपीटी) द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर का अनुशीलन करने पर ऐसा पता चलता है कि उन्होंने प्रश्नावली के भाग-2 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें संभावित निर्धारण करने के लिए संबद्ध सूचना निहित है।
38. कंपनी ने पीयूसी के परिशिष्ट-7 और 8 में लाभ का दावा किया है, लेकिन वास्तविक में यह घाटा है। इसके अलावा परिशिष्ट-8, दिनांक 28.02.2018 के व्यापार नोटिस 05/2018 के अनुसार नहीं है क्योंकि कंपनी ने पीयूसी के लिए प्रति यूनिट लाग का उल्लेख/दावा नहीं किया है। कंपनी ने परिशिष्ट-6 में पैकिंग सामग्री लागत का दावा नहीं किया है, जबकि परिशिष्ट-7 में उसका दावा किया है। परिशिष्ट-7 और 8 में दावा किए गए बिक्री मूल्य, बिक्रियों से संबंधित परिशिष्ट-7 और 8 के समनुरूप नहीं हैं।
39. तदनुसार प्राधिकारी ने निर्यातक को असहयोगी माना है और निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन की अनुमति नहीं दी है।

थाईलैंड के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

40. चूंकि प्राधिकारी ने मेसर्ज आईआरपीएल और मेसर्ज टीपीटी को असहयोगी पाया है और थाईलैंड से किसी भी अन्य निर्यातक की ओर से भाग न लिए जाने के मद्देनजर प्राधिकारी ने थाईलैंड से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

झ. निर्यात कीमत

झ.1 कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

41. जांच अवधि के दौरान मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने 2 चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं अर्थात् पीटीए के ***मी.टन सीधे निर्यात किए हैं और ***मी.टन निर्यात, मेसर्ज पोसको डईबू नामक गैर-संबंधित पक्षकार के माध्यम से किए हैं। मेसर्ज पोसको डईबू ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। तथापि, चूंकि मेसर्ज पोसको डईबू नामक गैर-संबंधित पक्षकार के माध्यम से किए गए निर्यात, मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए कुल निर्यातों का केवल ***% भाग बनते हैं, इसलिए इस आधार पर मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए उत्तर को खारिज कर दिया गया है।
42. मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई थी तथा भारत और शेष विश्व में निर्यातों के संबंध में उसमें कुछ कमियां पाई गई थीं।
43. प्राधिकारी का मानना है कि समुद्री भाड़े और समुद्री बीमा, जहां कहीं भी लागू होता है, अंतरदेशीय परिवहन, बन्दरगाह और अन्य संबंधित निर्यात व्यय, पैकिंग प्रभार, क्रेडिट लागत, शुल्क वापसी, दस्तावेजों के शुल्क और बैंक प्रभार के लिए समायोजन करने पर विचार किया जाए।
44. चूंकि मेसर्ज पोसको डईबू नामक गैर-संबंधित पक्षकार ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए मेसर्ज पोसको डईबू के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए निर्यात कीमत के समायोजन पर बेहतर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार किया गया है। तदनुसार, मेसर्ज टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत, सीधे निर्यातों और मेसर्ज पोसको डईबू के माध्यम से किए गए निर्यातों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर प्राप्त की गई है। इस प्रकार कारखाना गत निर्यात कीमत ***अमरीकी डालर/मी.टन बनती है।

मेसर्ज हनहवा जनरल केमिकल कंपनी, कोरिया जनवादी गणराज्य और मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

45. मेसर्ज हनहवा जनरल केमिकल कंपनी ने संबद्ध वस्तुओं के निर्यात, मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन और मेसर्ज पोसको डईबू नामक 2 माध्यमों से किए थे। जबकि मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, मेसर्ज पोसको डईबू ने जांच में भाग नहीं लिया है। तथापि, चूंकि मेसर्ज पोसको डईबू नामक गैर-संबंधित पक्षकार के माध्यम से किए गए निर्यात, मेसर्ज हनभा जनरल केमिकल कंपनी द्वारा किए गए कुल निर्यातों का मात्र ***% भाग बनते हैं, इसलिए इस आधार पर मेसर्ज हनभा जनरल केमिकल कंपनी के उत्तर को खारिज कर दिया गया है।
46. मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन के माध्यम से किए गए निर्यातों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने इन वस्तुओं की विक्रियां अंत-प्रयोक्ताओं को की है, लेकिन जांच अवधि के दौरान उनको घाटा हुआ है। प्राधिकारी ने कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत का उचित रूप से समायोजन किया है। प्राधिकारी ने समुद्री भाड़े, अंतरदेशीय परिवहन, पोर्ट हैंडलिंग, पैकिंग प्रभारों, क्रेडिट लागत और शुल्क वापसी के समायोजनों पर विचार किया है।
47. चूंकि मेसर्ज पोसको डईबू ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, उक्त निर्यातक के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए निर्यात कीमत का समायोजन, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करने पर विचार किया गया है। तदनुसार, मेसर्ज ह्योसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन और मेसर्ज पोसको डईबू के माध्यम से किए गए निर्यातों की भारित औसत निर्यात लागत के आधार पर मेसर्ज हनहवा जनरल केमिकल कंपनी के लिए निर्यात कीमत प्राप्त की गई है। कारखाना-गत निर्यात कीमत ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

कोरिया जनवादी गणराज्य से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

48. प्राधिकारी ने कोरिया जनवादी गणराज्य से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। तदनुसार, कोरिया जनवादी गणराज्य से निर्यातों के लिए कारखाना-गत स्तर पर निर्धारित निबल निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

झ.2 थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत

49. प्राधिकारी ने थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। तदनुसार, थाईलैंड से निर्यातों के लिए कारखाना-गत स्तर पर निर्धारित निबल निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ज. संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

50. उपरोक्त अनुसार सामान्य मूल्य निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर/मी.टन)	निर्यात कीमत (अमरीकी डालर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (अमरीकी डालर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (सीमा)
1.	कोरिया जनवादी गणराज्य	टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2.	कोरिया जनवादी गणराज्य	मेसर्ज हनहवा जनरल केमिकल कंपनी द्वारा मेसर्ज हयोसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन के माध्यम से	***	***	***	***	10-20
3.	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
4.	थाईलैंड	कोई भी	***	***	***	***	10-20

ख. क्षति निर्धारण और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए कार्य-प्रणाली**ख.1 घरेलू उद्योग के निवेदन**

51. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग भंगुर होने की स्थिति में है और उसे निरंतर सहायता और शुल्कों से संरक्षण देने की आवश्यकता है। शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उसके द्वारा की गई प्रगति के धीमे पड़ जाने की संभावना है।
- (2) हालांकि वर्ष 2016-17 तक आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन जांच अवधि में इसमें दुबारा 74% तक की वृद्धि हो गई है, जबकि मांग में केवल 9% की वृद्धि हुई है।
- (3) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयातों में वृद्धि हुई है।
- (4) संबद्ध आयातों ने बाजार के लगभग 10% भाग को निरंतर हथियाया हुआ है।

- (5) कुल आयातों के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है और अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है। संबद्ध आयात, भारत में कुल आयातों का लगभग 72% भाग बनते हैं।
 - (6) देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भारत संबद्ध वस्तुओं का एक निबल आयातक बना हुआ है। यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का घाटा होगा।
 - (7) इसके अतिरिक्त घरेलू उत्पादक भी उत्पाद की संभावित मांग को पूरा करने के लिए क्षमता का विस्तार करने हेतु लगभग ***अमरीकी डालर का निवेश कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप शुल्कों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है।
 - (8) आयातों और घरेलू संबद्ध वस्तुओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। घरेलू उद्योग को आयातों की कीमत के लगभग समान कीमत बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ा है और उसे उचित लाभ अर्जित करने के लिए अपनी कीमतों को बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं है।
 - (9) वर्तमान जांच में कीमत में कटौती सकारात्मक है और जांच अवधि के दौरान आयातों ने घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभ कमाने से रोके रखा है।
 - (10) कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और अत्यधिक है, जिससे पता चलता है कि आयातों की कीमतें उचित बिक्री कीमत से काफी कम हैं और पाटन-रोधी को शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
 - (11) भारत में पर्याप्त मांग है, जिससे उद्योग ***% तक उपयोग कर सकता है। तथापि, आयातों के कारण घरेलू उद्योग को घाटों पर *** लाख मी.टन का निर्यात करने पर विवश होना पड़ा है, जबकि वह ***% क्षमता प्रचालन कर रहा था।
 - (12) लागू शुल्कों के परिणाम स्वरूप ही घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है।
 - (13) जबकि जांच अवधि के दौरान बाजार के हिस्से में कमी अत्यधिक नहीं है, फिर भी इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने की स्थिति में ऐसी गिरावट आई है।
 - (14) आयातों में वृद्धि होने के फलस्वरूप आधार वर्ष में माल-सूचियों में पांच गुना वृद्धि हुई है और माल-सूची को रखने की अवधि बढ़ गई है।
 - (15) घरेलू उद्योग का लाभ पर्याप्त नहीं है और सुधार की दर धीमी है।
 - (16) निवेश पर प्रतिलाभ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए 22% के मानक से बहुत कम है।
 - (17) घरेलू उद्योग ब्याज की बैंक दर अर्जित करने में भी सक्षम नहीं है, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पूंजीगत निवेश बढ़ाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
 - (18) निर्णायक समीक्षा जांच में संभावित पाटन और संभावित क्षति होने के बीच कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने को अधिप्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - (19) घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति होने की संभावना नहीं है।
 - (20) शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली संभावित क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध है।
- (क) संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है।
- (ख) विशेषकर विगत दो वर्षों में आयातों में वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

- (ग) परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग की वस्तुओं की मांग में गिरावट आएगी, जिससे उसकी बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयो पर प्रभाव पड़ेगा।
- (घ) कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री होना सकारात्मक है।
- (ङ) शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयात कीमतों में संभवतः और कमी होगी जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी लाभप्रदता में और अधिक गिरावट आएगी।
- (21) अपर्याप्त मार्जिन होने के कारण मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पटलगंगा में अपने संयंत्र के प्रचालनों को बंद करने के लिए विवश होना पड़ा है।
- (22) मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लाभप्रदता से संबंधित तर्कों के उत्तर में यह निवेदन किया गया था कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही देखा जाना चाहिए और कंपनी का समग्र निष्पादन अप्रासंगिक है।
- (23) इस तर्क के उत्तर में कि वर्ष 2014-15 से आयातों में गिरावट आई थी, यह निवेदन किया जाता है कि जब पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं था, तो उस अवधि के दौरान हुए आयातों की तुलना, उस अवधि के साथ नहीं की जा सकती है जब शुल्क लागू थे।
- (24) घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद को उन कीमतों पर बेचना पड़ा था, जो कि शुल्क सहित आयात कीमत से काफी कम थीं। यदि उसने अपनी कीमतों को बढ़ाने का प्रयास किया होता, तो प्रयोक्ता तत्काल आयातों की ओर प्रवृत्त हो जाते।
- (25) प्रतिवादियों के तर्कों के विपरीत जिन देशों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं हो रहा है, वहां से आधार वर्ष की तुलना में आयातों में आयातों में 6 गुना वृद्धि हुई है।
- (26) इन तर्कों के संबंध में कि आयातों की मात्रा नगण्य थी, यूरोपीय संघ में प्रचलित पद्धति का हवाला दिया जाता है, जहां प्रत्येक देश से आयात मांग के 1% से भी अधिक और समस्त संबद्ध देशों से सामूहिक आयात 1% से भी अधिक होने पर उन्हें अत्यधिक माना जाता है।
- (27) पीएसएफ के परिणाम पर प्रतिवादियों का विश्वास करना उचित नहीं था क्योंकि यह एक ऐसी मूल जांच थी, जबकि वर्तमान मामले में शुल्क लागू होने के बावजूद आयात, बाजार का 10% हिस्सा बनते हैं।
- (28) मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लाभ मार्जिन के आंकड़ों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया था कि सूचित मार्जिन वैश्विक स्तर के हैं, जबकि वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सूचित मार्जिन के लिए स्रोत के रूप में प्लेट्स, आईसीआईएस, सीसीएस जर्नल हैं।
- (29) इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लागू किए जाने से पूर्व आयातों की भरमार होने की कोई स्थिति नहीं थी, यह निवेदन किया जाता है कि यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिणाम निष्कर्षों के विपरीत है।
- (30) इस तर्क के उत्तर में कि वैश्विक मांग-पूर्ति की स्थिति के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह निवेदन किया जाता है कि यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिणाम के विपरीत है, जिसका यह निष्कर्ष था कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (31) मार्जिन में वृद्धि होने के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि उस अवधि की तुलना में जबकि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को घाटे हुए थे, उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता पर्याप्त है।
- (32) मेसर्ज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अत्यधिक केपिटल खपत होने के तर्क के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग व्यापारी बाजार पर अत्यधिक निर्भर था और यह उसके कारोबार का प्रमुख भाग बनता है।

- (33) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग भार और पतन प्रभावों आदि के कारण ***रूप प्रति अतिरिक्त टन प्रभावित करने में समर्थ है, यह निवेदन किया जाता है कि यदि ऐसे व्ययों को अलग कर दिया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयातों की कीमत, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत से कम है।
- (34) इस तर्क के संबंध में कि मेसर्स एमसीपीएल को संयंत्र के बंद हो जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उल्लेखनीय है कि जांच अवधि के दौरान मेसर्स एमसीपीएल का क्षमता उपयोग अधिक था।

ब.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) यह तथ्य कि आयातों के समाप्त हो जाने से घरेलू उद्योग का घरेलू बाजार में लगभग एकाधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण उसके द्वारा अत्यधिक लाभ अर्जित किए जाने से उसके कार्य-निष्पादन में विशेष रूप से अत्यधिक सुधार हुआ है, जिससे ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग को न तो कोई वर्तमान क्षति हुई है और यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसे न तो क्षति की पुनारुक्ति होने की कोई संभावना है।
- (2) आयातों में ***% तक की गिरावट आई है, जो कि पर्याप्त है।
- (3) घरेलू उद्योग आर्थिक क्षति होने के बहाने पाटन-रोधी संरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि वह निवेश कर रहा है और घरेलू बाजार में एकाधिकारिक कीमतों के साथ क्षमताएं बढ़ा रहा है।
- (4) आयातों में कमी को भारत में पीटीए का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने के साथ जोड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि गिरावट स्थाई है। जांच अवधि पश्चात् आयातों में और गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त भारत में मांग को देखते हुए इस अवधि के दौरान आयात अथाह थे।
- (5) लागत में गिरावट, बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक थी, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने लागत में कटौती के लाभ अपने उपभोक्ताओं को अंतरित नहीं करने में बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति का उपयोग किया है।
- (6) आयातों में गिरावट आने और घरेलू उद्योग की मात्रा में वृद्धि होने से पता चलता है कि प्रयोक्ता, अग्रिम लाईसेंस और ईपीसीजी के अंतर्गत निशुल्क आयातों की कुछ मात्रा को छोड़ कर पीटीए के घरेलू उत्पादकों पर विश्वास कर रहे हैं।
- (7) यदि कीमत में अत्यधिक अंतर नहीं होता है, तो प्रयोक्ता उद्योग सदैव स्थानीय आपूर्ति को प्राथमिकता देगा। इसलिए यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, तो घरेलू प्रयोक्ता निरंतर घरेलू उद्योग से खरीदारी करते रहेंगे, जब तक कि वह एकाधिकार से कीमत का निर्धारण नहीं करता है।
- (8) पाटन-रोधी शुल्क संरक्षण और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिक मार्जिन (जो कि जांच अवधि के दौरान 15-30% और उसके बाद 40% है) के कारण घरेलू उद्योग की एकाधिकारिक कीमत निर्धारण के कारण नगण्य स्तर पर कीमत में कटौती हो सकती है।
- (9) यहां तक कि ऐसे अन्य स्रोतों, जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं होता है, से आयातों में गिरावट आई है, जिससे भी घरेलू उद्योग के प्रयोक्ताओं का स्थाई रूप से अंतरित होने का पता चलता है।
- (10) मांग के संबंध में आयात नगण्य हैं और ऐसी कम मात्रा के नहीं होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग पूर्णतः एकाधिकारिक कीमत निर्धारण के क्रियाकलाप करेगा।
- (11) जैसा कि पीएसएफ की पाटन-रोधी जांच परिणाम में निर्णय दिया गया है, मांग में आयातों द्वारा धारक 7% के नगण्य अंशदान को किसी प्रकार की क्षति के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है।
- (12) जांच अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग आदि जैसे प्राचल उच्चतम स्तर पर बने रहे हैं। मात्रात्मक प्राचलों में ऐसे विशिष्ट कार्य-निष्पादन से पता चलता है कि वर्तमान शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग किसी भी प्रकार की क्षति से असुरक्षित नहीं है।

- (13) बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत, लाभप्रदाता प्रति यूनिट, पीवीआईटी आदि जैसे कीमत प्राचलों में आश्चर्यजनक संवृद्धि हुई है और यह बहुत अधिक है।
- (14) बिक्री कीमत में कमी, लागत में कमी से निम्न थी, इस तथ्य से कि पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने सुदृढ़ कीमत निर्धारण शक्ति का लाभ उठाया है, जिसके फलस्वरूप उसके पीवीआईटी में जबरदस्त उछाल आया था।
- (15) हाल ही में मेसर्ज आरआईएल द्वारा अर्जित मार्जिन से ऐसे मार्जिन में सुसंगत बढ़ी मात्रा का पता चलता है, जो कि बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण कुछ क्षेत्रों में कुछ अनिश्चितता बनी रहने के बावजूद भी घटित हुई है।
- (16) निर्णायक समीक्षा जांच में जांच पश्चात अवधि में मार्जिन महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि में ***अमरीकी डालर प्रति मीटर मार्जिन था जो कि उसके बाद बढ़ कर ***अमरीकी डालर प्रति मीटर हो गया है। ऐसा घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए कीमत निर्धारण में एकाधिकारिक उपागम से हुआ है।
- (17) घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर 15% से 30% तक की सीमा में प्रतिलाभ अर्जित कर रहा है और ऐसा सुसंगत मार्जिन दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अब आयातों से किसी भी प्रकार की क्षति से असुरक्षित नहीं है।
- (18) जबकि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, संबद्ध देशों का हिस्सा आधा रह गया है। भारत में क्षमता में 67% तक की वृद्धि होने के फलस्वरूप आयातों में 50% तक की कमी आई है।
- (19) आयातित उत्पाद के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है और जो आयात हुए हैं, उनमें मुख्यतया निर्यात दायित्वों के आयात शामिल हैं।
- (20) अधिक कीमत बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग की कार्यक्षमता के साथ सकारात्मक कीमत कटौती से पता चलता है कि घरेलू उद्योग कीमत प्रदाता है, न कि कीमत प्राप्तकर्ता।
- (21) संबद्ध देशों से पीटीए पर पाटन-रोधी शुल्क के निरंतर जारी रहने से भारत में प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (22) घरेलू उद्योग द्वारा क्षति मार्जिन का दावा अतिशयोक्ति पूर्ण है और घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से अपनी लागत से अधिक कीमत पर और उसकी क्षति रहित कीमत से भी अधिक कीमत पर बिक्री कर रहा है। यदि घरेलू उद्योग उचित कीमत पर बिक्री कर रहा होता, उसने इतना अधिक लाभ और मार्जिन अर्जित नहीं किया होता।
- (23) निचले स्तर के उद्योग की मांग में बहुविध संवृद्धि होने और घरेलू उद्योग द्वारा बनाई गई सतत विस्तार योजनाओं के आलोक में पाटन-रोधी शुल्क के माध्यम से पीटीए की उपलब्धता में निरंतर प्रतिबंध लगाना तर्कसंगत नहीं है।
- (24) मेसर्ज रिलायन्स की वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मांग-पूर्ति की स्थिति का भारतीय बाजार पर भी प्रभाव पड़ा था। तथापि, हाल ही में प्रकाशित परिणामों से पता चलता है कि सख्त आपूर्तियां और निश्चित मांग होने के कारण पीटीए मार्जिन में सुधार हुआ है।
- (25) मूल जांच अवधि और जांच की वर्तमान अवधि के बीच की अवधि के दौरान पीटीए मार्जिन में ***% तक की संवृद्धि हुई है। मेसर्ज आरआईएल के आंकड़ों को उद्योग की औसत के बतौर प्रयुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह संबद्ध वस्तुओं की सबसे बड़ी उत्पादक है।
- (26) वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान निचले स्तर के उद्योग की धीमी मांग और द्रवता की सख्ती के कारण मार्जिन में गिरावट आई है, जिसका आयातों से कोई सरोकार नहीं है।
- (27) घरेलू उद्योग विगत क्षतियों से उभर कर आया है और कार्य-निष्पादन का सुसंगत सुसंगत स्तर दर्शाता है कि घरेलू उद्योग आयातों से होने वाली किसी भी क्षति से असुरक्षित नहीं है।
- (28) हालांकि मांग वर्ष 2014-15 में 100 बिन्दुओं से बढ़ कर जांच अवधि में 128 सूचक बिन्दु हो गई है, आयातों में ***% तक की गिरावट आई है। तुलना करने से घरेलू उद्योग की बिक्रियों में ***% तक की वृद्धि होने का पता चलता है।

- (29) जबकि पहुंच कीमत लागत में गिरावट के लगभग समान रूप है, बिक्री कीमत में अनुरूप कमी नहीं हुई है।
- (30) कीमत में कटौती होने को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन उसे घरेलू उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन के आलोक में देखना होगा ताकि यह पता चल सके कि क्या उसे घाटे हो रहे हैं।
- (31) जबकि याचिकादाताओं ने यह दावा किया है कि आयात कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्रदत्त आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2016-17 को छोड़ कर जांच अवधि के दौरान कीमत में कटौती नकारात्मक है।
- (32) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है और जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग अधिकतम है।
- (33) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां, केपिटव खपत और निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि होने के साथ-साथ बढ़ी हैं।
- (34) घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 100 से बढ़ कर जांच अवधि के दौरान 130 हो गया है, जबकि आयातों का हिस्से में गिरावट आई है। अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से में भी गिरावट आई है।
- (35) एमसीपीआई द्वारा एमसीए को प्रस्तुत की गई निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी खराबियों, ग्रिड में विद्युत में गिरावट आने आदि के कारण संयंत्र को बंद करना पड़ा था। वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों से पता चलता है कि अन्य कारक घरेलू उद्योग की क्षति के कारण हो सकते हैं।
- (36) जबकि लाभ में 100 से 485 सूचक बिंदुओं तक की पर्याप्त वृद्धि हुई है, निवेश पर प्रतिलाभ में भी समान रूप वृद्धि हुई होगी।
- (37) जबकि कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है, फिर भी घरेलू उद्योग की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (38) घरेलू उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा है और घरेलू उद्योग की क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- (39) भारत में मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर को दूर करने के लिए आयातों में वृद्धि हो रही है और न कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
- (40) आयातों से भिन्न अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है।
- (41) पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पता लगाने के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- (42) मूल जांच की जांच अवधि से ले कर अब तक वैश्विक और भारतीय पीटीए बाजार की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। यदि शुल्क को निरंतर जारी रखा जाता है, तो याचिकादाता एक अतिरिक्त और अनुचित लाभ प्राप्त करेंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को असमान्य लाभ होगा।
- (43) शुल्क लागू किए जाने के समय से आयातों की मात्रा निरंतर निम्न स्तर पर बनी हुई है और पीटीए-पीएक्स का व्यापक विस्तार होने के कारण भारतीय घरेलू उत्पादकों ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है।
- (44) रिलायन्स इंडस्ट्रीज पीएक्स और पीटीए के लिए अपने उत्पादन को निरंतर बढ़ा रही है।
- (45) यह तथ्य कि उसने मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार कर लिया है तथा उसका और विस्तार करने की योजना है, इस तर्क को निषिद्ध कर देता है कि उद्योग भंगुर है और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग अत्यधिक अच्छा कार्य-निष्पादन कर रहा है और उसके द्वारा वसूल की जा रही कीमतों ने भी उसके निवेशों पर बहुत अधिक मार्जिन सुनिश्चित किया है।
- (46) कथित "भंगुर उद्योग" का निर्धारण अथवा उसको अभिज्ञात करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली में कोई प्रावधान निहित नहीं है और घरेलू उद्योग को भंगुर निर्धारित किए जाने की स्थिति में पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू किए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

- (47) सकारात्मक क्षति मार्जिन के दावे, घरेलू उद्योग द्वारा असंगति से अत्यधिक क्षति-रहित कीमत पर किए गए दावों के कारण हो सकते हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

53. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में नीचे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल किया गया है।

क. संचयी मूल्यांकन

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:

- प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और
- आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

55. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित टिप्पणी करते हैं:

- प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं।
- प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है।
- विभिन्न संबद्ध देशों से और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामान समान वस्तु हैं।
- आयातित और घरेलू उत्पाद का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।
- किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है जो संचयी मूल्यांकन का औचित्य न बनाए।

56. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के संबंध में कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझते हैं।

57. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है।

58. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी। वर्तमान मामले में यह पाया जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा अपर्याप्त नहीं है। उत्पाद का पाटन संगत अवधि के दौरान जारी रहा है।

59. इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई है, की जांच करने के लिए कार्रवाई करते हैं।

ख. मांग एवं बाजार हिस्सा

60. संबद्ध सामानों की घरेलू खपत/मांग का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा भारत में कुल आयातों में जोड़ी गई है और उसका सार नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	170	192
अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	88	63
संबद्ध आयात	मी. टन	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
अन्य देशों से आयात जिन पर शुल्क लग रहा है	मी. टन	3,85,983	4,37,338	1,71,892	1,37,322
अन्य आयात	मी. टन	1,081	1,103	22,932	6,119
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	113	124
कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	152	166
अन्य भारतीय उत्पादक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	88	63
संबद्ध आयात	मी. टन	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
अन्य देशों से आयात जिन पर शुल्क लग रहा है	मी. टन	3,85,983	4,37,338	1,71,892	1,37,322
अन्य आयात	मी. टन	1,081	1,103	22,932	6,119
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	119	128

61. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में दोनों स्थितियों में क्षति की अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है।

ठ. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

क. आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

62. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में पूर्ण दृष्टि से अथवा उत्पादन के सापेक्ष अथवा खपत में पाटित आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है। क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से लिए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
अन्य देशों से आयात जिन पर शुल्क लग रहा है	मी. टन	3,85,983	4,37,338	1,71,892	1,37,322
अन्य आयात	मी. टन	1,081	1,103	22,932	6,119

कुल आयात	मी. टन	10,44,572	6,95,828	4,12,423	5,21,478
की तुलना में आयात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	29	22	36
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	36	29	46
मांग (कैप्टिव सहित)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	28	45
कुल आयात	%	62.95%	36.99%	52.76%	72.49%

63. यह देखा जाता है कि:

- संबद्ध देशों से आयातों में 2016-17 तक गिरावट आई है और उनमें उसके बाद पूर्ण दृष्टि से जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- भारतीय उत्पादन एवं मांग के संबंध में आयातों में समान प्रवृत्ति रही। संबद्ध आयातों में उत्पादन और खपत की दृष्टि से 2016-17 तक गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
- कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में 2015-16 में गिरावट आई और उसके बाद निरंतर वृद्धि हुई है।

ड. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

64. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से कीमतों की कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने उत्पाद की पहुँच कीमत तथा सभी छूटों और करों के निवल घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की है। आयातों की पहुँच कीमत, घरेलू कीमत और कटौती का मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार है:

कोरिया गणराज्य

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	57,618	47,134	45,694	48,436
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	0-10%	0-5%

थाइलैंड

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	56,449	46,398	45,589	48,253
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-5%	0-5%	0-10%	0-5%

66. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम है जो सकारात्मक कीमत कटौती दर्शा रही है।

ख. कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का कीमत ह्रास करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा हुई होती। प्राधिकारी ने आयातों की पहुँच कीमत तथा पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों की जांच की है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	57,192	46,796	45,642	48,335
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	80	85
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	84	87
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	82	82

68. यह देखा जाता है कि यद्यपि आयातों की पहुँच कीमत में 2016-17 तक गिरावट आ रही थी, तथापि, जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, यद्यपि बिक्री लागत में 2015-16 में काफी गिरावट आई, तथापि, उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी 2015-16 में काफी गिरावट आई और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई। पाटनरोधी शुल्क लागू रहने पर आयातों से कीमत न्यूनीकरण नहीं हो रहा था। तथापि, जबकि आयातों की पहुँच कीमत 2014-15 और 2015-16 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी, आयातों की पहुँच कीमत उसके बाद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी।

ग. कम कीमत पर बिक्री

69. कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन संबद्ध देशों की पहुँच कीमत के साथ क्षति रहित कीमत की तुलना करके किया गया है:

विवरण	यूनिट	कोरिया गणराज्य	थाइलैंड
क्षति रहित कीमत	रु./मी. टन	***	***
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	48,436	48,253
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी. टन	***	***

कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	5-15%	5-15%
पाटनरोधी शुल्क	रु./मी. टन	1,289	3,341
एडीडी सहित पहुँच कीमत	रु./मी. टन	49,725	51,594
एडीडी सहित कम कीमत पर बिक्री	रु./मी. टन	***	***
एडीडी सहित कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
एडीडी सहित कम कीमत पर बिक्री	रेंज	5-15%	0-10%

70. क्षति रहित कीमत के साथ पहुँच कीमत की तुलना से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री काफी तथा उत्तरदाता निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन से अधिक है।

ढ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

71. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटन आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

72. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	165	167
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	160	174
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	97	104
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	170	192
कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	133	138
निर्यात	मी. टन	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	160	145

73. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी। भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त क्षमता देश में *** लाख मी. टन की मांग की तुलना में *** लाख मी. टन है।
- ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग में देश के भीतर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री क्षति की अवधि में बढ़ी है।
- घ. कैप्टिव खपत भी क्षति की अवधि में बढ़ी है। व्यापारिक घरेलू बिक्री में वृद्धि कैप्टिव खपत में वृद्धि की अपेक्षा अधिक है।
- ङ. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के भाग का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उसने घरेलू बाजार से मांग के अभाव के कारण ही निर्यात किया है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

74. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कैप्टिव सहित मांग					
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	28	45
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	42	29
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	127	129
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	74	49
कैप्टिव को छोड़कर मांग					
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	36	29	46
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	45	30
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	150	155
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	78	51

75. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में शुल्क लागू होने के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि मांग में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है, तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान अपर्याप्त नहीं था।

ग. मालसूची

76. संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	242	496	743
अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	205	306	418

77. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में मालसूची के स्तर में काफी वृद्धि हुई है।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ तथा निवेश पर आय

78. घरेलू उद्योग के लाभ/हानि, नकद प्रवाह, नकद लाभ और निवेश पर आय निम्नलिखित हैं:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	रु./मी. टन	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	40	69	256
नकद लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	200	347	499
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	47	70	196

79. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को पूर्व में वित्तीय हानियां हो रही थीं जबकि पाटनरोधी उपाय लागू होने से घरेलू उद्योग हानियों से बाहर आ गया है परंतु अब भी अर्जित लाभ नियोजित पूंजी पर अपर्याप्त आय पर विचार करते हुए ईष्टतम से कम है।
- ख. उत्पाद की प्रति यूनिट अर्जित नकद लाभ पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक था और क्षति की अवधि में उसमें सुधार हुआ है।
- ग. अर्जित नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) 2014-15 में नकारात्मक थी, 2015-16 में सकारात्मक हो गई और क्षति की अवधि में उसमें आंशिक रूप से सुधार हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा निवेश पर अर्जित आय इष्टतम से कम थी।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

80. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नलिखित थी:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
मजदूरी	□ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	99	75
मजदूरी प्रति यूनिट	□ / मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	62	43
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	96	94
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	167	185
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	160	174

81. यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि में कम हुई है और प्रति यूनिट मजदूरी में भी गिरावट आई है। प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता में भी क्षति की अवधि में वृद्धि हुई।

च. वृद्धि

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
बिक्री	%	-	43%	19%	13%
उत्पादन	%	-	20%	34%	9%
प्रति यूनिट लाभ	%	-	140%	74%	271%
प्रति यूनिट नकद लाभ	%	-	100%	73%	44%
निवेश पर आय	%	-	147%	50%	179%

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभ मानदंडों ने इस अवधि में वृद्धि दर्शाई है। यह भी नोट किया जाता है कि काफी वृद्धि के बावजूद निवेश पर आय *** प्रतिशत से कम है।

छ. पाटन मार्जिन

83. यह पाया जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है। आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से अथवा उत्पादन के संबंध में अथवा देश में उत्पाद के लिए व्यापारिक मांग के संबंध में अपर्याप्त नहीं है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार में सख्त कीमत प्रतिस्पर्द्धा है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुँच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग आयातों की कीमतों के साथ अपनी कीमतों बराबर रख रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और बिक्री कीमत से कम है।

झ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

85. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के एक घटक ने संबद्ध सामानों के लिए क्षमता बढ़ाई है। घरेलू उद्योग ने काफी पूंजी निवेश किया है। यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप पूंजी निवेश जुटाने में उनकी क्षमता में सुधार हुआ है।

ण. क्षति संबंधी निष्कर्ष

86. मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा में पहले गिरावट आई थी और फिर भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई थी। आयातों और घरेलू उद्योग के बीच कीमत प्रतिस्पर्द्धा है। कीमत कटौती सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। पाटनरोधी शुल्क से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव होने से आयात रुके हैं। यद्यपि, घरेलू उद्योग के कुछ आर्थिक मानदंडों ने लाभप्रदता में सुधार के संकेत दर्शाए हैं तथा नियोजित पूंजी पर आय ईष्टतम से कम है।

नियोजित पूंजी पर आय 4.82 प्रतिशत है जोकि व्याज की लागत वसूल करने के लिए भी काफी नहीं है। इन सतत पाटित आयातों के कारण क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी रहता है।

त. क्षति की मात्रा तथा क्षति मार्जिन

87. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है। इस प्रकार, निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नलिखित है:

देश	उत्पादक	निर्यातक	एनआईपी अमेरिकी डॉलर /मी. टन	पहुँच मूल्य अमेरिकी डॉलर /मी. टन	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर /मी. टन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
कोरिया गणराज्य	तइकवांग इंडस्ट्रियल कं. लि.	तइकवांग इंडस्ट्रियल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
कोरिया गणराज्य	ह्योनसांग टीएनसी कारपोरेशन के माध्यम से हनवा जनरल कंपनी	ह्योनसांग टीएनसी कारपोरेशन के माध्यम से हनवा जनरल कंपनी	***	***	***	***	10-20
कोरिया गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20

थ. कारणात्मक संपर्क

88. क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की जांच उसकी कीमत कटौती के संबंध में करने पर प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध किए गए अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों और पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात केवल आयातों का 1 प्रतिशत है। अन्य स्रोतों से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

ख. मांग में संकुचन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं है। इसके विपरीत, संबद्ध सामानों के लिए समग्र मांग ने क्षति की अवधि में सुधार दर्शाया है। इसके अतिरिक्त, खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ग. प्रौद्योगिकी में विकास

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में संभावित महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। घरेलू उद्योग के संबद्ध सामानों के तीन प्रमुख उत्पादक हैं और उनका काफी घरेलू उत्पादन और बिक्री है। इस प्रकार, ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो।

ङ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

93. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों में वृद्धि हुई है। यद्यपि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करते समय निर्यात विक्री और लाभ से संबंधित आंकड़ों को अलग किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वे देश के भीतर उनके उत्पाद के लिए मांग के अभाव के कारण ही निर्यात करने के लिए विवश हुए हैं।
94. उपर्युक्त विश्लेषण ने प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक से नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित से सिद्ध है:
- शुल्क लागू रहने के बावजूद संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहा।
 - घरेलू उद्योग उन कीमतों को लगाने में सक्षम नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को उपयुक्त आय हो सकती थी।
 - शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में या तो आयातों से कीमतों में ह्रास, घरेलू उद्योग की कीमत और लाभ मानदंडों में ह्रास होने की संभावना है या इससे घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंड प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है अथवा दोनों की संभावना।

द. क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

95. समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में निरंतर आ रहे हैं अथवा आने की संभावना है तथा यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो क्या घरेलू उद्योग को इन पाटित आयातों के कारण क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

द.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

96. घरेलू उद्योग ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है और क्षतिकारक कीमतों पर आयात बाजार में आ रहे हैं।
 - वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन गहन पाटन दर्शाते हुए मूल जांच की अपेक्षा अधिक है।
 - निर्यातकों का अनुचित कीमत व्यवहार इस तथ्य से सिद्ध है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक रहा है।
 - इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में निर्यातक तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं। कोरिया से *** प्रतिशत निर्यात और थाइलैंड से *** प्रतिशत निर्यात पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर हैं। तीसरे देश के निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन भी काफी हैं।
 - जांच की अवधि में ही आयातों में वृद्धि हुई। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि की संभावना का संकेतक है।
 - इसके अतिरिक्त, आयातों में भी तिमाही-वार आधार पर पूरी जांच की अवधि में वृद्धि हुई है जो शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि का स्पष्ट संकेतक है।
 - प्रयोक्ताओं ने स्वयं ही पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से आयातों के प्रति अपना झुकाव स्वीकार किया है। यह दर्शाता है कि शुल्क हटाने के बाद आयातों में काफी वृद्धि होगी।
 - संबद्ध देशों में क्षमता लगभग *** लाख मी. टन की है जबकि क्षमता का लगभग केवल 45 प्रतिशत ही पूरा करने के लिए मांग पर्याप्त है, यदि संबद्ध देशों में निर्यातकों को *** मिलियन मी. टन की सीमा तक स्वतंत्र रूप से भारी निर्यात योग्य क्षमताओं के साथ छोड़ा जाए।
 - वस्तुतः संबद्ध देशों में लगभग 20 प्रतिशत क्षमताएं बेकार रहीं। यहां तक कि यदि इन बेकार क्षमताओं का उपयोग किया जाए तो इसके परिणामस्वरूप संबद्ध आयात व्यापारी भारतीय बाजार के 40 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त हिस्से को ले लेंगे।
 - संबद्ध देशों में उत्पादक उनके निर्यात बाजारों पर भारी रूप से निर्भर हैं।
 - संबद्ध देशों में घरेलू मांग स्थिर है और अभी संभावना की पेशकश नहीं करते। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से निर्यातों में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों में उत्पादक वैकल्पिक बाजारों को देखने के लिए विवश होंगे।
 - संबद्ध देशों से, पीईटी को छोड़कर, निचले स्तर के उत्पादों के निर्यातों में गिरावट आई है जो यह दर्शाता है कि पीटीए के लिए घरेलू मांग में गिरावट आई होती।
 - भारत, यूरोपीय संघ और चीन जन. गण. संबद्ध सामानों से निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार हैं। तथापि, चीन जन. गण. एक ओर पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध निर्यातकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा और दूसरी ओर चीन जन. गण. में क्षमताएं बढ़ रही होंगी।

- xiv. इनडोरामा वेंचर्स ने जुलाई, 2018 में यूरोप में गैर प्रचालनात्मक संयंत्र को अपने हाथ में लिया था और 2017 में क्षमता भी बढ़ाई थी जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ में क्षमता 14 लाख मी. टन तक बढ़ गई है। यूरोपीय संघ का बाजार बंद होने से भारत निर्यातकों के लिए केवल अर्थक्षम बाजार के रूप में रहेगा।
- xv. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, भारत का कोरिया से 8 प्रतिशत और थाइलैंड से 21 प्रतिशत निर्यात है। इससे वह संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए शीर्ष 5 निर्यात लक्ष्य में आ जाता है।
- xvi. भारत थाइलैंड से *** प्रतिशत निर्यात के रूप में निर्यातकों के लिए कीमत आकर्षक बाजार है और कोरिया गणराज्य से *** प्रतिशत निर्यात भारत के लिए उससे कम कीमत पर है।
- xvii. अतः, भारत संबद्ध देशों में निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार बना रह जाएगा।
- xviii. सकारात्मक कीमत कटौती और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयातों से घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ अर्जित करने से रुका है, यह संभावना है कि आयातों से शुल्कों के अभाव में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास होगा।
- xix. इस तर्क के संबंध में कि वैश्विक मांग आपूर्ति स्थिति संतुलित है, इस बात पर जोर दिया गया था कि संबद्ध सामानों के संबंध में 15-20 प्रतिशत तक वैश्विक अधिशेष है।
- xx. यद्यपि, संबद्ध सामानों के लिए क्षमता 19,601 हजार मी. टन तक बढ़ने का अनुमान है, तथापि, मांग केवल 13,941 मी. टन तक बढ़ने का अनुमान है जिससे वैश्विक अधिशेष बनेगा।
- xxi. ऐसी स्थिति में जहां प्रयोक्ता स्वीकार्य रूप से निर्यात आवश्यकताओं के लिए आयात कर रहे हैं, वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा शुल्क बंद होने की स्थिति में आयात करेंगे।
- xxii. इस तर्क के संबंध में कि भारतीय उद्योग में 5 वर्षों में अतिरिक्त क्षमता होगी, यह अनुरोध किया गया था कि वह वर्तमान स्तर अथवा निकट भविष्य में शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संभावित परिदृश्य पर कोई प्रकाश नहीं डालता।
- xxiii. चूंकि, निर्णायक समीक्षा का प्रयोजन यह मूल्यांकन करना है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संभावित है, कीमत कटौती शुल्क को छोड़कर पहुँच कीमत के आधार पर परिकलित की जानी चाहिए।
- xxiv. शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें नहीं घटाता तो आयातों के उसके बाजार हिस्से को लेने की संभावना है। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग का उत्पादन आरआईएल की कैप्टिव क्षमता की सीमा के सिवाय पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को निर्धारित लागत के रूप में काफी हानियां होने की संभावना है।
- xxv. वैकल्पिक रूप में यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें घटाता है तो उसकी लाभप्रदता बहुत ज्यादा कम होने की संभावना है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

97. पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है और पाटनरोधी शुल्क ने अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है क्योंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा लिए जा रहे कीमत संबंधी शक्ति का मानदंड यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास की कोई संभावना नहीं है।
- iii. इस तर्क के लिए कोई आधार नहीं है कि संबद्ध देशों के निचले स्तर के उत्पादों पर अन्य देशों द्वारा शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों में पीटीए के लिए मांग कम होगी क्योंकि भारत के विरुद्ध भारत से निर्यातों के लिए पीटीए के निचले स्तर के उत्पादों पर शुल्कों से घरेलू मांग में कोई गिरावट नहीं आई।
- iv. संबद्ध सामानों के लिए अनुमानित वैश्विक मांग अगले पांच वर्षों में 15.58 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप 15.53 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। क्षमता 19 प्रतिशत तक बढ़ेगी। 80-85 प्रतिशत क्षमता उपयोग को उपयुक्त रूप से आसान तथा पीटीए में उपयोग की विद्यमान दर के रूप में देखा जाना चाहिए। बुड मेकंजी के आंकड़े विश्व में अत्यधिक संतुलित मांग आपूर्ति स्थिति दर्शाते हैं।
- v. संबद्ध देशों में क्षमता तथा क्षमता उपयोग मांग में थोड़ी सी वृद्धि के साथ समान रहने की आशा है।
- vi. संबद्ध देशों में क्षमता घरेलू मांग से अधिक होने के बावजूद कोई मांग और क्षमता असंतुलन नहीं है तथा यदि भारत पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करता है तो कोई बेकार क्षमता सक्रिय नहीं होती है।

- vii. थाइलैंड से निर्यातों में गिरावट थाइलैंड में निचले स्तर के एक यूनिट की कठिनाई को दूर करने तथा पीटीए का इस्तेमाल करने वाले एक नए पॉलीस्टर संयंत्र के कारण है।
- viii. संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमता सही नहीं है क्योंकि 2014 में भारत में आयात 3 से 6 लाख मी. टन के घेरे में थे। यदि 16.61 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता होती तो भारत में आयात बहुत अधिक होते।
- ix. संबद्ध देशों से भारत में पीटीए के निर्यातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जब चीन ने वर्ष 2010 में संबद्ध देशों से पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया।
- x. यह दावा कि यूरोपीय संघ में नई क्षमताओं से संबद्ध देशों से यूरोपीय संघ को पीटीए के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा जिससे भारत को अधिक निर्यात होंगे, केवल एक आरोप है। संबद्ध देशों में निर्यातक बहुत उच्च स्तरों पर प्रचालन कर रहे हैं और बाजार की हानि की कोई आसन्न स्थिति नहीं है क्योंकि समग्र विश्व मांग आपूर्ति अच्छी तरह संतुलित है तथा पूरे विश्व में पीटीए के उत्पादक अच्छा काम कर रहे हैं।
- xi. भारत में क्षमता, उत्पादन और मांग में काफी वृद्धि होने की आशा है और इसमें 5 वर्षों में 11 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता होगी जो वैश्विक औसत से अधिक है।
- xii. भारत में पीटीए के लिए स्थिर बाजार है और मांग को संचालित करने वाले कई कारक हैं। भारतीय वस्त्र बाजार का आकार जो 2015-16 में 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 2024-25 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की आशा है।
- xiii. चूंकि भारत में निचले स्तर का उद्योग काफी बढ़ने की संभावना है, अतः उसके लिए आयात आवश्यक होंगे, परंतु संतुलित मांग आपूर्ति अंतराल उचित कीमत सुनिश्चित करेगा।
- xiv. आयातित उत्पादों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं था, यदि उत्पाद घरेलू रूप से उपलब्ध हो और कीमत सही है।
- xv. प्रयोक्ताओं ने उल्लेख किया है कि वे घरेलू उद्योग से खरीद कर रहे हैं और किसी आयात स्रोत में जाना आयात के साथ जुड़े कमजोर अवसंरचना आदि जैसे कारणों से अर्थक्षम नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग का बाजार पर लगभग *** प्रतिशत नियंत्रण है, यहां तक कि जब शुल्क लागू नहीं थे। बाजार में पाटित आयातों पर बढ़ते हुए आयातों का कोई परिदृश्य नहीं था और आयात स्पष्ट रूप से आवश्यक हो गए थे और भारत में मांग आपूर्ति अंतराल के अनुपात में थे। यदि प्रयोक्ताओं ने पाटित कीमतों पर जोर दिया होता, जैसा कि आरोप लगाया गया है तो घरेलू उद्योग ने ऐसा भारी बाजार हिस्सा न बनाए रखा होता।
- xvii. संबद्ध देशों में कोई अधिशेष क्षमताएं नहीं हैं। हनवा जनरल केमिकल अपनी इष्टतम क्षमता पर प्रचालन कर रहा है और उसकी क्षमता विस्तार के लिए तत्काल कोई योजना नहीं है।
- xviii. याचिकाकर्ताओं द्वारा स्पष्ट किए गए अनुसार क्षमता में से घरेलू मांग घटाकर अधिशेष क्षमताओं की संकल्पना गलत और आधारहीन है।
- xix. ऐतिहासिक रूप से पाटित कीमतों पर तथाकथित रूप से आयातों की कुछ स्थिति का उल्लेख करने का कोई आधार नहीं है और आगे का समय आयातों में केवल गिरावट ही दर्शाएगा क्योंकि घरेलू मांग आपूर्ति अब संतुलित है।
- xx. जांच की अवधि के बाद आयातों में और गिरावट आई है।

द.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

98. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और नियम 23 में उल्लिखित अपेक्षाओं तथा हितवद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है। प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि की दर

99. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया है। यह पाया जाता है कि जब 2016-17 तक आयातों में गिरावट आई तो उनमें जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। यद्यपि, 2015-16 में 61 प्रतिशत तक और 2016-17 में 15 प्रतिशत तक कम आयातों में गिरावट आई, तथापि, जांच की अवधि में उनमें 74 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि की दर विशेष रूप से काफी है जब मांग में वृद्धि की दर से तुलना की जाए और यह विचार किया जाए कि पाटनरोधी शुल्क लागू है।

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%		(-) 61%	(-) 15%	74%
मांग (कैप्टिव सहित)	मी. टन	***	***	***	***
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%		9%	4%	9%

ख. संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमताएं और अन्य निर्यात बाजारों की अतिरिक्त क्षमताएं देने की क्षमता

100. प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में, प्राधिकारी ने देश के सफल उत्पादक, कंपनी के उत्पादक, घरेलू बाजार में अन्य उत्पादकों की बिक्री, घरेलू बाजार में कुल बिक्री, देश में आयात, देश में कुल मांग, भारत में कंपनी के निर्यात, भारत को छोड़कर अन्य देशों को कंपनी के निर्यात, भारत में अन्य उत्पादकों के निर्यात, भारत को छोड़कर अन्य देशों को अन्य उत्पादकों के निर्यात के संबंध में प्रत्येक निर्यातक से सूचना मांगी। तथापि, थाइलैंड से निर्यातकों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी, कोरिया से उत्तरदाता निर्यातकों ने विरोधाभासी आंकड़े दिए हैं और वह भी आंकड़ों के किसी स्रोत के उल्लेख किए बिना। अतः प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अन्य संगत सूचना तथा घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास किया है जिसे हितबद्ध पक्षकारों को उनकी प्रति-टिप्पणियों के लिए प्रकट भी किया गया था।
101. संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए वर्ष 2017 के लिए पीसीआई वुड मैकेंजी के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

'000 मी. टन में मात्राएं

विवरण	कोरिया गणराज्य	थाइलैंड	संबद्ध देश
उत्पादकों की क्षमताएं	5,705	2,740	8,445
घरेलू मांग	2,619	1,262	3,881
अधिशेष क्षमताएं	3,086	1,478	4,564
संबद्ध देशों से निर्यात	1,940	963	2,903
आदर्श क्षमताएं	1,146	515	1,661

स्रोत – पीसीआई वुड मैकेंजी

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में निर्यातकों की 16.61 लाख मी. टन की बेकार क्षमताएं हैं।

ग. घरेलू उद्योग की कीमतों पर संभावित न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती सकारात्मक है और बाजार में सख्त प्रतिस्पर्धा दर्शाते हुए निम्न स्तरों पर है। घरेलू उद्योग की निवेश पर आय कम है। इस प्रकार जो यह दर्शा रही है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें उस स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है जहां वह उपयुक्त आय अर्जित कर सकता था। यह तथ्य बताते हैं कि आयातों से पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

घ. वर्तमान मार्जिन का स्तर

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी था जिससे शुल्क लगाए गए। पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से आयातों के लिए वर्तमान समीक्षा में सकारात्मक बना हुआ है।

ङ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

105. प्राधिकारी ने उस कीमत की जांच की जिस पर सामान भारत को तथा शेष विश्व को निर्यात किए गए थे। उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की जांच भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर शेष विश्व को उनके निर्यातों की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। सीमा शुल्क आंकड़ों पर विचार करते हुए औसत आधार पर यह देखा जाता है कि कोरिया से *** प्रतिशत अथवा *** मी. टन निर्यात भारत में उन कीमतों पर किए जाते हैं जो भारत

में कीमतों से कम हैं। थाइलैंड के मामले में तीसरे देशों के *** प्रतिशत अथवा *** मी. टन निर्यात भारत की कीमत से कम कीमत पर रखे गए हैं। भारत में निर्यात से कम कीमत पर तीसरे देशों के निर्यातों की मात्रा के संबंध में उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित है:

विवरण	टेकवांग	हनवा	कुल
सकल निर्यात	***	***	***
भारत को निर्यात	***	***	***
भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात	***	***	***
तीसरे देशों को कुल निर्यातों के प्रतिशत के रूप में भारत को कीमत से कम कीमतों पर निर्यात	***	***	***
तीसरे देशों को कुल निर्यातों के प्रतिशत के रूप में भारत को कीमत से कम कीमतों पर निर्यात (रेंज)	60-70%	65-75%	65-75%

106. यह देखा जाता है कि उत्तरदाता निर्यातकों के भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर शेष विश्व को काफी निर्यात है जिनके पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत में जाने की संभावना है।

द.4 पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना संबंधी निष्कर्ष

107. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन के काफी बड़ी हुई मात्रा में जारी रहने की संभावना है तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने की संभावना है। यहां तक कि जांच की वर्तमान अवधि के दौरान भी आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही थी और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय कम है। शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में आयातों के कारण कीमतों तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल रूप से और प्रभाव पड़ने की संभावना है। विदेशी उत्पादकों के पास काफी अधिशेष क्षमताएं हैं। भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा काफी है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है।

घ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

108. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच के दौरान पहले ही उठा दिए गए हैं और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

109. घरेलू उद्योग ने एचटीसी के उत्तर को रद्द करने, घरेलू उद्योग को क्षति, पाटन और क्षति के जारी रहने तथा प्रयोक्ता उद्योग की अत्यधिक लाभप्रदता की संभावना के संबंध में अपने अनुरोध दोहराए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- चूंकि वित्त मंत्रालय प्राधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तीन माह तक का समय दे सकता है, अतः प्राधिकारी कम से कम तीन माह के लिए शुल्क बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध करे।
 - पीईटी रेसिन, पीएसएफ, पीईटी फिल्म और फिलामेंट यार्ड की कीमतें व्यावहारिक रूप से पीटीए की कीमतों के बीच चली गई। वस्त्र उद्योग की कठिनाईयां चीन जन. गण. से आयातों में उछाल, कम सेवा शुल्क, जीएसटी में लगाया गया शुल्क ढांचा, अधिक क्षमताओं जैसे अन्य कारकों से संबद्ध है।
 - शुल्कों के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा विरोध उनकी अपनी पीड़ा के कारण नहीं है बल्कि अपने थाई संबंधी उत्पादकों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए है।
 - चूंकि टेकवांग हनवा और सम नाम यथा तथ्यतः कंपनियों से संबद्ध है, अतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण तीनों कंपनियों की प्रतिभागिता के बिना नहीं किया जा सकता। किसी भी दशा में चूंकि हनवा में पीएक्स की आपूर्ति टेकवांग को की है, अतः टेकवांग के लिए उत्पादन लागत का निर्धारण हनवा और टेकवांग

के बीच पीएक्स की अंतरण कीमत के संबंध में किसी सूचना के बिना नहीं किया जा सकता। उत्पादन और निर्यातों के संबंध में हनवा, सम नाम और टेकवांग के बीच एक करार है जिसे प्राधिकारी को प्रकट नहीं किया गया है।

- v. टेकवांग को उसके पीटीए प्रचालनों में हानि हुई है।
- vi. चूंकि, हनवा के पास कैप्टिव कच्ची सामग्री है, अतः टेकवांग की उत्पादन लागत हनवा की उत्पादन लागत से कम नहीं हो सकती।
- vii. मैसर्स पोसको देवू द्वारा प्रतिभागिता न किए जाने के मद्देनजर, निर्यात कीमत का निर्धारण प्रतिकूल उपलब्ध तथ्य पर विचार करके किया जाए।
- viii. उत्तरदाता उत्पादकों ने बीजक के बाद की छूटों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया है, यहां तक कि यद्यपि आयातकों ने उसे स्वीकार किया है।
- ix. एचटीसी ने इस तथ्य को छिपाया है कि उसकी संबद्ध कंपनी ह्योसंग केमिकल कारपोरेशन का कोरिया गणराज्य में पीटीए के उत्पादन के लिए एक संयंत्र है।
- x. आईआरएसएल व्यापार सूचना 9/2018 के तहत "संबद्ध" की परिभाषा के अनुसार आईआरपीएल और टीपीटी से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, इंडोरमा वेंचर्स ने जांच के बाद की अवधि में आईआरएसएल में 31.79 प्रतिशत का दावा अधिग्रहीत किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य संबद्ध आयातक आईडीपीआईपीएल ने पूर्ण उत्तर दायर किया है।
- xi. कीमत कटौती इस तथ्य के बावजूद सकारात्मक है कि घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर और उन कीमतों पर जो पर्याप्त रूप से लाभप्रद हैं, अपने सामानों की बिक्री कर रहा है।
- xii. क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध-III के पैरा (3) के अनुसार, जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- xiii. चूंकि, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कारणात्मक संपर्क जांच की अवधि के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं, अतः जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।
- xiv. चूंकि टेकवांग ने भारत के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक पाटन मार्जिन पर काफी मात्रा में निर्यात किया है, अतः टेकवांग पर मौजूदा शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है। अन्य निर्यातकों के लिए शुल्क में संशोधन तथा वृद्धि की आवश्यकता है क्योंकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन बढ़ गए हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

110. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के अभाव के संबंध में अपने पूर्व अनुरोधों को दोहराने के अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. टेकवांग द्वारा उत्पादित सामान तीन विभिन्न प्रकार की पैकिंग में बेचे जाते हैं। निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए मानी गई पैकिंग लागत उस लागत से भिन्न है जिसका टेकवांग ने दावा किया है। पैकिंग लागत की विस्तृत वर्किंग नहीं दी गई है।
- ii. समायोजित पत्तन एवं संबंधित व्यय टेकवांग द्वारा दावा किए गए अनुसार नहीं है और दावे को रद्द करने के लिए कोई वर्किंग अथवा कारण नहीं दिए गए हैं।
- iii. चूंकि, टेकवांग ने एफओबी आधार पर भारत को अधिकतर निर्यात किए हैं, अतः समुद्री भाड़ा और बीमा सभी लेन-देनों पर आबंटित नहीं किए जा सकते। भारत को निर्यातों के संबंध में कोई कमीशन अथवा वारंटी व्यय नहीं दिया गया है। बैंक प्रभार लेन-देन आधार पर दिए गए हैं।
- iv. टेकवांग द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत स्वीकार नहीं की गई है। जिन कारकों में संशोधन किया गया है, उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- v. कीमत आकर्षकता का विश्लेषण उपयुक्त नहीं है क्योंकि जांच की अवधि के लिए औसत कीमत की तुलना लेन-देन वार निर्यातों से की गई है जबकि इस अवधि के दौरान कीमत में उतार-चढ़ाव आया है।
- vi. हनवा ने माह वार उत्पादन लागत दी है। चूंकि, प्राधिकारी द्वारा माह वार उत्पादन के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया था, अतः हनवा को अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में काफी अंतर दर्शाने के लिए कोई अवसर नहीं था। उच्चतम और कम उत्पादन लागत के बीच 14 प्रतिशत का अंतर है।
- vii. प्राधिकारी ने पूर्व जांच में भी माह वार विश्लेषण किया था।
- viii. प्राधिकारी ने समग्र रूप से ह्योसंग कारपोरेशन के लिए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय को समग्र रूप से लिया है जो कि व्यापार प्रभाग के लिए इनसे अधिक है जो बाद में एचटीसी के रूप में अलग हो गई थी। चूंकि

- ह्योसंग कारपोरेशन एक बहु उत्पाद कंपनी है, अतः कुल बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों पर विचार नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक रूप से प्राधिकारी संबद्ध देश के दूसरे उत्पादक के बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों पर विचार कर सकते हैं।
- ix. किसी असंबद्ध व्यापारी के बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को लागू करना धारा 9क(ख) के अनुसार उपयुक्त आधार नहीं है और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई परिपाटियों तथा डब्ल्यूटीओ की न्याय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
 - x. आईआरपीएल और टीपीटी ने निर्यातक प्रश्नावली का भाग-II दायर नहीं किया है, जैसा कि यह व्यापार सूचनाओं तथा डीजीटीआर की वेबसाइट के तहत निर्धारित नहीं है। प्रश्नावली का भाग-II वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। व्यापार सूचना 5/2018 में, जो सभी पूर्व अनुदेशों तथा इस मुद्दे से संबंधित व्यापार सूचनाओं को रद्द करता है, भाग-II निर्धारित नहीं करता।
 - xi. आईआरपीएल और टीपीटी ने सुनवाई के बाद अपने अनुरोधों में भाग-II दायर न करने के कारण स्पष्ट किए थे जिन पर विचार नहीं किया गया है।
 - xii. प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ के अनुबंध-II के विरोध में कार्य किया है क्योंकि न तो उन्होंने प्रश्नावली का भाग-II जारी किया और न ही यह उल्लेख किया कि वह सूचना दायर थी। प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों का सहारा नहीं ले पाए जब उन्होंने पैनल और अपीलीय निकाय के जांच परिणामों के अनुरूप प्रश्नगत पक्षकार से संगत सूचना के लिए स्पष्ट रूप से अनुरोध नहीं किया।
 - xiii. यद्यपि आईआरपीएल और टीपीटी के उत्तरों को रद्द कर दिया गया है, तथापि कोरिया के निर्यातकों के उत्तर विसंगतियों एवं एक निर्यातक के असहयोग के बावजूद स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, टेकवांग के आंकड़ों में विसंगतियां नोट की गई थीं, परंतु उत्तर को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि घरेलू उद्योग ने प्रपत्र ज निर्धारित प्रपत्र में दायर नहीं किया था, परंतु उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
 - xiv. चूंकि भाग-II में संभावना के संबंध में सूचना होती है, अतः प्राधिकारी संभावना संबंधी विश्लेषण के संबंध में केवल आईआरपीएल और टीपीटी के लिए उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग कर सकते थे। भाग-II वर्तमान पाटन एवं क्षति के निर्धारण के लिए संगत नहीं है।
 - xv. आईआरपीएल और टीपीटी के उत्तरों को रद्द करना अनौचित्यपूर्ण है क्योंकि तालिका अध्ययन के प्रयोजन के लिए रिकार्ड हेतु मांगे गए पत्र में किसी विसंगति का उल्लेख नहीं किया गया था।
 - xvi. ऐसी कई निर्णायक समीक्षाएं हैं जिनमें निर्यातकों को प्रश्नावली के किसी भाग को दायर किए बिना अलग पाटन मार्जिन की अनुमति दी गई है। चूंकि प्रश्नावली वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, अतः यदि प्राधिकारी संभावना के संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना चाहते हैं तो वे मामला विशेष के आधार पर उसे जारी करते हैं।
 - xvii. उत्तरों को रद्द करने के बाद थाइलैंड के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक बढ़ाए गए और स्वैच्छिक हैं।
 - xviii. जांच की अवधि के बाद आयातों में गिरावट आई है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से सिद्ध है। तथापि, उस पर विचार नहीं किया गया है। आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में गिरावट आई है।
 - xix. बाजार में अनुचित कीमत प्रतिस्पर्द्धा दर्शाने के लिए कुछ नहीं है जबकि घरेलू उद्योग सभी आयातों को रोकना चाहता है।
 - xx. यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त आय के रूप में किस पर विचार नहीं किया गया है। भारत में पीटीए का घरेलू उद्योग अच्छा मार्जिन दे रहा है।
 - xxi. वर्तमान मामले में, कोई वर्तमान क्षति नहीं है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पाया गया है। यह तथ्य कि पाटित आयातों की मौजूदगी के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी सुधार हुआ है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
 - xxii. चूंकि, पाटनरोधी जांच अनुचित कीमत व्यवहार को हल करने के लिए है, अतः प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि क्या घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में एकाधिकारी की स्थिति बनाने के लिए कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है।
 - xxiii. यह तथ्य कि आयातों की पहुँच कीमत कम है, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों पर प्रीमियम प्राप्त करता है।
 - xxiv. अधिशेष क्षमताओं के संबंध में, प्राधिकारी की टिप्पणियों में कमी है, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से विश्व भर में इष्टतम क्षमता उपयोग वर्तमान स्तर पर रहे हैं।

- xxv. प्राधिकारी के ये जांच परिणाम कि पाटन और क्षति जारी रहेगी, दोषपूर्ण हैं क्योंकि विभिन्न पहलुओं और अपीलीय निकायों के निर्णयों में यह माना गया है कि संभावना की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि कुछ सुदूर संभावनाओं के आधार पर।
- xxvi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ज अपूर्ण है।
- xxvii. प्रयोक्ताओं ने अपनी लिखित अनुरोधों में अपनी चिंताओं को बताया था और प्रस्तुत किया था कि पीटीए का पीएसएफ, एफडीवाई, पीओवाई और पॉलीस्टर चिप्स की उत्पादन लागत का 55-75 प्रतिशत है। प्रयोक्ताओं ने यह भी अनुरोध किया था कि घरेलू उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय पीटीए कीमतों पर अतिरिक्त प्रीमियम लगा रहे हैं। प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों को उपयुक्त रूप से हल नहीं किया गया है।
- xxviii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार किया है कि निचले स्तर के प्रयोक्ता फैल रहे हैं। तथापि, इस साक्ष्य को प्रकटन विवरण का भाग नहीं बनाया गया है।
- xxix. अगले पांच वर्षों में मांग एवं आपूर्ति दर्शाते हुए उत्तरदाताओं द्वारा जोड़े गए साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया है और इसके बजाए 2017 के आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- xxx. आयात बहुत नगण्य थे और बाजार में सामग्री की कमी के मात्रा तक थे, प्राधिकारी द्वारा इसे हल नहीं किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 111. जहां तक टेकवांग और एचटीसी द्वारा दायर उत्तरों के संबंध में, घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उचित जांच के बाद और समस्त सूचना के सत्यापन के बाद पक्षकारों के उत्तरों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार किया है।
- 112. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एचटीसी जांच की अवधि के दौरान मौजूद नहीं, था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ह्योसंग कारपोरेशन के बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों पर उचित सत्यापन के बाद निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।
- 113. इस दावे के संबंध में कि क्षति रहित कीमत उपयुक्त रूप से निर्धारित नहीं की गई है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षति रहित कीमत निर्धारित की है।
- 114. टेकवांग ने सूचित किया कि पैकिंग का केवल एक स्वरूप घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में प्रयुक्त किया गया था जबकि सामग्री का निर्यात पैकिंग के तीन विभिन्न स्वरूपों में किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने किए गए कुल पैकिंग व्यय का समाधान नहीं किया और पैकिंग के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में तीसरे देशों को निर्यातों तथा भारत को निर्यातों के संबंध में अलग-अलग किए गए व्ययों में बहियों में सूचित किया। इस प्रकार, निर्यातक ने अपनी लेखा बहियों में पर्याप्त रूप से और पूर्ण रूप से व्यय को पैकिंग के विभिन्न स्वरूपों तथा विभिन्न बाजारों के लिए अभिज्ञात नहीं किया। अतः प्राधिकारी के लिए विभिन्न बाजारों के लिए तथा विभिन्न लदानों के लिए पैकिंग के विभिन्न स्वरूपों का सह-संबंध बनाना संभव नहीं था। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा उसकी लेखा बहियों में सूचित कुल पैकिंग व्यय तथा पैक की गई एवं बेची गई सामग्री की मात्रा पर विचार किया है। पैकिंग लागत का निर्धारण कंपनी द्वारा की गई औसत पैकिंग लागत के आधार पर किया गया है।
- 115. जहां तक पत्तन एवं संबंधित व्ययों के निमित्त कीमत समायोजनों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने परिशिष्ट-5, 7, 8 और 9 में बिक्री एवं वितरण व्यय सूचित किए हैं। तथापि, यह देखा जाता है कि इन व्ययों का एक-दूसरे के साथ विधिवत रूप से पुनर्समाधान नहीं किया गया है। इस प्रकार, निर्यातक ने बाजार विशेष के लिए किए गए इन खर्चों को स्पष्ट रूप से अभिज्ञात नहीं किया है और उनका लेखा बहियों में सह संबंध नहीं बनाया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी इस निमित्त कंपनी द्वारा किए गए सभी व्ययों को लेना और उन्हें किए गए कुल निर्यातों का भाग बनाना उपयुक्त मानते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इस निमित्त व्यय बाजार पर निर्भर रहते हुए भिन्न क्यों होंगे। निर्यातक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि एफओबी स्तर तक भी व्यय विभिन्न देशों को किए गए निर्यातों के संबंध में भिन्न क्यों नहीं होंगे।

116. समुद्री भाड़ा और बीमा व्यय वास्तविक आधार पर समायोजित किए गए हैं, जैसा कि टेकवांग द्वारा दावा किया गया है।
117. यद्यपि टेकवांग ने यह उल्लेख किया है कि निर्यातक द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया गया है, तथापि घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि श्री रोहित दत्ता मैसर्स केमसिंथ, 25-ए, पॉकेट एफ, मयूर विहार, फेज-II, दिल्ली-110091 कंपनी के लिए कार्य करने वाला एजेंट है और उत्पाद की बिक्री में कंपनी की सहायता कर रहा है। तथापि, प्राधिकारी इतने विलंब के स्तर पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे का संज्ञान नहीं ले सकते।
118. जहां तक उत्पादन लागत को रद्द करने का संबंध है, प्राधिकारी ने विनिर्माण लागत के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए सभी दावों को स्वीकार किया है। अंतर केवल निर्यातक द्वारा दावा की गई बिक्री एवं वितरण लागत के संबंध में है।
119. जहां तक कीमत आकर्षकता का संबंध है, प्राधिकारी ने निर्यातक के अपने दावों पर विचार किया है और भारत में उसकी निर्यात कीमत की तुलना शेष विश्व में निर्यात कीमत से की है। इसके अतिरिक्त, उन स्थितियों में जहां शेष विश्व को निर्यात कीमत भारत में निर्यात कीमत से कम है, निर्यातकों/विदेशी उत्पादकों द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि वे लदान शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में क्यों भेजे जाएंगे।
120. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि हनवा ने माह-वार उत्पादन लागत के ब्यौरे दिए हैं और यह कि इस प्रकार वार्षिक आधार पर तुलना का औचित्य बनाकर उसमें अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में ऐसे विश्लेषण की आवश्यकता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती।
121. जहां तक सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के संबंध में इस तर्क का संबंध है और यह तर्क कि उसमें विनिर्माण एवं व्यापार क्रियाकलाप के लिए व्यय शामिल हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसकी अपनी प्रकृति से विनिर्माण व्यय विनिर्मित सामानों की लागत में शामिल किए गए हैं। उनकी अपनी प्रकृति से बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय विनिर्माण अथवा व्यापार तक सीमित नहीं हैं। अतः इन व्ययों को कंपनी के समग्र कारोबार के आधार पर भाग बनाया जाना उपयुक्त है। यह भी नोट किया जाता है कि जहां तक कि यदि बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय पर विचार किया जाए, जैसे कि निर्यातक द्वारा दावा किया गया है, तो पाटन मार्जिन मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक होता है।
122. जहां तक असंबद्ध व्यापारिक कंपनी के बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय को शामिल करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि व्यापारी हानि पर बिक्री कर रहा है, अतः इस हानि को उत्पादक की कारखानागत निर्यात कीमत पर समायोजित करना अथवा उस निर्यात कीमत से एसजीए को कम करना उपयुक्त है, जिस पर व्यापारी संबद्ध सामानों की बिक्री करता है।
123. आईआरपीएल और टीपीटी का यह तर्क कि उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली का भाग-II दायर नहीं किया है क्योंकि वह व्यापारी सूचना 5/2018 के तहत निर्धारित नहीं है, जो उत्पादक/निर्यातकों द्वारा दी जाने वाली सूचना के संबंध में पूर्व के सभी अनुदेशों को रद्द करती है, गलत है क्योंकि (क) अन्य निर्यातकों ने वह दायर है, (ख) घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और (ग) प्राधिकारी द्वारा इन निर्यातकों सहित सभी ज्ञात निर्यातकों को इस आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया तथा उसका एक वेब लिंक भी दिया गया था। निर्यातक ने उल्लेख किया है कि यद्यपि प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र में वेब लिंक दिया गया था, तथापि वह खुल नहीं रहा था और पक्षकार उपर्युक्तानुसार व्यापार सूचना में गए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस मामले में निर्यातक को यह मानने के बजाए आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए निदेशालय से संपर्क करना चाहिए था कि निर्यातक प्रश्नावली के भाग-II से संबंधित सूचना आवश्यक नहीं थी। यह भी नोट किया जाता है कि लिंक निर्यातक के कानूनी प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला गया था जब उसने प्रकटन जारी करने के बाद बैठक में मांग की। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातक प्रश्नावली के भाग-II की मांग करने वाले निर्यातक को विशेष पत्र किसी भी दशा में भेजा जाना चाहिए था।
124. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पूरक प्रश्नावली अथवा कमी वाला पत्र जारी किया जा सकता था, यह नोट किया जाता है कि कमी वाला पत्र जारी करने का प्रश्न केवल तभी उठता है, जब पक्षकार निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली का उत्तर दायर करे। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां पक्षकार ने खुद ही प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, कमियां उठाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। यह भी नोट किया जाता है कि इस संबंध में पूर्व जांचों एवं निर्धारणों का संदर्भ देना अनुपयुक्त है।

125. जहां तक अन्य कोरियाई उत्पादकों के प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार करने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोरियाई उत्पादकों ने तीसरे देशों को अपने निर्यातों के पूरे ब्यौरे दिए हैं।
126. आईआरपीएल और टीपीटी ने यह भी अनुरोध किया है कि संगत व्यापार सूचना अथवा डीजीटीआर की वेबसाइट में प्रश्नावली के भाग-II के रूप में निर्णायक समीक्षा जांच में कोई अतिरिक्त अनुबंध प्रस्तुत किया जाना निर्धारित नहीं था और यह कि आज भी डीजीटीआर की वेबसाइट पर ऐसी कोई प्रश्नावली उपलब्ध नहीं है। इस मामले की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और यह पाया गया था कि यद्यपि प्रश्नावली के भाग-II को वेबसाइट पर अद्यतन करने का कार्य गलती से बाद में निदेशालय की वेबसाइट से हटा लिया गया था। यद्यपि यह स्पष्टीकरण निर्यातक द्वारा उत्तर दायर न करने का औचित्य नहीं बनाता, तथापि, निर्यातक द्वारा व्यक्त व्यावहारिक कठिनाई पर विचार करते हुए प्राधिकारी थाई निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर और अनुरोधों की जांच करना उपयुक्त मानते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इन निर्यातकों ने अपनी प्रकटन पश्चात टिप्पणी में खुद ही यह माना है कि प्राधिकारी संभावना विश्लेषण के संबंध में उनके विरुद्ध उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों को लागू कर सकते थे। यह भी नोट किया जाता है कि इस प्रकटन विवरण पर विवाद करते हुए निर्यातक ने पाटन की संभावना न होना भी नहीं दर्शाया है। इसके विपरीत यह देखा जाता है कि इन दोनों थाईलैंड के निर्यातकों द्वारा स्वीकार किये गये पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा (आईआरपीएल के मामले में *** प्रतिशत अर्थात् *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन और टीपीटी के मामले में *** प्रतिशत अर्थात् *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन) से काफी अधिक है। तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन थाई निर्यातकों से पाटन जारी है और पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
127. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई क्षति संबंधी सूचना का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित पूरी संगत सूचना दी है। वस्तुतः प्रकटन विवरण में उसका विस्तृत विश्लेषण निहित है।
128. जहां तक थाईलैंड के मामले में निर्धारित पाटन मार्जिन का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने एसजीए तथा उपयुक्त लाभ को जोड़ने के बाद उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। किसी भी दशा में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, थाई निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर भारत में उनके निर्यातों के संबंध में *** प्रतिशत और *** प्रतिशत पाटन मार्जिन दर्शाता है।
129. जहां तक जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में गिरावट का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात इसके विपरीत जांच की अवधि में 378,037 मी. टन से बढ़कर अप्रैल से सितंबर, 2018 तक छः माह में 408,862 मी. टन (वार्षिक) हो गए।
130. यह तर्क देते हुए कि कीमत कटौती ऐतिहासिक रूप से और वैश्विक रूप से समान स्तर पर रही है, हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी निजी क्षमता, उत्पादन, बिक्री, कीमत और लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर यह नहीं दर्शाया है कि पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में संभावित नहीं हैं।
131. इस तर्क के संबंध में कि संभावित निर्धारण सुदूर संभावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य पाटन एवं क्षति की संभावना न होना कैसे दर्शाता है।
132. यह नोट किया जाता है कि प्रपत्र ज में मांगे गए अनुसार वर्तमान जांच के संबंध में क्षति संबंधी सभी संगत सूचना और घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित सूचना प्राधिकारी के रिकार्ड में है।
133. जहां तक निचले उत्पाद की कुल उत्पादन लागत में पीटीए के हिस्से से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तरदाताओं ने उत्पादन लागत में पीटीए का अनुमानित हिस्सा ही दिया है और अपनी लागत में शुल्क का प्रभाव नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं ने वस्तुतः आयातक प्रश्नावली के उत्तर में निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना दायर न करना बेहतर माना है, जैसा कि यहां ऊपर नोट किया गया है। आयातक प्रश्नावली में विशेष रूप से आयातकों से यह अपेक्षा है कि वे उत्पाद के उपयोग और प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता जैसी संगत सूचना दें। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना कोई संगत अनुबंध प्रस्तुत न कर इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रोककर रखी गई है। साथ ही, घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि निचले उत्पादों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.21 प्रतिशत से 1.53 प्रतिशत की रेंज में होगा।
134. जहां तक अगले पांच वर्षों में मांग एवं आपूर्ति की स्थिति से संबंधित सूचना का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में क्षति की अवधि 31 मार्च, 2018 तक है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने इस संभावित सूचना के आधार पर संभावना का न होना सिद्ध नहीं किया है।

135. जांच की अवधि में आयातों की मात्रा नगण्य थी, जैसा कि तर्क दिया गया है। वस्तुतः नियमों में विशेष रूप से यह निर्धारित है कि 3 प्रतिशत से अधिक आयात की मात्रा को मूल जांचों के संदर्भ में काफी माना जाएगा। किसी भी दशा में वर्तमान अवधि में संबद्ध देशों से आयात भारत में व्यापारिक मांग के लगभग 10 प्रतिशत थे। चूंकि, वर्तमान जांच का प्रयोजन पाटन एवं क्षति की संभावना निर्धारित करना है, अतः हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह अपेक्षित था कि वे यह सिद्ध करें कि शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति होने की संभावना नहीं है। यद्यपि दो उत्पादकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर उनके तीसरे देश में निर्यात को दर्शाते हुए स्पष्ट रूप से पाटन के जारी रहने की संभावना दर्शाते हैं। तथापि, थाई उत्पादकों ने स्वीकार किया है कि प्राधिकारी इस संबंध में उपलब्ध तथ्यों को लागू कर सकते थे। प्रतिभागी उपभोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना अथवा साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में होने की संभावना नहीं है।
136. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग सभी आयातों को रोकना चाहता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान देश में व्यापारिक मांग के 13 प्रतिशत की पूर्ति उस समय भी आयातों द्वारा की गई थी।
137. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सतत परिपाटी के अनुसार क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय मानी है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक आय बहुत कम है।
138. यह तर्क कि वर्तमान में क्षति नहीं है और इसीलिए क्षति के बार-बार होने की संभावना नहीं है, कानूनी प्रावधानों को व्यक्त करने के विपरीत है। यह नोट किया जाता है कि क्षति के बार-बार होने की संभावना का प्रश्न केवल तभी उठता है जब निरंतर क्षति न हो। तथापि, वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में इष्टतम से कम रहा है।
139. जहां तक एकाधिकार की स्थिति बढ़ाने अथवा कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने से संबंधित तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे की जांच व्यापार उपचार जांच के क्षेत्र में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त, विवरण देने के सिवाय, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि देश में इस उत्पाद के तीन उत्पादक हैं और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग एकाधिकारिक स्थिति में हैं।
140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, सकारात्मक कीमत कटौती की मौजूदगी दर्शाता है।

न. निष्कर्ष

141. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन के बार-बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में पाटित आयातों पर आयात आने की संभावना है।
- ख. काफी पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, आयातों की काफी मात्रा, सकारात्मक कीमत कटौती, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर कम आय और निर्यातकों की सामूहिक एवं संचयी रूप से अधिशेष क्षमताओं जैसे मानदंड यह दर्शाते हैं कि शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग की स्थिति बिगड़ने की संभावना है।
- ग. घरेलू उद्योग के निष्पादन में हास संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण होने की संभावना है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- घ. घरेलू उद्योग ने खुद ही शुल्क लगाया जाना जारी रखने की मांग की है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का समान स्तर जारी रखना उपयुक्त है, जैसा कि मूल जांच में पहले लगाया गया था।

प. सिफारिशें

142. वर्तमान में लागू उपाय समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना की जांच करने पर और पूर्व निष्कर्षों के मद्देनजर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

संबद्ध सामान के सभी निर्यातों के संबंध में पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (8) में दर्शाए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हनवा जनरल केमिकल कं., लि.	ह्योसंग टीएनसी कारपोरेशन	27.32	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	टेकवांग इंडस्ट्रियल कं., लि.	टेकवांग इंडस्ट्रियल कं., लि.	23.61	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उपर्युक्त क्रम सं. 1 व 2 में उल्लिखित को छोड़कर कोई अन्य संयोजन		78.28	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
4.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	कोरिया गणराज्य	अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	78.28	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
5.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन देश को छोड़कर कोई अन्य देश	कोरिया गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	78.28	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
6.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	थाईलैंड	थाईलैंड	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	45.43	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
7.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	थाईलैंड	थाईलैंड	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कं. लि.	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक कं. लि.	45.43	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
8.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	थाईलैंड	थाईलैंड	उपर्युक्त क्रम सं. 6 व 7 में उल्लिखित को छोड़कर कोई अन्य संयोजन		62.55	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
9.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	थाईलैंड	अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	62.55	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
10.	29173600	प्यूरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड	पाटनरोधी शुल्क के	थाईलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	62.55	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

		एसिड	अध्यधीन देश को छोड़कर कोई अन्य देश						
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

फ. आगे की प्रक्रिया

143. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid, originating in or exported from Korea RP and Thailand

F. No. 7/36/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules”), thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

- Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), had issued preliminary findings vide notification No.14/7/2013-DGAD dated 19th June, 2014, recommending imposition of provisional anti-dumping duty against imports of Purified Terephthalic Acid (hereinafter referred to as PTA, the subject goods or product under consideration), originating in or exported from Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), which was imposed by Central Government vide Notification No. 36/2014 – Customs (ADD) dated 25th July, 2014.
- And whereas, the Authority issued final findings vide Notification No. No.14/7/2013-DGAD dated 7th April, 2015 recommending imposition of definitive anti-dumping duties against the imports of subject goods from subject countries. The definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 23/2015 – Customs (ADD) dated 27th May, 2015.
- And whereas, a petition was jointly filed by M/s Reliance Industries Limited and M/s MCPI Private Limited (hereinafter referred to as 'petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of sunset review of the anti-dumping duty in force against the subject imports and for extending the duties for a further period of five years. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation/recurrence of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.
- And whereas, in view of the duly substantiated application, filed by the domestic industry, the Authority in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, initiated the sunset review investigation vide Notification No. F.No. 7/36/2018-DGTR dated 31st October, 2018 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and Thailand, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 31st October, 2018 to the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as per available information. The known interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their views known in writing within the prescribed time-limit.
- ii. Copy of letter and questionnaire sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.
- iii. Copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants was made available to the known producers/exporters of the subject countries and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
- iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the SSR to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) and 6(4) of the Rules:
 - a. Hyosung Corporation, Korea RP
 - b. Taekwang Industrial Co., Ltd, Korea RP
 - c. Hanwha General Chemical Co., Ltd, Korea RP
 - d. Hyosung Petrochemical, Korea RP
 - e. Honam Petrochemical Corporation, Korea RP
 - f. Samnam Petrochemical Co., Ltd, Korea RP
 - g. SK Petrochemical, Korea RP
 - h. Lotte Chemical, Korea RP
 - i. Siam Mitsui PTA Co., Ltd., Thailand
 - j. Indorama Petrochem Limited, Thailand
 - k. TPT Petrochemicals Public Co. Ltd, Thailand
- v. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/ exporters from the subject countries responded by filing questionnaire response and making submissions:
 - a. Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP
 - b. Hyosung TNC Corporation, Korea RP
 - c. Hanwha General Chemical Co., Korea RP
 - d. Indorama Petrochem Limited, Thailand
 - e. TPT Petrochemicals Public Company Limited, Thailand
- vi. Questionnaire was sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules:
 - a. JBF Industries Limited
 - b. Alok Industries Limited
 - c. Bhilosa Industries Limited
 - d. Garden Silk Mills Limited
 - e. Gokulanand Petrofibres
 - f. DNH Spinners Private Limited
 - g. Filatex India Limited
 - h. Rashmi Polyfab Private Limited
 - i. Sumeet Industries
 - j. SRF Limited
 - k. Shubhalakshmi Polyesters Limited
 - l. Wellknown Polyester Limited
- vii. In response to the above, following importers/users filed importer questionnaire response and made submissions.

- a. Garden Silk Mills Limited
- b. Filatex India Limited
- c. Indo Rama Synthetics (India) Limited
- d. IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
- e. Sumeet Industries
- f. The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited
- viii. The following parties also made submissions during the course of this investigation:
 - a. Garden Silk Mills Limited
 - b. PTA Users Association
 - c. Confederation of Indian Textiles Industry
 - d. Indian Spinners' Association
 - e. The Southern Indian Mills' Association
- ix. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- x. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2014-15, 2015-16, 2016-17, and the period of investigation.
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.
- xii. Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The non-injurious price (NIP) has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure – III to the Anti-Dumping Rules.
- xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 29th April, 2019. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xiv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xv. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the disclosure on the basis of available facts.
- xvi. A Disclosure Statement was issued to interested parties on 18th June, 2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 25th June, 2019 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.
- xvii. ***represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.
- xviii. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 65.33 prevailing during the POI has been adopted by the Authority

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 6. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review is Purified Terephthalic Acid. In the original investigation, the product under consideration was defined as under:

“i. The product under consideration in the present investigation, as defined by the Authority in the initiation notification is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). The PUC is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is $C_6H_4(COOH)_2$. It sublimates at $402^\circ C$ and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textile, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. The product under consideration is classified under subheading 29173600 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.

ii. As claimed by the applicants, Di-Methyl Terephthalate (DMT) is chemically a different product and therefore not covered in the scope of the product under consideration.”

7. The Authority found that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. In view of the same, the subject goods produced by the domestic industry were treated as domestic like article to the product under consideration imported from subject countries.
8. None of the importers, consumers, exporters, domestic industry and other interested parties have raised any objection with regard to the scope of the product under consideration and like article. In view of the above the investigation conducted, information filed by various interested parties and information on record, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

9. The application has been filed by M/s Reliance Industries Limited and M/s MCPI Private Limited. There is one more producer of subject goods in India, namely Indian Oil Corporation Limited (IOCL).
10. The definition of domestic industry is provided under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, which reads as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

11. The petitioners constitute more than 90% of the Indian production. Further, the petitioners have not imported the subject goods and are not related to exporters or importers thereof. No submissions have been made by the exporters, importers, users or any other interested party with regard to the scope of the domestic industry. Having regard to the investigation conducted, information filed by various interested parties and information on record, the Authority holds that the petitioners constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by the domestic industry

12. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality –
 - i. The users have not provided any reason for claiming confidentiality.
 - ii. Publicly available information such as shareholding, annual reports, product specification has been claimed confidential by the exporters and users.
 - iii. Exporters have claimed even the names of producers and exporters as confidential, despite the fact that channel of distribution get inevitably mentioned in the duty table.

- iv. Even the names of producers and exporters through which goods have been exported has been claimed as confidential, despite the fact that such details are inevitably mentioned in the duty table.
- v. The exporters have not complied with the Trade Notice 10/2018.
- vi. The confidentiality claims of the domestic industry are consistent with the guidelines prescribed under Trade Notice 10/2018.
- vii. The information provided by the domestic industry was sufficient to allow the interested parties to defend its interests, as they were aware of the contentions of the domestic industry.
- viii. Formats A to L, which contain costing and pricing information of the domestic industry, are confidential by nature, and disclosure thereof would cause severe prejudice to the competitive interests of the domestic producers.
- ix. The data relating to productivity per day and employees cannot be disclosed in as much as the data relating to each company is not only confidential with respect to the other opposing parties, but also against each other.

E.2. Submissions by other interested parties

13. Following submissions have been made by other interested parties in this regard –

- i. The domestic industry has claimed all volume parameters as confidential, whereas the same were disclosed in the findings of the original investigation. The spirit of Trade Notice 10/2018 should not be violated by any party.
- ii. The actual extent of captive consumption is not disclosed to restrict the parties on commenting upon crucial volume parameters.
- iii. The domestic industry has removed rows for cash profit, average capital employed and PBIT as a percentage of capital employed from Format H, in contravention of the prescribed format. The incomplete Format H is certified as complete and authentic whereas it has been tampered and changed by the domestic industry. As a result, the opposing parties do not have information with regard to return on capital employed in actual or indexed form.
- iv. The non-confidential version of application does not allow a sufficient understanding of the information provided on a confidential basis. Significant data provided in the petition is not properly indexed and the justification table indicating reasons for confidentiality provided by the domestic industry is not as per requirements as per Trade Notice.
- v. In response to Section VI, the petitioners have not provided any information at all, but have referred Annexure 6.1, which have been claimed confidential. The costing information is crucial to understand the claims put forward by the petitioners, since a number of arguments referring to injury are based on these documents.
- vi. Indexed data on unit price, total costs, investments, employment and stock have not been explicitly provided and analyzed.
- vii. As per Trade Notice 10/2018, the aggregate data in case of number of employees and average data for productivity per day should have been disclosed, whereas the petitioners have provided the same in trend form.
- viii. The interested parties have claimed certain information confidential as permissible in Rule 7 and a proper reasoning for the same has been provided.
- ix. The domestic industry should be directed to adhere to Rule 7 and disclose essential details so that the opposing parties would get the chance to comment upon the petition effectively.

E.3 Examination by the Authority

14. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish

non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

15. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

16. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
 - i. Users' responses need to be rejected as none of the users has filed the relevant and some of the most critical information regarding details of imports, domestic purchases, consumption of product under consideration and profitability, rendering the questionnaire response an empty exercise.
 - ii. The users have not furnished their financial statements and other exhibits, rendering their response incomplete.
 - iii. Users have also failed to provide details of post invoicing/sales discounts, which casts a doubt on the accuracy of price reported in respect of imports.
 - iv. The users have also failed to provide other exhibits.
 - v. The users have resorted to harsh, accusatory and offensive language, and resorted to wild accusations and allegations to make up for the lack of evidence in support of their claims.
 - vi. The users have tried to cover up the fact that (a) the user industry across segment have been able to significantly improve their performance, whether it is a question of volumes or profits/margins, (b) the user industry across segment has expanded capacities, (c) PTA consumption grew by *** lakh MT over current injury period as opposed to *** lakh MT over previous injury period, (d) global consumption has increased during the corresponding period by much lesser proportion.
 - vii. In response to allegations in this regard, it was submitted that the present proceedings, being related to an anti-dumping investigation and not an investigation under the competition law, allegations of “monopolistic practices” or “abuse of dominant position” have absolutely no relevance to the investigation. There are a number of anti-dumping investigations having one or few producers.
 - viii. There are three producers of the subject goods in India itself, with another one expected to establish its plant soon. Therefore, even without imports, there cannot be any monopoly in the market.
 - ix. Even with the duties, the imports may continue, but at un-dumped prices, and therefore, there is no monopoly.
 - x. Countering the allegations of the respondents, it was urged that it must be borne in mind that the fair competition in the market is being destroyed by the imports, and not by the domestic industry.
 - xi. The data on record clearly shows that the domestic industry has not earned “monopolistic rent”, “supernormal profits” or a “very high return on capital employed”, as contended by the respondents. The very fact that the price undercutting is nominal shows that the domestic industry is selling the subject goods at an import parity price.
 - xii. In fact, the user industry have earned better returns than the domestic industry, as is evident from their financial statements, which shows that the domestic industry has not been abusing the alleged dominant position.
 - xiii. To cover up the fact that the duty has not impacted the user industry, the respondents have refrained from filing the information in the form and manner prescribed by the Designated Authority.
 - xiv. Responding to the allegation that the domestic industry was throttling the voice of the user industry, it is

- emphasized that the respondents have resorted to wild accusations only because they have been caught with glaring deficiencies.
- xv. The users have resorted to such language to distract the Designated Authority from the actual merits of the case and to malign the reputation of the domestic industry.
 - xvi. The users have withheld the information that would have proved fatal to their fallacious arguments that they have suffered as a result of imposition of duties.
 - xvii. Responding to the argument that associations of users form part of definition of interested party, it was submitted that the manner of participation of users is laid out under Rule 6(5) to (a) industrial users and (b) user associations when the product is sold at a retail level.
 - xviii. The exclusion of right of Association to participate in the investigation does not operate as a bar on right of users to participate and therefore, the users are not left remediless, as claimed by the users.
 - xix. If the yardstick of “direct or indirect impact of duties on the business” suggested by the respondents were to be considered, then it would lead to a very wide interpretation of the term “interested party” and it may imply that even commission agents, customs house agents, shipping lines, inland transporters, warehouses, etc. engaged in distribution of imported and domestic goods may also be treated as interested parties. Further, by that logic, even a consumer of bottled water made from PET resin or consumer buying garments from man-made fabric may also be treated as an interested party.
 - xx. With regard to the argument that the user associations are covered under the inclusive definition under Rule 2(c), it was submitted that the respondents cannot be allowed to read the provisions of Rule 2(c) in a manner that makes the provisions of Rule 6(5) redundant.
 - xxi. It is a settled principle of interpretation of law that if a special provision is made on a certain matter that matter is excluded from the general provision. Therefore, when a special provision has been made under Rule 6(5) for the manner in which the users may participate, the issue shall not be covered under the broader definition of an “interested party” under Rule 2(c).
 - xxii. As held by Tribunal in the case of Automotive Tyre Importers Association, a user association must establish itself as an interested party by demonstrating its credentials, which has not been done in the present case.
 - xxiii. Even when it is assumed that Rule 2(c) definition is an inclusive definition, those parties who have not been specified as interested party under Rule 2(c) need to seek the liberty from the Designated Authority for being treated as an interested party.
 - xxiv. The desire of the responding users for inclusion of the downstream industry appears to stem from the fact that since the present respondents and members of PTA Users Association have not suffered due to the duties in force, they are trying to create an illusion of further downstream users suffering.
 - xxv. The downstream industry of users, or association thereof is not an interested party as they not have a proximate interest in the levy of duties and the data to analyse their situations is not on record.
 - xxvi. The associations of downstream industries of spinning, etc. need not only demonstrate an interest, but also the interest must not be remote or negligible; but rather, the party must be able to show a significant impact of duties on its operations.
 - xxvii. Only such entities may be considered as “included” within the definition, as are of the same class or kind as those enumerated. Since the present definition relates only to producers, exporters, importers, etc. of product under consideration or like article; an entity that is a user of any other article cannot be considered within the scope of definition of interested party.
 - xxviii. As held by Tribunal in Merino Panel, it is incumbent upon a party to demonstrate itself to be an interested party by filing relevant information. No such information has been filed by associations.
 - xxix. In terms of the Initiation Notification, the interested parties are also required to intimate their nature of interest. Even, as per US Handbook, parties must state their reasons for participating in the investigation and only a person found by the Secretary to have a proper reason is permitted to appear as an interested party.
 - xxx. At the very least, association of further downstream users must show a proper reason for participation in that they must provide data to substantiate that they are, in fact, impacted by duties.
 - xxxi. The reliance on the FAQs by respondents was misplaced as it referred only to users of dumped product.
 - xxxii. Regarding the reference to decision in Bharat Solvent by users, it was highlighted that the decision made it

clear that the interest of the party must be real and proximate.

- xxxiii. The associations are also not eligible for the reason that their members are primarily dependent on cotton, and not on man-made fibres.
- xxxiv. Even if assuming that the users' downstream industry is suffering, then, the users should be blamed for the same.
- xxxv. Responding to the argument that the users were suffering, the domestic industry emphasized that the respondents have failed to show that (a) that they have suffered losses; and (b) that the losses arose as a result of imposition of duties.
- xxxvi. The respondents appear to believe that they have a right to unfair priced imports, and the step taken by Government towards establishment of fair competition in the market by imposing anti-dumping duty, has caused losses to them.
- xxxvii. Data furnished by the domestic industry shows that almost all users of the subject goods are running profitable business and in fact their profitability has shot up significantly over the period.
- xxxviii. For the users that are in losses, their annual reports itself show that the losses are attributable to reasons other than the anti-dumping duties in place.
- xxxix. Responding to the claims of stagnation of downstream industry, it was highlighted that many users Filatex India Limited, Chiripal Poly Films Limited, Shubhlakshmi Polysters Limited, Vacmet India Limited, Wellknown Polysters Limited, SRF Limited and Bhilosa Industries Limited have expanded capacity since the levy of duty.
- xl. Further, Filatex India Limited, Bhilosa Industries Limited, Ester Limited and Jindal Poly Films Limited are undertaking further capacity expansion, demonstrating that the user industry is not facing stagnation.
- xli. The respondents have themselves acknowledged that the downstream industry is growing multifold
- xl.ii. The users have also acknowledged in their annual reports that the margins of the downstream industry of PTA are growing.
- xl.iii. As regards the other industries engaged in spinning, knitting, processing and garments industry; the respondents have not adduced any evidence to show impact of duty on the cost of production of these industries.
- xl.iv. The impact of duties is only about Rs. 1.39 per kg with respect to a textured yarn of around Rs. 110 per kg. Likewise, in a saree of about Rs. 250, the impact of duties is only Rs. 0.56. The duties shall be about Rs. 0.31 in a shirt of about Rs. 146.
- xl.v. The growth potential of the textile industry underscores the importance of continued growth of the domestic industry to ensure that India remains self-sufficient.
- xl.vi. The imposition of duties can have no impact on the exports of textiles as the users can easily import the subject goods under advance license for the purpose of exports, without payment of duties.
- xl.vii. When the users have not been adversely impacted, losses or stagnancy of their downstream industry can only indicate two things – (a) either the users are profiteering and have not passed on the benefit of reduced prices to their consumers; or (b) the losses incurred by the downstream users are not on account of the duties in force.
- xl.viii. Contrary to the arguments of the respondents, the PCI Wood Mackenzie data shows that the consumption of polyesters has been increasing over the period, showing growth of downstream industry.
- xl.ix. In any case, spinning mills suffer from over capacity.
- l. It must be carefully examined as to whether the objections are actually being raised by the respondents as users; or false claims of suffering have been conjured to help their related exporters escape duties.
- li. Chairman of the respondent, Filatex India Limited has acknowledged in an interview that the availability of PTA domestically has improved the prospects of the users.
- lii. Regarding the argument that RIL has obtained advantage in downstream industry as well, it was submitted that the users have not adduced any evidence to show that they have suffered due to the duties.
- lii. Further, when RIL has valued captive consumption of PTA at market value and has not suffered injury in downstream products, there is no basis for the argument that the downstream industry is suffering due to anti-dumping duty.

- liv. As regards the reliance of respondents on PSF case, it is submitted that Indo Rama Synthetics, which was earlier suffering due to low capacity utilization, has itself mentioned in its annual report that it is now enjoying higher operating rates and profit margin. Performance of other producers of PSF, especially that Bombay Dyeing, has improved significantly.
- lv. As regards the contention of low capacity utilization of PSF industry, it was highlighted that Bombay Dyeing has itself mentioned in its annual report that it achieved a capacity utilization of 93% and that other producers achieved 80%. Even then, the average utilization of PSF producers was low due to Alok Industries, which is operating at 30% due to financial crunch, and Indo Rama Synthetics, which has working capital issues. Further, the findings of the Authority make it clear that the production of the PSF producers increased.
- lvi. With regard to reliance on lack of demand supply gap, it is submitted that there is nothing to show that the imports shall not increase now even if there is no demand-supply gap.
- lvii. In regard to the argument regarding stoppage of imports, it is pointed out that when the present duties have not led to a complete stoppage of imports, there is no basis for the contention that the continuation of duties shall lead to that.
- lviii. In relation to post period of investigation data, it was submitted that such data is only relevant when (a) the dumping margin or injury margin is negative in period of investigation, or (b) the duties have expired post period of investigation, to show likelihood.
- lix. If the post period of investigation data is called for, then extension of duties for one year should be requested as the investigation would take longer to conclude.
- lx. As regards the argument that there was a shut down at the plant of IOCL, it was submitted that the domestic industry had supplied additional volumes to the consumers to cater to the deficit created by the shutdown to ensure that the consumers did not suffer. Further, RIL's plant at Patalganga can be restarted within a period of 15 days to cater to supply.
- lxi. With regard to the reference to Article 8 of ASEAN-India Free Trade Agreement, it was highlighted that the article relates only to non-tariff measures.
- lxii. As regards the argument that paperbook was not circulated by the domestic industry, copies of the emails sent were produced. It was also submitted that since the paperbook contained extracts of responses and the domestic industry had already filed letters highlighting deficiencies therein, the respondents got due opportunity to defend.
- lxiii. In response to the allegation that application was not duly substantiated, reliance was placed on the observations of the Authority in this regard in the Initiation Notification.
- lxiv. Regarding arguments of public interest, it was submitted that the same is for the Government of India to consider, and not for exporters to comment upon. Continuation of duties shall ensure level playing field in the market.

F.2. Submissions by other interested parties

- 17. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:
 - i. The post period of investigation data is relevant in a sunset review, which would show decline in imports.
 - ii. The argument that users' associations do not have a right to present their views before the Designated Authority is absurd. It cannot be said that the users are remediless in an anti-dumping investigation. Whether the anti-dumping duties have either a direct or indirect impact on the business of a party determines whether a party can be treated as an interested party or not.
 - iii. The definition under Rule 2(c) is an inclusive definition and it cannot be argued that a party importing for self-consumption cannot be treated as an interested party. The Anti-Dumping Agreement also provides that other parties not included in the list may be treated as interested parties.
 - iv. The past practice of the Designated Authority also shows the adoption of the inclusive aspect of the definition as the PTA Users Association has been treated as an interested party in the past as well. The Association comprises of users of PTA and anti-dumping duty thereon has a direct impact on the duties.
 - v. Not only the PTA Users Association, but also the users and associations concerning products supplied by PTA users should also be treated as interested parties, as they suffer due to the anti-dumping duty on PTA.
 - vi. PTA Users Association along with its members and associations of producers of downstream products are

- clearly interested parties and any contentions to the contrary by the domestic industry show that they want to shut any voice against their request for continuation of anti-dumping duty.
- vii. Incidence of anti-dumping duty in a situation where imports were necessitated due to a demand-supply gap has rendered the user industry vulnerable to mounting losses and stagnation.
 - viii. The user industry covers many producers in the downstream applications such as PSF, POY, DTY, Film, PET etc., and is also one of the largest employment generating industries in the country consisting of spinning, weaving, knitting, processing and garments industry.
 - ix. The domestic manufacturers have added significant capacity and the improved supply position combined with the anti-dumping duty protection enjoyed by them has led to tremendous decline in imports into India.
 - x. The domestic producers enjoy near monopolistic situation and resort to monopolistic rent and manipulate the prices to the disadvantage of the users.
 - xi. Reliance Industries Limited, the largest producer having vertical integration, enjoys dominant position in the market; whereas the user industry is highly diversified and is affected by the anti-dumping duty on PTA.
 - xii. The downstream products of PTA earn major foreign exchange, of about Rs. 8,080 crores and if the downstream products up to garmenting are included, the earnings would be about Rs. 1 trillion. This segment represents a very significant share of India's GDP and urban as well as rural employment. All these downstream producers are in serious disadvantage because of antidumping duty.
 - xiii. The textiles exports are stagnant due to high cost of raw materials because of anti-dumping duty on PTA. Producers of downstream value added textile products in the entire value chain have been rendered vulnerable and have become uncompetitive.
 - xiv. The change in demand supply situation shows that the domestic industry did not suffer injury.
 - xv. Performance of domestic industry shows that it is enjoying a fabulous profits and earning a monopolistic rent.
 - xvi. The declining trend of imports and sharp increase in profitability of the domestic industry signifies that it has been resorting to overcharging the PTA users in India by misusing the anti-dumping duty in place. Any continuation of such limited volumes in the future also should be seen as a balancing factor to stop the domestic industry from overpricing the PTA produced by them.
 - xvii. Global demand supply situation shows that there is no likelihood of recurrence of dumping from the subject countries.
 - xviii. Though the imposition of anti-dumping duty on PTA has enriched a few producers of PTA significantly, the growth of dozens of companies in the user segment have been impacted.
 - xix. The users are the worst sufferers because of the long imposition of anti-dumping duties on their basic raw material. The duty should expire to allow the users breathing space to run their businesses competitively.
 - xx. The plant of IOCL has been shut down for 3-4 months and the users need a viable alternative source of PTA. There should be free and fair availability of other sources of PTA.
 - xxi. The high captive consumption by Reliance should be examined in view of the anti-dumping duty in force, as the chances of Reliance rigging the PTA market is very much possible.
 - xxii. In the recent investigation into imports of PSF, no duty was levied as the domestic industry could not prove that the injury was caused due to imports. Reliance as a major producer of PSF did not participate, and it determines the price for both PTA as well as for PSF. The Authority found that the domestic industry suffered loss as it could not even pass on the cost of production to its users.
 - xxiii. The PTA prices in India are most expensive when compared to any other country. The Indian PTA producers are charging additional premium over international PTA prices, in the form of ocean freight, port clearing charge, customs duty and anti-dumping duty. As a result, the domestic industry is able to charge a whopping Rs. 7,120 per ton or USD 102 per ton extra.
 - xxiv. The user industry needs to get PTA at fair price to explore all the opportunities it has, including the robust export and domestic market for textiles/man-made fibre. The main reason why the share of man made fibres is not increasing is the costly raw material.
 - xxv. As a result of the duties, the raw material cost of PSF producers increases and they are forced to offer discounts on their finished product, as a result of which they have become sick.

- xxvi. As the Indian textile industry grows, it shall benefit all the domestic players, including the PTA producers as also increase employment, exports and GDP.
- xxvii. There are short term plant shutdowns, the duration and timing of which is unknown. These shutdowns cause scarcity in the market and the producers use these scarcities to jack up prices.
- xxviii. The users cannot consider imports in face of short supply and are cutting operations. While Reliance could meet more than 90% capacity utilization in PSF in 2018-19 and 100% thereafter due to uninterrupted supply of PTA, other PSF producers ended up with lower utilization of 65-75% due to the local shutdowns.
- xxix. The supply issues are going to persist for at least another 6 to 12 months and the PTA producers shall use these opportunities to increase prices as they are aware that the users do not find it viable to shift to imports.
- xxx. The domestic industry did not circulate the paper book relied upon during the hearing, as is required by Trade Notice issued by the Authority in the past. The domestic industry went on to make one sided allegations without giving any opportunity to the other side to rebut them.
- xxxi. Although the paperbook was circulated later on 30th April, 2019, it shall not be appropriate to address them unless the claims are reproduced in writing.
- xxxii. Responding to the allegations of the domestic industry, it was submitted that the response by the users contains relevant information about purchases and also imports.
- xxxiii. Reply to Section E in the questionnaire was mentioned as not applicable as it is applicable for the imports and resale of product under consideration.
- xxxiv. The annual reports of all the users were provided in the respective CD-ROMs, including in the non-confidential version of the CD-ROMs, in case of listed companies.
- xxxv. Allegations of the domestic industry with respect to post-invoicing discounts are baseless as replies contain all information on how such items are accorded in the books of account of the respective company.

F.3 Examination by the Authority

- 18. The present investigation being under anti-dumping law, the Authority has considered and examined only such issues which are relevant and appropriate under the present law. Alleged issues such as monopolistic pricing or abuse of dominant position are not within the scope of the present investigation. It is however noted that the interested parties have not placed any credible evidence on record in support of these allegations. Further, it is noted that the landed price of imports from subject countries are lower than the selling price of each of the petitioners.
- 19. With regard to scope of interested parties, the Authority notes that Rule 2(c) provides as under:
 - “(c) *“Interested party” includes -*
 - (i) an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in India, or a trader or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;*
 - (ii) the government of the exporting country; and*
 - (iii) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India”*
- 20. It is noted that the concern regarding impact of anti-dumping duty has been expressed by the downstream users and their associations.
- 21. It is noted that even though associations of downstream users are not explicitly mentioned in the definition of Rule 2(c), the Authority has examined their submission to address the concerns expressed by these associations. Associations such as SIMA, CITI and ISA, while expressing their views, have not given any concrete evidence to substantiate their claims, nor quantified the impact of the existing duties on their members. Since there was an ADD in force on the product for some time, it was possible for the associations to demonstrate and quantify the impact of ADD. The Authority also notes the submissions of the petitioners quantifying the impact of duties on the final downstream products. The petitioners have also made submissions that the alleged adverse performance of the downstream industry of the consumers are attributable to other factors.
- 22. As regards the submissions of the responding users regarding the impact of duties, the Authority notes that no concrete or verifiable evidence has been provided by users too to substantiate their contention. The Authority notes that the users have not filed information in the form and manner prescribed and the questionnaire response filed are

incomplete. The domestic industry has filed the financial statements and annual reports of a number of consumers, which show that the profitability of the user industry has not declined. Further, the evidence provided by the domestic industry on the contrary shows that the downstream industry is expanding.

23. The Authority also notes that the imposition of anti-dumping duty has not prevented imports in any way, nor would continuation of duty prevent imports in any manner. Continuation of duty would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to address the issue of trade distortion caused by the unfair trade practices in order to re-establish the situation of open and fair competition.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the domestic industry

24. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. Despite anti-dumping duties in force, the exporters from the subject country have continued to dump the subject goods into India.
 - ii. There is a long history of dumping from the subject country and the dumping margin in the present investigation is higher than the dumping margin determined in the past investigations.
 - iii. Indorama Petrochem Limited (IRPL), TPT Petrochemical Public Company Limited (TPT) and Hyosung TNC Corporation (HTC) have not filed a response to the Part II of the Exporters' Questionnaire, which is important for carrying out a likelihood analysis.
 - iv. HTC was not even in existence during the period of investigation and has no locus to file a response for exports made by M/s Hyosung Corporation. A response by the related party cannot substitute a response by the actual exporter of the goods.
 - v. The exporters and traders forming part of the channel of distribution have not participated, leaving the value chain incomplete.
 - vi. One of the producers, whose goods have been exported to India by HTC, has not participated in the investigation.
 - vii. There are other exporters mentioned in the responses of HTC, Taekwang Industrial Company Limited ("Taekwang"), and TPT, which have not participated in the investigation.
 - viii. IRPL, TPT and HTC have not filed details of their third country exports, which is necessary for likelihood analysis.
 - ix. HTC has supplied goods of two Korean producers but has filed a response in respect of goods produced by only one of them.
 - x. IRPL and TPT have suppressed the details of their related importer in India, namely, Indo Rama Synthetics Limited, which has actually imported the subject goods from Thailand.
 - xi. HTC has suppressed the fact that its related entity has a plant in Korea RP.
 - xii. The responses filed by the producers / exporters are contradictory in themselves.
 - xiii. While at one place, HGC purported that none of its shareholders or their related parties are engaged in resale of the product under consideration, it later disclosed that one of its related parties is engaged in resale of the products.
 - xiv. TPT, IRPL and Taekwang have also made contradictory claims regarding the channel of distribution.
 - xv. Unless an interested party has filed correct, complete and accurate information, it cannot be considered to have cooperated to the best of its ability with the Designated Authority and its response should be rejected.
 - xvi. The respondents have claimed to have cooperated by stating that they would provide any "further information" or "details" required. However, at this stage, the Authority may only call for "further" information or details and not information that was already required to be provided by the explicit language of the questionnaire.
 - xvii. Considering that the duties would expire on 24th July, 2019, and the investigations must be concluded before that, the Designated Authority may consider the appropriate action with regard to incompleteness of responses.
 - xviii. When the exporters have not even filed Part II of Questionnaire or determination of third country exports, the question of determination of likelihood based on their response does not even arise.

- xix. Despite the domestic industry filing multiple letters identifying the deficiencies in the responses giving exporters ample time to respond to the submissions, the respondents are yet to offer any defence or clarification.
- xx. Since PX constitutes about 80% of the total cost of the product, considering raw material cost in home market of exporter itself shall serve as a reasonable basis for determination of normal value.

G.2. Submissions by other interested parties

25. The submissions made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. Though the responses filed are complete to the best of the understanding of the parties, they are ready to provide further information/details.
 - ii. During the period of investigation, there were significant fluctuations in the global oil market, which directly affected the price of PX and PTA. The dumping margin should be calculated on a month-wise basis.
 - iii. The petitioners have constructed normal value based on cost of production of the producers in subject countries. The said calculation is hypothetical and not based on actual data.
 - iv. As per Annexure – I to the Anti-Dumping Agreement, the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to obtain further details. Therefore, the Exporters' Questionnaire Response is not the end of investigation and the Authority may call for additional information or clarification.
 - v. The cooperating producers/exporters and other parties as above have submitted all relevant data to determine dumping margins, injury margins etc. respectively and the same should be adopted for final findings.
 - vi. Response of Hyusong is complete as it reports all exports made to India and has submitted complete data in questionnaire as applicable to an exporter entity.
 - vii. HTC was previously a trading arm of Hyousong Corporation, but is an independent entity now.
 - viii. More than 85% of the goods exported are produced by Hanwha and therefore, the value chain for such goods is complete; whereas the Authority always accepts responses where more than 70% of the value chain is complete.
 - ix. In the original investigation, the dumping margin of Taekwang was only 4-5%, and it is not dumping in the present investigation. The imports from Korea RP are not being dumped and are coming only to fill the demand and supply gap in India.
 - x. More than 90% of the exports by Taekwang have been made directly and the balance through an unrelated exporter. The exporter did not file a response despite giving verbal assurances for the same. This cannot be considered as non-cooperation by producer/exporter since more than 70% value chain is complete.
 - xi. The Designated Authority is requested to change the name on record for the purpose of the present investigation from Samsung General Chemical Co., Limited to Hanwha General Chemical.
 - xii. IRPL and TPT have filed the relevant information in the prescribed format as per Trade Notice issued by the Authority in this regard.
 - xiii. TPT had exported some volume through certain unrelated exporters but they did not file the response. However, such exports are very insignificant.
 - xiv. The domestic industry has submitted an inflated normal value and lower export price to exaggerate the dumping margins, which is not correct
 - xv. The questionnaire requires the exporters to provide third country export data if the normal value claimed is based on domestic price of the exporter. In any case, the performance data provided by the exporter has details of third country exports as well.
 - xvi. TPT and Indorama have provided their corporate structure in detail.
 - xvii. IRSL is not related to the exporters in terms of any shareholding and the relation is only in terms of family relations with the directors. The said disclosure is available in the annual report of IRSL filed before the Authority.
 - xviii. The assertion of the domestic industry that IRSL imported from Thailand is incorrect.
 - xix. The responses are not deficient and should not be rejected as the interested parties have filed the prescribed responses within the timelines fixed by the Authority and the responses are complete.
 - xx.

H. NORMAL VALUE

26. Exporter's questionnaire responses have been submitted by the following producers/exporters from Korea RP and Thailand.
- i. M/s Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP
 - ii. M/s Hyosung TNC Corporation, Korea RP
 - iii. M/s Hanwha General Chemical Co., Korea RP
 - iv. M/s Indorama Petrochem Limited, Thailand
 - v. M/s TPT Petrochemicals Public Company Limited, Thailand
27. Some of the exporters submitted that the dumping margin should be determined by undertaking comparison of normal value and export price on monthly basis. It is however, noted that the exporters have not been able to demonstrate significant variation in both the normal value and export price on the basis of monthly prices.

H.1. Normal value for Korea RP**Normal value for M/s Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP**

28. The Authority notes that M/s Taekwang Industrial filed response. The company had exported *** MT of the subject goods directly to India and *** MT through related exporter M/s Posco Daewoo during the period of investigation. M/s Posco Daewoo has not filed a response in the present investigation.
29. In the domestic market, the company has some captive consumption and some sales to related party. The cost of production reported by the company was examined in detail, and after due verification & reconciliation of the data, the cost of production of the company has been determined as US\$ ***/MT (excluding packing cost) which has been adopted for the purpose of determination of normal value.
30. Transaction wise details of sales made by the exporter has been examined in detail. Profit margin has been determined in respect of profitable sales as ***%. Further, considering the cost of production, it is seen that ***% sales of the company are profitable. Since sales below cost of production are more than 20%, the normal value has been determined on the basis of profitable sales of the company in the domestic market. Price adjustments have been claimed in respect of inland freight, packing cost, credit cost, which have been allowed after due verification. The normal value so determined comes to US\$ *** per MT

Normal value for M/s Hanwha General Chemical Co., Korea RP and M/s Hyosung TNC Corporation, Korea RP

31. The Authority notes that M/s Hanwha General Chemical Co. (HGC) had exported the subject goods through the trading division of M/s Hyosung Corporation (HC) during the period of investigation. The trading division of HC has been hived off and a new entity M/s Hyosung TNC Corporation has been formed. HTC has filed a response in respect of the exports made by HC. After due verification of the records, the Authority finds it appropriate to determine the dumping margin considering the response filed by HGC and HTC.
32. Transaction wise detailed of domestic sales made by the exporter has been examined in detail. It is noted that ***% of the sales in the domestic market are profitable. Accordingly, the normal value has been considered on the basis of profitable sales. The normal value so determined comes to US \$ *** per MT.

Normal value for all other producers/exporters from Korea RP

33. In respect of all other producers/exporters from Korea who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. The normal value so determined is USD *** per MT.

H.2. Normal value for Thailand**Normal Value for M/s Indorama Petrochem Limited (IRPL), Thailand**

34. A perusal of the responses filed by M/s Indorama Petrochem Limited (IRPL) shows that they have not filed response to Part II of the questionnaire, which contains information relevant for likelihood determination.
35. Further, data/ detail reported in different appendices do not tally. SGA expenses reported in Appendix 9 is not matching with that in appendix 7 and 8. The profit figure as reported in appendix 5 (for trading) & other raw material cost, packing cost and utility cost as reported in appendix 6 do not match with appendix 7 and 8.
36. Accordingly, the Authority holds the exporter as non-cooperative and has not allowed an individual dumping margin for the exporter.

Normal Value for M/s TPT Petrochemicals Public Company Limited, Thailand

37. A perusal of the responses filed by M/s TPT Petrochemicals Public Company Limited (TPT) shows that they have

not filed response to Part II of the questionnaire, which contains information relevant for likelihood determination.

38. The company claimed profit in Appendix 7 and 8 for PUC but this is actually a loss. Appendix 8 is still not as per Trade Notice 05/2018 dated 28.02.2018 as company has not mentioned/claimed per unit cost for PUC. The company has not claimed packing material cost in appendix 6 whereas the same has been claimed in appendix 7. The sales value as claimed in Appendix 7 and 8 is not matching with Appendix 3 & 4 related to sales.
39. Accordingly, the Authority has treated the exporter as non-cooperative and has not allowed an individual dumping margin for the exporter.

Normal value for all producers/exporters from Thailand

40. Since the Authority has found M/s IRPL and M/s TPT to be non-cooperative and in view of non-participation from any other exporter from Thailand, the Authority holds to determine normal value for all producers/exporters from Thailand as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. The normal value so determined is USD *** per MT.

I. EXPORT PRICE

I.1. Export price for Korea RP

Export price for M/s Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP

41. M/s Taekwang Industrial Co. Ltd. has exported the subject goods through 2 channels i.e directly *** MT of PTA during POI to India and *** MT through unrelated party M/s Posco Daewoo. M/s Posco Daewoo has not filed the Exporter Questionnaire Response. However, since exports through unrelated trader M/s Posco Daewoo constitute only ***% of the total exports made by M/s Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP, the response of M/s Taekwang Industrial Co. Ltd has not been rejected on this ground.
42. The questionnaire response filed by Taekwang Industrial was examined and certain discrepancies were noticed in respect of exports to India and rest of the world.
43. The Authority holds to consider adjustments on account of ocean freight & ocean insurance; wherever applicable, inland transportation, port & other related export expenses, packing charges, credit cost, duty drawback, documents fee and bank charges.
44. Since the unrelated exporter, M/s Posco Daewoo has not filed response, the adjustments to export price for the exports made through M/s Posco Daewoo have been considered on the basis of facts available. The export price for M/s Taekwang Industrial Co. Ltd., has, accordingly, been arrived on the basis of weighted average export price of the direct exports and exports through M/s Posco Daewoo. The Ex-factory export price comes to USD ***/MT.

Export price for M/s Hanwha General Chemical Co., Korea RP and M/s Hyosung TNC Corporation, Korea RP

45. M/s Hanwha General Chemical Co., has exported the subject goods through 2 channels i.e through M/s Hysoung TNC Corporation and through M/s Posco Daewoo. While M/s Hyosung TNC Corporation has filed Exporter Questionnaire Response, M/s Posco Daewoo has not participated in the investigation. However, since exports through unrelated trader M/s Posco Daewoo constitute only ***% of the total exports made by M/s Hanwha General Chemical Co., the response of M/s Hanwha General Chemical Co. has not been rejected on this ground.
46. As regards exports through M/s Hyosung TNC Corporation, it is noted that the exporter has sold these goods to end customers but has incurred losses during POI. The Authority has appropriately adjusted the export price to determine the Ex-factory Export Price. The Authority has considered adjustments ocean freight, inland transportation, port handling, packing charges, credit cost and duty draw back. Further, adjustment on expenses incurred by the exporter, HTC, has also been considered.
47. Since M/s Posco Daewoo has not filed response, the adjustments to export price for the exports made through the said exporter have been considered on the basis of facts available. The export price for M/s Hanwha General Chemical Co., has, accordingly been arrived on the basis of weighted average export price of exports through M/s Hyosung TNC Corporation and exports through M/s Posco Daewoo. The Ex-factory Export Price is determined at *** \$/MT.

Export Price for all other producers/exporters from Korea RP

48. The Authority has determined the export price for non-cooperating producers/exporters from Korea RP based on facts available. Accordingly, net export price at ex-factory level for exports from the Korea RP is as shown in the dumping margin table below.

I.2. Export price for Thailand

49. The Authority has determined the export price for all producers/exporters from Thailand on the basis of facts available. Accordingly, net export price at ex-factory level for exports from the Thailand is as shown in the

dumping margin table below.

J. Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject countries

50. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries is determined as below:

SN	Country	Producer	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1.	Korea RP	Taekwang Industrial Co. Ltd.	***	***	***	***	0-10
2.	Korea RP	Hanwha General Company through Hyosung TNC Corporation	***	***	***	***	10-20
3.	Korea RP	Any other	***	***	***	***	20-30
4.	Thailand	Any	***	***	***	***	10-20

K. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

K.1 Submissions by the domestic industry

51. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced hereinbelow:
- The domestic industry is in a fragile state and it needs continued support and protection of duties. Cessation of duty is likely to set back the progress made.
 - Although the volume of imports declined upto 2016-17, it has increased again in the period of investigation by 74%, even though the demand increased by only 9%.
 - The imports have also increased in relation to production and consumption as compared to the preceding year.
 - The subject imports continue to hold about 10% of the market.
 - Imports have also increased in relation to total imports, and the imports from other countries have declined. The subject imports account for about 72% of the total imports into India.
 - Despite there being sufficient capacity to cater to the demand of product in the country, India continues to be a net importer of the subject goods. If the duties are removed and the imports are allowed to increase, it would result in loss of valuable foreign exchange for the country.
 - Further, the domestic producers are also investing approximately *** crores in capacity expansions to meet the potential demand for the product and as a result, continuation of duties is necessary.
 - There is stiff price competition between the imports and domestic subject goods. Domestic industry has been forced to almost match the price of imports and is not at liberty to increase its price so as to earn a reasonable return.
 - The price undercutting in the present investigation is positive and the imports have prevented the domestic industry from earning adequate profits even during the period of investigation.
 - The price underselling is positive and significant showing that the imports are at prices much below fair selling price and the domestic industry shall be injured in case the anti-dumping duty ceases.
 - The demand in India is sufficient to allow the industry to operate at ***% utilization. However, due to the imports, the domestic industry was forced to export *** Lakh MT at losses, even when operating at ***% capacity.
 - While the production and sales of the domestic industry have increased, the same is only a result of the duties in force.
 - While the market share lost in the period of investigation is not significant, it needs to be considered that

- such decline is in a situation where the anti-dumping duties are in force.
- xiv. Increase in imports has led to increase in inventories by five times of that in base year and the inventory holding period has increased.
 - xv. The profits of domestic industry are not adequate and the rate of improvement is slow.
 - xvi. The return on investment is way below the benchmark of 22% set up by the Authority, and even lower than the bank rate of interest.
 - xvii. When the domestic industry is not even able to earn a bank rate of interest, it shows that the domestic industry would face significant difficulty in raising capital investments.
 - xviii. There is no requirement to establish the existence of a causal link between the likely dumping and likely injury in a sunset review.
 - xix. The domestic industry is not likely to suffer injury due to other factors.
 - xx. There is a clear causal link between dumping of subject goods and the likely injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.
 - a. There is continued dumping of subject goods.
 - b. There is an increase in imports, particularly during the last two quarters, which shows likelihood of increase in imports in the event of cessation of duty.
 - c. Resultantly, there is likely to be a decline in demand for goods of domestic industry, which would impact its sales, production and capacity utilization.
 - d. There is positive price undercutting and underselling.
 - e. In the event of cessation of duty, the import prices are likely to reduce further, which would put a strain on the prices of the domestic industry and its profitability would deteriorate.
 - xxi. Reliance Industries Limited has been forced to suspend the operations at its plant in Patalganga due to inadequate margins.
 - xxii. In response to arguments regarding profitability of Reliance, it was submitted that the performance of domestic industry must be seen with regard to product under consideration only, and performance of company as a whole is irrelevant.
 - xxiii. Responding to the argument that there was a decline in imports from 2014-15, it is submitted that imports during a period when the anti-dumping duty was not in force cannot be compared to a period when the anti-dumping duties were in force. On the contrary, the decline shows that the imports are low only because of the duties in force.
 - xxiv. The domestic industry had to sell the product at prices much lower than the import price inclusive of duty. Had it tried to increase its prices, the users would have immediately switched to imports.
 - xxv. Contrary to the arguments of the respondents, the imports from countries not attracting anti-dumping duty has increased by 6 times when compared to the base year.
 - xxvi. Regarding the arguments that the volume of imports was negligible, the reference is made to the practice in European Union wherein imports from each country above 1% of demand, and collectively from all subject countries above 3% is considered significant.
 - xxvii. The reliance of respondents on the PSF finding was not appropriate as it was an original investigation, whereas in the present case, the imports account for 10% of market share despite duty.
 - xxviii. Regarding figures of profit margins as per annual reports of RIL, it was clarified that the margins reported are that at a global level, with the annual report clearly mentioning Platts, ICIS, CCF journals as the source for the margins reported.
 - xxix. As regards the contention that there was no situation of flood of imports even prior to imposition of duty, it is submitted that the same is contrary to the findings of the Designated Authority.
 - xxx. Responding to the argument that the injury to the domestic industry had been caused by global demand supply situation, it is submitted that the same is contrary to the finding of the Designated Authority which concluded that the injury to the domestic industry had been caused by dumped imports.
 - xxxi. With regard to the increase in margin, it was submitted that the increase in margins as compared to a period when the domestic industry was in losses due to dumped imports does not imply that the profitability in the period of investigation is adequate.
 - xxxii. As regards the argument of significant captive consumption of RIL, it is submitted that the domestic industry was heavily dependent on the merchant market and it constituted a major share of its turnover.
 - xxxiii. As regards the argument that the domestic industry is able to charge Rs. *** per ton extra due to freight, port charges, etc., it is submitted that if such expenses are excluded, it would be clear that the price of

imports is even below the cost of production of the subject goods.

- xxxiv. Regarding the contention that MCPI suffered due to plant shutdowns, it was highlighted that the capacity utilization of MCPI was high during the period of investigation.

K.2 Submissions by other interested parties

52. The other interested parties have submitted as under:

- i. The fact that the performance of domestic industry has improved magnificently, with supernormal profits earned by it because of its near total monopoly in the domestic market due to elimination of imports, demonstrates that the domestic industry neither suffers any current injury nor there is any imminent threat of recurrence of injury if the duties are allowed to expire
- ii. The imports have declined by **%, which is substantial.
- iii. The domestic industry has been seeking protection of antidumping on the plea of material injury while it is investing and adding capacities with monopolist prices in the domestic market.
- iv. The reduction in imports is linked to increase in capacity to produce PTA in India, which shows that the decline is permanent. Post period of investigation, the imports have decreased further. Further, the imports during this period were abysmal given the demand in India.
- v. The decline in cost was more than the decline in selling price, which shows that the domestic industry has used its dominant position in the market to not pass on the benefits of cost reduction to its customers.
- vi. The decrease in imports and increase in volumes of domestic industry shows that users are relying on domestic producers of PTA except for some minor volumes of duty free imports under Advance License and EPCG.
- vii. The user industry would always prefer local supply, if the price differential is not too high. Therefore, even if the duties are removed the domestic users will continue to buy from the domestic industry unless they resort to monopolistic pricing.
- viii. Negligible level of price undercutting maybe due to monopolistic pricing of the domestic industry due to anti-dumping duty protection and high margins enjoyed by it (in the range of 15-30% during the period of investigation and 30-40% thereafter).
- ix. Even the imports from other sources, not attracting anti-dumping duty have declined, which further indicates a permanent shift of the users to the domestic industry.
- x. The imports are negligible in relation to demand and absence of even such small volume would lead to absolutely monopolistic pricing activities from the domestic industry.
- xi. As held in the finding in anti-dumping investigation into PSF, a negligible share of 7% held by imports in demand cannot be treated as sufficient to cause any injury.
- xii. Parameters such as capacity, production, sales, capacity utilization etc. have been at the highest level during the period of investigation. Such magnificent performance in volume parameters suggests that the domestic industry is not vulnerable to any injury in terms in the event of expiry of present duties.
- xiii. Growth in price parameters such as selling price and cost of production, profitability per unit, PBIT, etc. is stupendous and very significant.
- xiv. The fact that reduction in selling price was lower than reduction in cost implies that the domestic industry enjoyed a stronger pricing power, as a result of which there was a strong jump in its PBIT.
- xv. Margins achieved by RIL in the recent times show the magnitude of such consistent increases in margins irrespective of certain volatility in some quarters owing to market fluctuations.
- xvi. Post period of investigation margins are important in a sunset review case. The data shows that margins increased from USD *** per MT in period of investigation, to USD *** per MT thereafter, driven by monopolistic approach in pricing adopted by the domestic industry.
- xvii. Domestic industry is earning return on capital employed in the range of 15% to 30% and such consistent margins show that the domestic industry is no longer vulnerable to any injury from imports.
- xviii. While the market share of domestic industry increased, the share of subject countries halved. The imports have come down by 50% as a result of increase in capacity in India by 67%.
- xix. There is no preference for the imported product and the imports that took place includes imports for export obligations predominantly.
- xx. The positive price undercutting combined with the capability of the domestic industry to maintain high price indicates that the domestic industry is a price giver and not price taker.

- xxi. Continuation of anti-dumping duty on PTA from subject countries will impact the user industry adversely in India.
- xxii. The claim of injury margin by the domestic industry is exaggerated and the domestic industry is clearly selling above its cost, and even above its non-injurious price. Had the domestic industry not been selling at a fair price, it would not have registered such high profits and margins.
- xxiii. In the wake of manifold growth in demand from downstream industry and the ongoing expansion plans by the domestic industry, it is not logical to continue restrictions in PTA availability through anti-dumping duty.
- xxiv. As per annual report of Reliance for 2012-13, the global demand supply situation had an impact on the Indian market as well. However, the recently published results show that PTA margins improved due to tight supplies and firm demand.
- xxv. There is a growth of ***% in the PTA margin between period of investigation of original investigation and present period of investigation, and by ***% post period of investigation. The figures for RIL should be taken as industry average as it is the largest producer of subject goods.
- xxvi. During the last quarter of 2018-19, the margins declined due to sluggish downstream demand and liquidity tightness, which has nothing to do with imports.
- xxvii. The domestic industry has come out of the past injuries and the consistent scale of performance indicates that the domestic industry is not vulnerable to any injury from imports.
- xxviii. Although the demand has increased from 100 index points in 2014-15 to 128 index points in period of investigation, the imports have declined by ***%. By comparison, the sales of the domestic industry have increased by ***%.
- xxix. While the landed price has declined in tandem with the decline in cost, the selling price has not reduced commensurately.
- xxx. Price undercutting should not be seen in isolation, but has to be seen in light of the overall performance of the domestic industry, as to whether it is resulting in losses.
- xxxi. While the petitioners have claimed that imports are undercutting prices, the data provided shows that price undercutting is negative across the injury period, except in 2016-17.
- xxxii. The capacity, production and capacity utilization of the domestic industry have improved over the injury period and the capacity utilization is maximum in the period of investigation.
- xxxiii. The domestic sales of the domestic industry have increased, along with substantial increase in captive consumption and exports.
- xxxiv. The market share of the domestic industry has increased from 100 in 2014-15 to 130 in the period of investigation, while the share of imports has declined. Share of other Indian producers has also declined.
- xxxv. As per the Directors' Report filed by MCPI with MCA in 2016-17, the plant was shut down due to technical troubles, power-dips in the grid supply, etc. The financial statements for 2017-18 are not available, but the financial statements of 2016-17 show that injury to the domestic industry may be caused due to other factors.
- xxxvi. When the profits have increased substantially from (100) to 485 index points, the return on investment must have also increased commensurately.
- xxxvii. While the number of employees has declined, the productivity of the domestic industry has increased significantly.
- xxxviii. The overall performance of the domestic industry is improving and the injury to the domestic industry cannot be attributed to the imports.
- xxxix. Imports are increasing in India only to fill the demand and supply gap and not to cause injury to the domestic industry, as alleged.
- xl. Any injury suffered by the domestic industry is due to factors other than imports.
- xli. Non-attribution analysis should be performed to ensure causal link between the dumped imports and alleged injury.
- xlii. Since the period of investigation of the original investigation, global and Indian PTA market situation has improved considerably. If the duty is continued, the petitioners would get an additional and unfair advantage as it would result in abnormal profit of the domestic industry.
- xliii. The import quantities have continued to remain at low levels since imposition of duties, and the Indian domestic producers have made huge profits due to increasing PTA-PX spread.
- xliv. Reliance Industries has been consistently increasing its production for PX and PTA.

- xliv. The fact that it has expanded capacity to meet demands and has further expansions planned negates the contention that the industry is fragile and needs protection. The domestic industry is performing extremely well and the prices realized by them have ensured very high margins on their investments also.
- xlvi. There is no provision in the Anti-Dumping Rules to determine or identify the so called 'fragile industry' and there is no provision to continue the anti-dumping duty in case it is determined that the domestic industry is fragile.
- xlvii. The claims of positive injury margin may be due to irrationally high non-injurious price claimed by the domestic industry.

K.3. Examination by the Authority

53. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

a. Cumulative assessment

54. Para (iii) of Annexure – II of the Anti-Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- i. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively account for more than seven per cent of the import of like article; and
 - ii. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
55. In this regard, the Authority observes the following:
- i. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
 - ii. The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
 - iii. The subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are like articles.
 - iv. Imported and domestic product are being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product and imported product.
 - v. None of the interested parties have brought any such argument which does not justify cumulative assessment.
56. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from Korea RP and Thailand on the domestic industry.
57. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure – II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
58. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension. In the present case, it is found that the volume of import from each of the subject countries is not insignificant the dumping of the product has continued during the relevant period.
59. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

b. Demand and market share

60. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of

the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Excluding captive consumption					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	143	170	192
Other Indian producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	88	63
Subject imports	MT	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
Imports from other countries attracting duty	MT	3,85,983	4,37,338	1,71,892	1,37,322
Other imports	MT	1,081	1,103	22,932	6,119
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	113	124
Including captive consumption					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	152	166
Other Indian producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	88	63
Subject imports	MT	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
Imports from other countries attracting duty	MT	3,85,983	4,37,338	1,71,892	1,37,322
Other imports	MT	1,081	1,103	22,932	6,119
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	119	128

61. It is noted that the demand for the product under consideration has increased consistently over the injury period, in both the situations.

L. VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

a. Import volume and market share

62. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under –

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Subject imports	MT	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
Imports from other countries attracting duty	MT	3,85,983	4,37,338	1,71,892	1,37,322
Other imports	MT	1,081	1,103	22,932	6,119
Total imports	MT	10,44,572	6,95,828	4,12,423	5,21,478
Imports in relation to					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	29	22	36
Demand (exc. captive)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	36	29	46
Demand (inc. captive)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	34	28	45

Total imports	%	62.95%	36.99%	52.76%	72.49%
---------------	---	--------	--------	--------	--------

63. It is seen that:

- i. Imports from the subject countries declined till 2016-17 and increased thereafter in the period of investigation in absolute terms.
- ii. Imports in relation to Indian production and demand followed a similar trend. Subject imports declined in relation to production and consumption till 2016-17, but increased in the POI.
- iii. Imports from subject countries in relation to total imports declined in 2015-16 and have increased thereafter consistently.

M. PRICE EFFECTS OF THE DUMPED IMPORTS

64. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization and non-injurious price of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

a. Price undercutting

65. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the Authority has undertaken comparison between the landed price of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes. The landed price of imports, domestic prices and margin of undercutting are shown as per the table below:

Korea RP

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Selling price of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Landed price of imports	Rs/MT	57,618	47,134	45,694	48,436
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	Negative	Negative	0-10%	0-5%

Thailand

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Selling price of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Landed price of imports	Rs/MT	56,449	46,398	45,589	48,253
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0-5%	0-5%	0-10%	0-5%

66. It is seen that landed price of imports is below the net sales realization of the domestic industry, showing positive price undercutting.

b. Price suppression or depression

67. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price

of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period, when ADD was in force.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed price of subject imports	Rs/MT	57,192	46,796	45,642	48,335
Trend	Indexed	100	82	80	85
Selling price of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	84	87
Cost of sales of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	82	82

68. It is seen that while the landed price of imports were declining till 2016-17, the same increased in the POI. Further, while cost of sales declined significantly in 2015-16, the same has increased thereafter. Selling price of the domestic industry too declined significantly in 2015-16, and increased thereafter. With the ADD in force, imports were not leading to price suppression. However, whereas the landed price of imports were above selling price of the domestic industry in 2014-15 and 2015-16, the landed price of imports were below the selling price of the domestic industry thereafter.

c. Price underselling

69. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

Particulars	Unit	Korea RP	Thailand
Non-injurious price	Rs/MT	***	***
Landed price of imports	Rs/MT	48,436	48,253
Price underselling	Rs/MT	***	***
Price underselling	%	***	***
Price underselling	Range	5-15%	5-15%
Anti-dumping duty	Rs/MT	1,289	3,341
Landed price with ADD	Rs/MT	49,725	51,594
Price underselling with ADD	Rs/MT	***	***
Price underselling with ADD	%	***	***
Price underselling with ADD	Range	5-15%	0-10%

70. From a comparison of the landed price with the non-injurious price, it is noted that the price underselling is significant and more than the dumping margin for the responding exporters.

N. ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY

71. Annexure – II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

72. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	165	167
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	160	174
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	97	104
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	143	170	192
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	133	138
Exports	MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	160	145

73. It is seen that

- the capacity with the domestic industry increased during the injury period. The combined capacity with Indian industry stands at *** lacs MT as against demand of *** lacs MT in the Country.
- the production and capacity utilization has increased over the injury period to meet the growing demand within the country.
- The domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- The captive consumption has also increased over the injury period. The increase in merchant domestic sales is higher than the increase in captive consumption.
- The domestic industry has exported part of its production. The domestic industry has contended that it has undertaken exports only because of absence of demand from the domestic market.

b. Market share in demand

74. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Demand including Captive					
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	34	28	45
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	42	29
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	127	129
Other Indian producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	74	49
Demand excluding Captive					
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	36	29	46
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	45	30
Domestic industry	%	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	131	150	155
Other Indian producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	78	51

75. It is seen that the market share of domestic industry has increased over the injury period, with the duties being in force. Further, while the share of imports from the subject country in demand has declined over the injury period, it has increased in the period of investigation as compared to the preceding year. The market share of subject imports was not insignificant during the present POI.

c. Inventories

76. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table—

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	242	496	743
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	205	306	418

77. It is seen that there has been a significant increase in the level of inventories in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment

78. Profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry are as follows:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Profit/(Loss)	Rs/MT	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	40	69	256
Cash Profit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	200	347	499
Return on capital employed	%	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	47	70	196

79. It is seen that

- The profitability of the domestic industry has improved over the injury period. The domestic industry was earlier suffering financial losses. With anti-dumping measure in force, the domestic industry has come out of losses but the profit earned even now is sub-optimal considering the inadequate ROCE.
- Cash profits earned per unit of product was positive throughout the injury period and has improved over the injury period.
- Return on capital employed (ROCE) earned was negative in 2014-15, became positive in 2015-16 and improved marginally over the injury period. The ROI earned by the domestic industry was however sub-optimal.

e. Employment, wages and productivity

80. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was as below –

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	99	75
Wages per Unit	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	62	43

No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	96	94
Productivity per employee	MT/No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	140	167	185
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	160	174

81. It is seen that the number of employees has decreased over the injury period, with decline in wages per unit too. The productivity per employee and per day have however increase over the injury period.

f. Growth

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales	%	-	43%	19%	13%
Production	%	-	20%	34%	9%
Profit per unit	%	-	140%	74%	271%
Cash profit per unit	%	-	100%	73%	44%
Return on investment	%	-	147%	50%	179%

82. It is noted that both volume and profit parameters of the domestic industry have shown a growth over the period. It is also noted that despite high growth the ROI is below ***%.

g. Margin of dumping

83. It is found that the margin of dumping is positive. There is continued dumping of subject goods from the subject countries. The volume of imports is not insignificant either in absolute terms or in relation to production or merchant demand for the product in the Country.

h. Factors affecting prices

84. The Authority notes that there is a stiff price competition in the market. Comparison of landed price of imports with the selling price of the domestic industry shows that the domestic industry is aligning its prices with the price of imports. It is also noted that the landed price of subject goods from subject countries are below non-injurious price and selling price of the domestic industry.

i. Ability to raise capital investments

85. It is seen that one of the constituents of the domestic industry has enhanced capacity for the subject goods. The domestic industry has made significant capital investment. This signifies that ADD has resulted in improving their ability to raise capital investment.

O. CONCLUSIONS ON INJURY

86. With regard to volume effect, the Authority notes that the volume of imports had first declined and then increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. There is price competition between imports and the domestic industry. The price undercutting is positive Further, the price underselling is also positive. The ADD has prevented imports from causing suppression or depression effects on the prices of the domestic industry in the market. Though some of the economic parameters of the domestic industry have shown signs of improvement yet profitability and the return on capital employed remains sub-optimal. The return on capital employed is 4.82%, which is not enough to recover the cost of interest even. Injury margins on account of these continued dumped imports remains positive and significant.

P. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

87. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed price of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the period of investigation. The injury margin thus determined is as under:

Country	Producer	Exporter	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin % Range
Korea RP	Taekwang Industrial Co. Ltd.	Taekwang Industrial Co. Ltd.	***	***	***	***	10-20
Korea RP	Hanwha General Company through Hyosung TNC Corporation	Hanwha General Company through Hyosung TNC Corporation	***	***	***	***	10-20
Korea RP	Any other	Any other	***	***	***	***	20-30
Thailand	Any	Any	***	***	***	***	10-20

Q. CAUSAL LINK

88. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting; the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Anti-Dumping Rules.

a. Volume and prices of imports from third countries

89. The Authority notes that apart from subject countries and countries attracting duties, the imports from other countries are only 1% of the imports. Imports from other sources could not have caused injury to the domestic industry.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

90. The Authority notes that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. Further, there have been no changes in the pattern of consumption which can cause injury to the domestic industry.

c. Developments in technology

91. The Authority notes that none of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate possible significant changes in technology.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

92. The Authority notes that the subject goods can be freely imported. The domestic industry constitutes of three major producers of the subject goods and accounts for significant domestic production and sales. There is thus no restrictive practice causing injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry:

93. The exports by the domestic industry have increased. While the Authority has segregated data relating to export sales and profits while assessing injury to the domestic industry, the domestic industry has contended that they have been forced to export only because of absence of demand for their product within the Country.
94. From the above analysis, the Authority notes that injury to the domestic industry has not been caused by any other known factor. Further, the causal link between the dumping and injury is evident from the following:

- i. There is continued dumping of the subject goods, despite duties in force.
- ii. The domestic industry is not able to charge prices which could have led to reasonable return to the domestic industry.
- iii. In the event of cessation of duties, the imports are likely to cause either deterioration in price & profit parameters of the domestic industry, or is likely to adversely affect volume parameters of the domestic industry or both.

R. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

95. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

R.1. Submissions by the domestic industry

96. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury –
 - i. There is continued dumping of subject goods and the imports are entering the market at injurious prices.
 - ii. The dumping margin and the injury margin in the present investigation are more than the original investigation, indicating intensified dumping.
 - iii. The unfair pricing behaviour of the exporters is evident from the fact that the dumping margin and injury margin have been positive across the injury period.
 - iv. Moreover, the exporters in the subject countries are dumping in third countries as well. ***% of the exports from Korea and ***% of exports of from Thailand are at dumped and injurious prices. The dumping margin and injury margin for third country exports is also significant.
 - v. The increase in imports in the period of investigation itself is indicative of the likelihood of increase in imports in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - vi. Further, the imports have also increased across the period of investigation on a quarter-wise basis, which is a clear indicator of increase in imports in the event of cessation of duty.
 - vii. The users have themselves admitted their inclination towards imports from subject countries at dumped prices. It indicates that the imports will increase significantly after removal of duty.
 - viii. The capacity in the subject countries is about *** lakh MT, whereas demand is sufficient to meet only about 45% of the capacity, leaving the exporters in the subject countries with huge freely exportable capacities to the extent of *** million MT.
 - ix. In fact, about 20% of the capacities in the subject countries remained idle. Even if such idle capacities are used, it would result in the subject imports capturing an additional share of more than 40% of the merchant Indian market.
 - x. The producers in the subject countries are heavily dependent upon their export markets.
 - xi. The domestic demand in the subject countries is stagnant and does not offer much potential. Further, the exports from the subject countries have declined. As a result, the producers in subject countries shall be forced to look for alternative markets.
 - xii. There has been a decline in exports of downstream products, except PET, from the subject countries, which indicates that the domestic demand for PTA would have declined.
 - xiii. India, European Union and China PR are the major markets for the exports from subject goods. However, China PR shall not be available to subject exporters due to anti-dumping duties on one hand and expanding capacities in China PR on the other hand.
 - xiv. Indorama Ventures has taken over a non-operational plant in Europe in July, 2018 and had also expanded capacity in 2017, as a result of which the capacity in European Union has increased by 14 lakh MT. With the closure of European Union market, India shall remain as the only viable market for the exporters.
 - xv. Despite existing anti-dumping duty, India accounts for 8% of exports from Korea and 21% of exports from Thailand. This makes it amongst the top 5 export destination for subject goods from the subject countries.
 - xvi. India is a price attractive market for the exporters in as much as ***% of exports from Thailand and ***% of exports from Korea RP are at prices lower than that for India.
 - xvii. Therefore, India shall continue to remain as a major market for the exporters in the subject countries.

- xviii. Considering the positive price undercutting and the fact that the imports have prevented the domestic industry from earning adequate profits, it is likely that the imports would suppress or depress the prices of domestic industry in the absence of duties.
- xix. Regarding the argument that the global demand supply situation is balanced, it was emphasized that there is a global surplus with regard to the subject goods, to the extent of 15-20%.
- xx. While the capacity for the subject goods is projected to increase by 19,601K MT, demand is projected to increase by only 13,941K MT, creating a global surplus.
- xxi. In a situation where the users are admittedly importing for export requirements, they will import for meet their domestic requirement as well in the event of cessation of duty.
- xxii. Regarding the argument that the Indian industry would have excess capacity in five years, it was submitted that it does not throw any light on the present status or the likely scenario in the event of cessation of duty in the near future.
- xxiii. Since the purpose of a sunset review to evaluate whether injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of duties, price undercutting should be calculated based on landed price exclusive of duty.
- xxiv. In the event of expiry of duties, if the domestic industry does not reduce its prices, the imports are likely to take over its market share. In such a situation, the production of the domestic industry would be completely wiped out, except to the extent of captive production of RIL. In such a situation, the domestic industry is likely to incur significant losses in the form of fixed costs.
- xxv. In the alternative, if the domestic industry reduces its prices, its profitability is likely to decline steeply.

R.2. Submissions by other interested parties

97. Following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:
- i. There is no likelihood of dumping and injury, and the anti-dumping duty has served its purpose as the performance of Domestic Industry has improved.
 - ii. The scale of pricing power being enjoyed by the domestic industry clearly shows that there is no likelihood of price suppression or depression in the event of expiry of present duties.
 - iii. There is no basis for the argument that imposition of duties by other countries on downstream products of subject countries would reduce the demand for PTA in subject countries, as the duties on downstream products of PTA against exports from India did not cause any decline in domestic demand thereof.
 - iv. The projected global demand for the subject goods is expected to increase by 15.53% in the next five years, with a commensurate increase in production by 15.58%. The capacity shall increase by 19%. 80-85% capacity utilization should be seen as a reasonably comfortable and prevalent rate of utilization in PTA. The Wood Mackenzie data shows highly balanced demand supply situation in the world.
 - v. The capacity and capacity utilization in the subject countries is expected to remain the same, with a slight increase in demand.
 - vi. Despite the capacity in subject countries being higher than the domestic demand, there is no demand and capacity imbalance as such and no idle capacity waiting to be activated if India removes anti-dumping duty on PTA.
 - vii. Decline in exports from Thailand are attributable to debottlenecking of one of the downstream units in Thailand and a new polyester plant consuming PTA.
 - viii. Excess capacity in subject countries is not true since imports into India in 2014 were in the range of 3 to 6 lakhs MT. Had there been 16.61 lakh MT excess capacities, the imports into India would have been much more.
 - ix. There was no spike in exports of PTA to India from subject countries when China imposed anti-dumping duty on imports of PTA from subject countries in the year 2010.
 - x. The claim that new capacities in EU will also impact the export of PTA from subject countries to EU which may lead to higher exports to India is also a mere allegation. The exporters in subject countries are operating at very high levels and there are not any imminent situation of loss of market as the overall world demand supply is well balanced and the producers of PTA across the globe are doing well.
 - xi. There is expected to be considerable growth in capacity, production and demand in India, and it would have 11% excess capacity in five years, which is higher than global average.

- xii. India has a stable market for PTA and there are many factors driving the demand. Indian Textile Market size which was US\$ 140 BN in 2015-16 is expected to reach US\$ 300 BN by 2024-25.
- xiii. Since the downstream industry in India is expected to grow significantly, it would necessitate imports, but the balanced demand supply gap shall ensure a fair price.
- xiv. There was no preference for the imported products per se if the product is available domestically and the price is right.
- xv. The users have stated that they are procuring from DI and shifting to any import source is not viable for the reasons therein such as poor infra associated with the import etc.
- xvi. The domestic industry commanded about ***% of the market, even when there were no duties in place. There were no scenarios of imports at dumped rate flooding the market and the imports were clearly necessitated and were proportionate to the demand supply gap in India. Had the users been focused on dumped prices as alleged, the domestic industry would not have maintained such a huge market share.
- xvii. There are no surplus capacities in the subject countries. Hanwha General Chemical is operating at its optimal capacity and has no immediate plans for capacity expansion.
- xviii. The concept of surplus capacities as capacity minus domestic demand as explained by petitioners is incorrect and baseless.
- xix. Citing some situation of imports allegedly at dumped prices historically have no basis and the time ahead will see only further reduction in the imports as the domestic demand supply is now pretty balanced.
- xx. There has been a further decline in imports post period of investigation.

R.3. Examination by the Authority

98. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The Authority notes as under.

a. Rate of increase in imports during the period of investigation

99. The Authority has undertaken analysis of the volume of imports of the subject goods into India from the subject countries over the injury period. It is observed that while imports declined up to 2016-17, the same increased during the period of investigation. While imports declined by 61% in 2015-16 and by 15% in 2016-17, the same increased by 74% in POI. The rate of increase in imports in POI is especially significant when compared to the rate of increase in demand and considering that ADD is in force.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Subject imports	MT	6,57,507	2,57,387	2,17,599	3,78,037
Change over previous year	%		(-) 61%	(-) 15%	74%
Demand (excluding captive)	MT	***	***	***	***
Change over previous year	%		9%	4%	9%

b. Surplus capacities in subject countries and ability of other export markets to absorb additional capacities

100. As part of questionnaire response, the Authority sought information from each exporter with regard to country's gross production, company's production, other producers' sales in domestic market, total sales in domestic market, imports in the country, total demand in the country, company's exports to India, company's export to countries other than India, other producers' exports to India, other producers exports to countries other than India. However, while the exporters from Thailand have not furnished any such information, the responding exporters from Korea have given contradictory figures, that too without quoting any source of data. The Authority has therefore relied upon other relevant information publicly available, and provided by the domestic industry, which was also disclosed to the interested parties for their counter comments.

101. With regard to surplus capacities in subject countries, the PCI Wood Mackenzie data for the year 2017 furnished by the domestic industry is as under –

Volumes in '000 MT

Particulars	Korea RP	Thailand	Subject Countries
Capacities of the producers	5,705	2,740	8,445
Domestic demand	2,619	1,262	3,881
Surplus capacities	3,086	1,478	4,564
Exports from subject countries	1,940	963	2,903
Idle capacities	1,146	515	1,661

Source – PCI Wood Mackenzie

102. The Authority notes that the exporters in the subject countries have 16.61 lakh MT of idle capacities.

c. Likely suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry

103. The Authority notes that the price undercutting is positive and is at low levels showing stiff competition in the market. The ROI of the domestic industry is low thus showing that the domestic industry has not been able to increase its prices to a level where it could earn reasonable return. These facts suggest that the imports are likely to have a suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry in the event of cessation of ADD.

d. Level of current margin

104. The Authority notes that dumping margin in the original investigation was positive and significant, which led to the imposition of duties. The dumping margin continues to be positive in the present review for imports from the subject countries.

e. Price attractiveness of Indian market

105. The Authority examined the price at which the goods were exported to India and rest of the world. The questionnaire response filed by the responding exporters were examined to ascertain the volume of their exports to rest of the world at a price below export price to India. On average basis considering customs data, it is seen that ***% or *** MT of the exports from Korea are made at prices below the price to India. In case of Thailand, ***% or *** MT of the third countries exports are priced below the price to India. Questionnaire response filed by the responding exporters with regard to volume of third countries exports at a price below exports to India is as under :

Particular	Taekwang	Hanwha	Total
Gross exports	***	***	***
Exports to India	***	***	***
Exports to third countries , at a price below export price to India	***	***	***
Exports at prices below price to India as a % of total exports to third countries	***	***	***
Exports at prices below price to India as a % of total exports to third countries (Range)	60-70%	65-75%	65-75%

106. It is seen that the responding exporters have significant exports to rest of the world at a price below export price to India, which are likely to be diverted to India in the event of cessation of ADD.

R.4. Conclusion on likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

107. It is noted that there is continued dumping of the subject goods. Further, dumping is likely to continue in the event of cessation of duty at enhanced volume and cause injury to the domestic industry. Even during the present period of investigation, the imports were undercutting the prices of the domestic industry and the return on capital employed earned by the domestic industry is low. In the event of cessation of duty, the imports are likely to further impact the prices and profitability of the domestic industry adversely. The foreign producers are holding significant surplus capacities. The volume of exports from subject countries to third countries at a price below export price to India is significant. Therefore, the Authority holds that there is likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of duty.

S. POST DISCLOSURE COMMENTS

108. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analyzed as under –

S.1. Submissions by the domestic industry

109. The domestic industry reiterated its submissions regarding rejection of response of HTC, injury to the domestic industry, likelihood of continuation of dumping and injury and high profitability of the user industry. In addition, the domestic industry submitted as under:
- i. Since Ministry of Finance may take upto three months to consider the recommendations of the Authority, the Authority may request for extension of duties for at least three months.
 - ii. The prices of the PET resin, PSF, PET film and filament yarn practically moved in tandem with the prices of PTA. The difficulties of the textile industry are linked to other factors such as surge in imports from China PR, low customs duty, inverted duty structure in GST, over capacities.
 - iii. The objections by the users to the duties is not on account of their own suffering, but in order to obtain an advantage for their Thai related producers.
 - iv. Since Taekwang, Hanwha and Sam Nam are de facto related entities, the normal value and export price cannot be determined without participation of all three entities. In any case, since Hanwha has supplied PX to Taekwang, the cost of production for the latter cannot be determined without any information regarding transfer pricing of PX between Hanwha and Taekwang. There is an arrangement between Hanwha, Sam Nam and Taekwang with regard to production and exports, which has not been disclosed to the Authority.
 - v. Taekwang has suffered loss in its PTA operations.
 - vi. Since Hanwha has captive raw material, the cost of production of Taekwang cannot be lower than that of Hanwha.
 - vii. In view of non-participation by M/s Posco Daewoo, export price may be determined considering adverse facts available.
 - viii. The responding producers have not admitted to the existence of post invoicing discounts, even though the importers have acknowledged the same.
 - ix. HTC has suppressed the fact that its related entity Hyosung Chemical Corporation has a plant for production of PTA in Korea RP.
 - x. IRSL is related to IRPL and TPT, as per the definition of the term “related” under Trade Notice 9/2018. Further, Indorama Ventures has acquired a stake of 31.79% in IRSL post period of investigation. Further, the other related importer, IDPIPL has not filed a complete response.
 - xi. The price undercutting is positive despite the fact that the domestic industry is selling its goods at prices below the non-injurious price and at prices that are not adequately remunerative
 - xii. The non-injurious price should be determined on the basis of cost of production for the period of investigation as per para (3) of Annexure – III.
 - xiii. Since the dumping margin, injury margin and causal link have been established for the period of investigation itself, there is no need to refer to post POI data.
 - xiv. Since Taekwang has exported significant volume at a higher dumping margin than that determined for India, there is a need for continuation of existing duties on Taekwang. For other exporters, there is a need for modification and enhancement of duty as dumping margin and injury margin have increased.

S.2. Submissions by other interested parties

110. In addition to reiterating their earlier submissions regarding improvement in the performance of domestic industry and lack of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the interested parties submitted as under:
- i. The goods produced by Taekwang are sold in three different types of packing. The packing cost considered for determination of export price is different from that claimed by Taekwang. Detailed workings of packing cost have not been provided.

- ii. The port and related expenses adjusted for are not as claimed by Taekwang and no working or reasons for rejection of claim have been provided.
- iii. As Taekwang has made most of the exports to India on FOB basis, ocean freight and insurance cannot be allocated on all transactions. No commission or warranty expenses have been paid in respect of exports to India. Bank charges have been provided on a transaction-wise basis.
- iv. The cost of production claimed by Taekwang has not been accepted. No information has been provided regarding factors that have been modified.
- v. The analysis of price attractiveness is not appropriate as average prices for the period of investigation have been compared to the transaction-wise exports, whereas the prices have fluctuated over the period.
- vi. Hanwha has provided month-wise cost of production. Since no analysis was undertaken by Authority regarding month-wise production, there was no opportunity to Hanwha to demonstrate significant variation in its normal value and export price. There is a variation of 14% between the highest and lower cost of production.
- vii. The Authority had undertaken month-wise analysis in the previous investigation as well.
- viii. The Authority has taken selling, general and administrative expenses for Hyosung Corporation as a whole, which is higher than that for the trading division, which was subsequently hived off as HTC. Since Hyosung Corporation is a multi-product company, total selling, general and administrative expenses cannot be considered. In the alternative, Authority may consider selling, general and administrative expenses of another producer of the subject country.
- ix. Applying selling, general and administrative expenses of an unrelated trader is not a reasonable basis in terms of Section 9A(b) and is not in conformity with the WTO jurisprudence and practices followed by other investigating authorities.
- x. IRPL and TPT have not filed Part – II of exporter's questionnaire as it is not prescribed under the trade notices and website of DGTR. No Part – II of the questionnaire is available on the website. Trade Notice 5/2018, which supersedes all previous instructions and trade notices on this issue does not prescribe Part – II.
- xi. IRPL and TPT had explained reasons for not filing Part – II in their post hearing submissions, which have not been considered.
- xii. The Authority has acted in contravention of Annexure – II of the WTO as it neither issued Part – II of the questionnaire, nor it pointed out that such information was missing. The Authority could not resort to facts available when they did not clearly request the relevant information from the party in question, in line with findings of Panel and Appellate Body.
- xiii. While the responses of IRPL and TPT have been rejected, the responses of Korean exporters have been accepted despite discrepancies and non-cooperation by one of the exporters. . Similarly, discrepancies were noted in the data of Taekwang, but the response has been accepted. Further, even the domestic industry had not filed Format H in the prescribed format, but no cognizance has been taken of the same.
- xiv. Since Part – II contains information regarding likelihood, the Authority could have used facts available for IRPL and TPT only with regard to likelihood analysis. Part – II is not relevant for determination of current dumping and injury.
- xv. The rejection of responses of IRPL and TPT is unjustified as no deficiencies were pointed out in the letter calling for records for the purpose of table study.
- xvi. There are a number of sunset reviews wherein the exporters have been allowed an individual dumping margin without filing any Part – II of the questionnaire. As the questionnaire is not available on the website, the Authority issues the same on a case-specific basis if it wants additional information regarding likelihood.
- xvii. The dumping margins determined for Thailand after rejecting responses are highly inflated and arbitrary.
- xviii. The imports have declined post POI, as evident from DGCI&S data submitted by the interested parties. However, the same has not been considered. The imports have declined in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- xix. There is nothing to show unfair price competition in the market, whereas the domestic industry wishes to prevent all imports.
- xx. It is not clear what has been considered as reasonable return by the Authority. The domestic industry of PTA in India is enjoying good margins.

- xxi. In the instant case there is no current injury as has been observed by the Authority. The fact that the performance of the domestic industry has tremendously improved, in spite of presence of dumped imports clearly shows that there is no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.
- xxii. Since anti-dumping investigation is to address unfair pricing behaviour, the Authority has the responsibility to see whether the domestic industry is abusing the provisions of the law to create a monopolistic situation in the domestic market.
- xxiii. The fact that landed price of imports is lower shows that domestic industry obtains a premium on its prices.
- xxiv. The observations of the Authority with regard to surplus capacities is flawed as historically the optimum capacity utilizations across the world have remained at the current level.
- xxv. The findings of the Authority that dumping and injury will continue is flawed as various Panels and Appellate Body decisions have held that the likelihood examination should be based on facts and not on some remote possibilities.
- xxvi. The Authority has not considered the submission of the interested parties that Format H submitted by the domestic industry is incomplete.
- xxvii. The users had quantified their concerns in their written submissions and submitted that PTA constituted 55-75% of the cost of production of PSF, FDY, POY and Polyester chips. The users had also submitted that domestic producers are charging additional premium over international PTA prices. Submissions made by the users have not been appropriately addressed.
- xxviii. The Authority has admitted the evidence provided by the domestic industry that the downstream users are expanding. However, such evidence has not been made part of Disclosure Statement.
- xxix. The evidence adduced by the respondents showing demand and supply over the next five years has not been considered, and instead, data for 2017 has been relied upon.
- xxx. The imports were very negligible and were to the extent of scarcity of material in the market is not addressed by the Authority at all.

S.3. Examination by the Authority

- 111. As regards the submissions of the domestic industry with regard to responses filed by Taekwang and HTC, it is noted that the Authority has considered and accepted the responses of the parties after due examination and verification of all information.
- 112. As regards the argument that HTC was not in existence during the period of investigation, the Authority notes that the selling, general and administrative expenses of Hyosung Corporation have been considered for determination of export price after due verification.
- 113. With regard to the claim that non-injurious price has not been appropriately determined, it is noted that the Authority has determined the non-injurious price in accordance with the guidelines prescribed under Annexure – III to the Anti-Dumping Rules.
- 114. Taekwang reported that only one form of packing was used in sale of PUC in the domestic market, whereas the material was exported in three different forms of packing. Further, the exporter did not reconcile total packing expenses incurred and reported in the books with the expenses incurred separately in respect of exports to India and exports to third countries in respect of different forms of packing. The exporter has thus not adequately and sufficiently identified in its books of accounts packing expense for different forms of packing and for different markets. It was therefore not possible for the Authority to co-relate different forms of packing, for different markets and for different shipments. Under the circumstances, the Authority has considered total packing expenses reported by the company in its books of accounts and total volume of material packed and sold. The packing cost has been determined on the basis of average packing cost incurred by the company.
- 115. As regards price adjustments on account of port and related expenses, the Authority notes that the exporter has reported selling and distribution expenses in Appendices 5, 7, 8 and 9. However, it is seen that these expenses are not duly reconciled with each other. Thus, the exporter has not precisely identified these expenses incurred for a particular market and has not correlated the same to the books of accounts. Under the circumstances, Authority holds it appropriate to adopt all expenses incurred by the company on this account and apportion the same on total exports made. It is also noted that there is no explanation given by the exporter why expenses on this account would be different depending on market. The exporter has not explained why expenses up to the FOB stage would also be different in respect of exports made to different countries.
- 116. The ocean freight and insurance expenses have been adjusted on actual basis, as claimed by the Taekwang.

117. While Taekwang has stated that no commission has been paid by the exporter, the domestic industry has reported that Mr. Rohit Dutta M/s. Chemsynth, 25-A, Pocket-F, Mayur Vihar Phase 2 Delhi – 110 091 is an agent working for the company and assisting the company in sales of the product. . However, the Authority cannot take cognizance of the claim made by the domestic industry at this belated stage.
118. As regards rejection of cost of production, the Authority has accepted all claims made by the company with regard to manufacturing cost. The only difference is in respect of selling and distribution cost claimed by the exporter.
119. As regards price attractiveness, the Authority has considered exporter's own data and has compared its export price to India with export price to rest of the world. Further, in those situations where export price to rest of the world is lower than export price to India, it has not been demonstrated by exporters/foreign producers why those shipments would not be diverted to Indian markets in the event of cessation of duty.
120. As regards the contention that Hanwha has provided details of month wise cost of production and that there is a variation in the same thus justifying monthly comparison, the Authority notes that the need for such an analysis in this investigation could not be established by interested parties.
121. As regards Hanwha's argument concerning general and administrative expenses, and the contention that the same includes expenses for manufacturing and trading activity, the Authority notes that by its very nature, manufacturing expenses are included in the the cost of goods manufactured. Selling, general and administrative expenses by their very nature are not limited to either manufacturing or trading. It is therefore appropriate to apportion these expenses based on overall turnover of the company. It is also noted that even if the selling, general and administrative expenses are considered as claimed by the exporter, the dumping margin remains higher than the dumping margin determined in the original investigation. .
122. As regards inclusion of unrelated trading company's selling, general and administrative expenses, it is noted that since the trader is selling at a loss, it is appropriate to make adjustments of this loss at the ex-factory export price of the producer or to make deduction of SGA from the export price at which trader sells the subject goods.
123. The contention of IRPL and TPT that they have not filed Part – II of the Exporter's Questionnaire as it is not prescribed under Trade Notice 5/2018, which supersedes all previous instructions with regard to the information to be provided by producer/exporters is incorrect because (a) other exporters have filed the same, (b) the domestic industry had raised this issue during the oral hearing and (c) the letter issued by the Authority to all the known exporters, including these exporters, clearly stated this requirement and a web link of the same was also provided. The exporter has stated that even though the web link was provided in the letter issued by the Authority, the same was not opening and the parties went by the Trade Notice as above. The authority notes that in that case the exporter should have approached the Directorate for necessary clarification instead of presuming that the information relating to part –II of the Exporters questionnaire was not necessary. It is further noted that link was opened in presence of the legal representative of the exporter when he sought meeting post-issuance of disclosure. It is also noted by the authority that specific communication to the exporter seeking part II of exporter's questionnaire should in any case prevail.
124. As regards the contention that supplementary questionnaire or deficiency letter could have been issued, it is noted that the question for issue of deficiency letter arises only in when a party has filed response to questionnaire in the form and manner prescribed. However, in a situation where a party has not filed response to questionnaire itself, the question of raising deficiencies should not arise. It is further noted that reference to the past investigations and determinations in this regard is inappropriate.
125. As regards acceptance of questionnaire response of other Korean producers, it is clarified that the Korean producers have provided complete details of their exports to third countries.
126. IRPL and TPT have also submitted that the relevant Trade notice or the website of DGTR did not prescribe any additional annexure to be submitted in a sunset review investigation as part-II of the questionnaire and that even today no such questionnaire is available on the website of the DGTR. This matter was examined by the Authority and it was found that while updating the website the part-II of questionnaire was inadvertently deleted from the website of the Directorate subsequently. While this explanation does not justify non-filing of the response by the exporter, considering the practical difficulty expressed by the exporter, the authority considers it appropriate to examine the questionnaire response and submissions of the Thai exporters. However, the authority further notes that these exporters however have themselves conceded in their post disclosure comment that the Authority could apply adverse facts available against them with regard to likelihood analysis. It is also noted that while disputing the disclosure statement, the exporter has not even shown absence of likelihood of dumping. On the contrary, it is seen that the dumping margins admitted by both these Thailand exporters are significantly beyond de-minimis limits (***% i.e. USD *** per MT in case of IRPL and ***% i.e., *** USD per MT in case of TPT). The Authority accordingly concludes that the dumping from these Thai exporters continue and the revocation of anti-dumping duty will cause injury to the domestic industry
127. As regards injury information provided by the domestic industry, it is clarified that the domestic industry has

- provided all relevant information required by the authority. In fact, disclosure statement contains elaborate analysis of the same.
128. As regards the dumping margin determined in case of Thailand, it is clarified that the authority has determined normal value on the basis of best estimates of cost of production, after addition for SGA and reasonable profits. In any case, as stated above, the response filed by the Thai exporters itself shows a dumping margin of ***% and ***% in respect of their exports to India.
 129. As regards decline in imports in post POI period, it is noted that imports in post POI period from subject countries have on the contrary increased from 378,037 MT in the period of investigation to 408,862 MT (annualized) in the six months from April to September, 2018.
 130. While contending that the price undercutting has remained at similar level historically and globally, the interested parties have not shown on the basis of their own capacity, production, sales, price and cost data that dumping and consequent injury is unlikely in the event of cessation of duty.
 131. With regard to the contention that likelihood determination cannot be based on remote possibilities, the Authority notes that the interested parties have not provided any evidence to substantiate how the evidence provided by them shows absence of likelihood of dumping and injury.
 132. It is noted that all relevant injury information, as called for in Format H, with regard to present investigation and concerning injury to the domestic industry is on record of the authority.
 133. As regards the contention concerning share of PTA in gross cost of production of downstream product, the Authority notes that the respondents have only provided estimated share of PTA in the cost of production and not the impact of duty in their cost. Further, these consumers in fact have preferred not to file information in the form and manner prescribed in the importers' questionnaire response, as noted hereinabove. The importer's questionnaire in particular requires the importers to provide relevant information such as utilization of the product and profitability of the users. It is however noted that said information has been withheld by these interested parties by not furnishing any relevant annexure. At the same time, the information provided by the domestic industry shows that the impact of present anti-dumping duty on the eventual downstream product shall be in the range of 0.21% to 1.53%.
 134. As regards the information concerning demand and supply situation over next five years, the Authority notes that the injury period in the present case is upto 31st March, 2018. Further, the interested parties have not established absence of likelihood on the basis of this prospective information.
 135. The volume of imports in the period of investigation was not negligible, as contended. In fact, the rules specifically prescribe that a volume of import beyond 3% shall be considered significant, in the context of original investigations. In any case, in the present period, imports from subject countries constituted about 10% of the merchant demand in India. Since the purpose of present investigation is to determine likelihood of dumping and injury, the interested parties were required to establish that the dumping and injury is unlikely in the event of cessation of duty. While the questionnaire response filed by two exporters showing their third country export clearly shows a likelihood of continuation of dumping, the Thai producers have admitted that the Authority could apply facts available in this regard. The participating consumers have provided no information or evidence to show that dumping and consequent injury to the domestic industry is unlikely in the event of cessation of duty.
 136. As regards the contention that the domestic industry wishes to prevent all imports, the authority notes that 13% of the merchant demand in the country during POI was still met by imports.
 137. It is clarified that the Authority has considered 22% return on capital employed for the purpose of non-injurious price determination, as per consistent practice. Further, it is also noted that the actual return earned by the domestic industry is far lower.
 138. The contention that there is absence of current injury and therefore there is no likelihood of recurrence of injury, is contrary to the express legal provisions. It is noted that the question of likelihood of recurrence of injury arises only when there is no continued injury. However, in the present case, the Authority has noted that the performance of the domestic industry has remained sub-optimal with regard to profits, and ROCE.
 139. As regards the contention regarding abusing the provisions of law or creating monopolistic situation, it is noted that examination of this issue does not fall within the scope of the trade remedy investigation. Moreover, except for making statements, none of the interested parties have furnished any evidence whatsoever. Further, it is noted that there are three producers of the product in the country and therefore it cannot be said that the domestic industry is in a monopolistic position.
 140. The Authority notes that the fact that import price is lower than the selling price of the domestic industry shows existence of positive price undercutting.

T. CONCLUSION

141. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of recurrence of dumping and consequent injury, the Authority concludes that:

- a. There is continued dumping of the subject goods and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
- b. The parameters such as significant dumping margin, injury margin, significant volume of imports, positive price undercutting, price attractiveness of the Indian market, low return on investment earned by the domestic industry and surplus capacities of the exporters, collectively and cumulatively shows that injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of duty. The situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti-dumping duties are allowed to cease.
- c. The deterioration in the performance of the domestic industry is likely because of dumped imports from the subject country. Thus, the anti-dumping duties are required to be extended.
- d. The domestic industry has itself sought continued imposition of duty. The authority therefore concludes that it is appropriate to continue the same level of anti-dumping duty as imposed earlier in the original investigation.

U. RECOMMENDATIONS

142. Having examined the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of expiry of the current measure in place, and in view of the foregoing conclusions, the Authority recommends continued imposition of Anti-Dumping Duty as indicated in column (8) of the table below for a period of five (5) years concerning all imports of the subject good originating in or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29173600	Purified Terephthalic Acid	Korea RP	Korea RP	Hanwha General Chemical Co., Ltd.	Hyosung TNC Corporation	27.32	MT	USD
2	29173600	Purified Terephthalic Acid	Korea RP	Korea RP	Taekwang Industrial Co., Ltd.	Taekwang Industrial Co., Ltd.	23.61	MT	USD
3	29173600	Purified Terephthalic Acid	Korea RP	Korea RP	Any combination other than mentioned in S. No. 1 & 2 above.		78.28	MT	USD
4	29173600	Purified Terephthalic Acid	Korea RP	Any country	Any	Any	78.28	MT	USD
	29173600	Purified Terephthalic Acid	Any country other than those subject to anti-dumping	Korea RP	Any	Any	78.28	MT	USD

			duty.						
	29173600	Purified Terephthalic Acid	Thailand	Thailand	Indorama Petrochem Ltd.	Indorama Petrochem Ltd.	45.43	MT	USD
	29173600	Purified Terephthalic Acid	Thailand	Thailand	TPT Petrochemicals Public Co. Ltd.	TPT Petrochemicals Public Co. Ltd.	45.43	MT	USD
	29173600	Purified Terephthalic Acid	Thailand	Thailand	Any combination other than mentioned in S. No. 6 & 7 above.		62.55	MT	USD
9.	29173600	Purified Terephthalic Acid	Thailand	Any country	Any	Any	62.55	MT	USD
10.	29173600	Purified Terephthalic Acid	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Thailand	Any	Any	62.55	MT	USD

V. FURTHER PROCEDURE

147. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SUNIL KUMAR, Additional Secy. and Director General